



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 19, 1990/वैशाख 29, 1912

No. 20]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 1990/VAISAKHA 29, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम,
(जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं) ।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general
Character) issued by the Ministries of the Government of India (other
than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other
than the Administration of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1990

सा. का. नि. 296.—राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद् के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय औद्योगिक
सुरक्षा बल (अनुसन्धानीय अराजकपन्नि समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1974 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (अनुसन्धानीय अराजकपन्नि समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990
है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (अनुसचिवीय अराजपत्रित समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1974 को अनुसूची में आशुलिपिक के पद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थापन पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चरन पद अथवा अचरन पद	सोघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों की फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
-----------	----------------	----------	---------	---------------------	---	--

1	2	3	4	5	6	6क
आशुलिपिक श्रेणी-II	9* (1989)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित अनुसचिवीय,	1400-40-1600-50-2300 द.रो.-60 1600 रु.	अचरन	लागू नहीं होगा।	लागू नहीं होता
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।						

सोघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सोघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य

भर्ती की पद्धति : भर्ती सोघे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरो जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
10	11

प्रोन्नति द्वारा जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा

प्रोन्नति:—

1200-2040 रु. के वेतनमान में ऐसा आशुलिपिक (कनिष्ठ) जिनसे उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :—

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या

(ii) जिन्होंने 1200-2040 रु. के वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

(ख) जिनकी आशुलिपि (अंग्रेजी/हिंदी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति है।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उनी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले पारित किसी अन्य काठोर बड़य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जायेगा।

13

14

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. उच्च महानिरीक्षक (कार्मिक), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल—सदस्य
2. अन्य उच्च महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मुख्यालय—सदस्य
3. सहायक महानिरीक्षक (कार्मिक/स्थापना), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मुख्यालय—सदस्य

टिप्पणः—मूल नियम अधिसूचना सं. 1181 सो आई एस एफ/रजिन/72/(कार्मिक-1), तारीख 10-7-1974 (सा. का. नि. 783, द्वारा प्रकाशित किए गए थे, उनका पश्चात्-वर्ती संशोधन सं. ई 3012/4/77—एल एण्ड आर. (सी आई एस एफ) (कार्मिक-1) तारीख 14-12-1982 (सा. का. नि. 49) द्वारा किया गया है।

[सं. ई-32012/3/88—एल एण्ड आर/सी. आई. एस. एफ. कार्मिक I],
रा. शंकर नारायणन, अवसर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 19th April, 1990

G.S.R. 296.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Industrial Security Force (Ministerial Non-Gazetted Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1974 namely:—

1. (i) These rules may be called the Central Industrial Security Force (Ministerial Non-Gazetted Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1990.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Industrial Security Force (Ministerial Non-Gazetted Group 'B' Posts) Recruitment 1974, for the post of Stenographer and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10
Stenographer Grd.II	9* (1989)	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600.	Non Selection						
*Subject to variation dependent on workload.										
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil	By promotion failing which by transfer on deputation					
11			12		13					
Promotion: Stenographer (Junior) in the scale of Rs. 1200-2040 with 5 years regular service in the grade.		Group 'B' Departmental Promotion Committee								
Transfer on deputation: Officers of the Central Government—		1. Deputy Inspector General (Personnel)/ Central Industrial Security Force—		Consultation with the U.P.S.C. not necessary.						
(a)(i) holding analogous posts on regular basis: or		—Chairman.								
(ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 1200—2040/-		2. Another Deputy Inspector General/ Assistant Inspector General, Central Industrial Security Force at Headquarters—								
(b) Possessing a speed of 100 words per minute in Stenography (English/Hindi) (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).		—Member								
		3. Assistant Inspector General (Personnel/ Establishment)/Central Industrial Security Force Headquarters—Member								

NOTE : The Principal rules published vide notification No. 1/8/CISF/Regn/72 (Pers. I) dated 10-7-1974 (G.S.R. 783) had been subsequently amended vide notification No. E-32012/4/77-L&R/CISF/Pers. I dated 14-12-1982 (G.S.R. 49.)

[No. E. 32012/3/88-L&R/CISF-Pers. I]
R, SANKARANARAYANAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1990

सा. का. नि. 297:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय में ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (गैर-योधक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय समूह “क” (ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) गैर योधक भर्ती नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि:— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवश एसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू रवोंय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े हुए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1* (1990) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह “क” राजपत्रित, अनुसूचिवीय	3000-100-3500-125-4500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं						
				सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परिवर्षा की अवधि यदि कोई हो विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों का दशा में लागू होगी या नहीं		
				8.	9	10
लागू नहीं होता				लागू नहीं होता		
				प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष		

भर्ती को पद्धति: भर्ती सोचे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की वृद्धा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।

11

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा

12

प्रोन्नति: सीमा सुरक्षा बल के ऐसे प्रशासनिक अधिकारी अनुभाग अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष अनुभूति सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जिनके अन्तर्गत सीमा सुरक्षाबल में अधिकारी भी हैं।

(क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(2) जिन्होंने 2200—4000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है, या

(3) जिन्होंने 2000—3500 रु. वेतनमान वाले पद पर 8 वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास प्रशासन, लेखा और स्थापन विषयों का पांच वर्ष का अनुभव है। पोषाक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीमा पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति किए गए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

13

14

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. अध्यक्ष सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
2. महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल (महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा) —सदस्य
3. उप सचिव (केन्द्रीय पुलिस संगठन), गृह मंत्रालय—सदस्य
4. उप निदेशक (कार्मिक) सीमा सुरक्षा बल—सदस्य

[सं. 12011/1/87-स्टाफ/सी सु बल/कार्मिक-II]

एम. के. अग्रवाल, उप सचिव

New Delhi, the 30th April, 1990

G.S.R. 297.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Administrative Officer (Non-Combatised) in the Border Security Force Headquarters, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Border Security Force Headquarters, Group 'A' (Senior Administrative Officer) (Non-Combatised) Recruitment Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or or non-selection post.
1	2	3	4	5
Senior Administrative Officer	1* (1990) *Subject to variation dependent on workload. Ministerial.	General Central Service, Group 'A', Gazetted,	Rs. 3000-100-3500-125-4500	Selection
Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	
6	7	8	9	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	
Period of probation, if any.	Method of rectt. Whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which U.P. S.C. is to be consulted in making rectt.
10	11	12	13	14
2 years for promotees.	By promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion Administrative Officer/ Section Officer of Border Security Force who have rendered 8 years approved service in the grade. Transfer on deputation Officers of the Central	Group 'A' Departmental Promotion Committee (For promotion) 1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman 2. Inspector General Border Security Force Headquarters/	Consultation with the U.P. S.C. is necessary on each occasion.

10

11

12

13

14

Government including Officers of Border Security Force:

- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or
(ii) With 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 2200-4000/- or equivalent; or

- (iii) With 8 years regular service in post in the scale of Rs. 2000-3500/- and

- (b) having five years' experience of administration, accounts and establishment matters. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 4 years).

(To be nominated by Director General)—Member.

3. Deputy Secretary (Central Police Organisation), Ministry of Home Affairs—Member.
4. Deputy Director (Personel), Border Security Force—Member

[No. 12011/1/87-Staff/BSF/Pers-II]

M.K. AGARWAL, Dy. Secy.

कार्मिक, लोक शिक्षा तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1990

सा. का. नि. 298:— राष्ट्रपति, विधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्मिक, और प्रशासनिक सुधार विभाग, मंत्रिमण्डल सचिवालय अनुसंधान अधिकारी (वर्ग-1) भर्ती नियम, 1973 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है कार्मिक, लोक शिक्षा और पेंशन मंत्रालय में अनुसंधान अधिकारी समूह "क" के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिक्षा और पेंशन मंत्रालय अनुसंधान अधिकारी समूह "क" भर्ती नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 3 में स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि उक्त पर पद भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निर्हता वह व्यक्ति.--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसको पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रिय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विवाह के अधीन अन्वेष्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समर्पित है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रिय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	साधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रिय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
अनुसंधान अधिकारी समूह "क"	4 * (1990) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रिय सेवाएं समूह "क" राजपत्रित	2200-75-2800- द. रो.-100-4000रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
<p>साधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परिवर्द्धता की अवधि यदि कोई हो अर्हताएं विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों को दशा में लागू होंगी या नहीं</p>						
8			9		10	
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		प्रोन्नत अधिकारियों के लिए 2 वर्ष	

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होमी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती को दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

11

- (i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा है) द्वारा।
- (ii) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा है) द्वारा।

12

प्रोन्नति :

ऐसे अनुसंधान अधिकारी समूह "ख" जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :

(जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा है) :

केन्द्रीय सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/केन्द्रीय सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों/अनुसंधान/संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो नियमित आधार पर मद्रास पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने 2000-3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं :-- आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/सांख्यिकी गणित/लोक प्रशासन/कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

(ii) कामिक प्रशासन या आर्थिक और सांख्यिकीय आंकड़ों के अन्वेषण और निर्वचन या कामिक और प्रशासन में योजना और अनुसंधान या कार्य विश्लेषण या कार्य मूल्यांकन या प्रशिक्षण पद्धति और तकनीकी में चार वर्ष का अनुभव।

वाछनीय :

(i) कम्प्यूटर कार्यक्रम का ज्ञान;

(ii) निर्जा कम्प्यूटर पर विस्तारित/उन्नत प्रौद्योगिकी से कार्य करने का अनुभव और एम एम डी ओ एस/यूनिक्स प्रचालन पद्धति से सुपरिचित हो;

(iii) डी वेस iii प्लस, लोटस या समरूप पैकेजों का ज्ञान। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति को संघ पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उन्ही प्रकार प्रतिनियुक्ति किए गए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार दिए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/विदा को अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काउंटर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, हैं, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होंगे।)

अल्पकालिक संविदा पर नियुक्ति के लिए आयु साधारणतया 55 वर्ष से अधिक नहीं होंगे तथापि, यदि 55 वर्ष से अधिक की आयु वाले किसी व्यक्ति का चयन कर लिया जाता है, तो संविदा की अवधि उस सीमा तक कम की जाएगी ताकि संविदा की अवधि व्यक्ति की 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पूरी हो जाए।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसको संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति

14

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. सदस्य अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग--अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) --सदस्य
3. संबंध प्रभाग का निदेशक/उप सचिव--सदस्य

[संख्या ए-12018/2/86-प्रशासन (I)]

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS**

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 26th April, 1990.

G.S.R. 298.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the Article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Personnel and Administrative Reforms, Cabinet Secretariat Research Officer (Class-I) Recruitment Rules, 1973, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer Group 'A' in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Research Officer, Group 'A' Recruitment Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age

limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.
1	2	3	4	5
Research Officer Group 'A'	4* (1990)	General Central Service Group 'A', Gazetted	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000	Selection
*Subject to variation dependent on workload.				
Age limit for direct recruits	Whether the benefit of added years of service is admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972		Educational and other qualifications required for direct recruits	
6	7		8	
Not applicable	Not applicable		Not applicable	
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any		Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	
9	10		11	
Not Applicable	2 years for promotee Officers		(i) 50% by Promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract) (ii) 50% by transfer on deputation (including short-term contract)	

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
12	13	14
<p>Promotion :</p> <p>Research Officer Group 'B' with 3 years' regular service in the grade</p> <p>Transfer on deputation (including short-term contract)</p> <p>Officers under the Central Government/Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies under the Central Government/Research Institutions:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or</p> <p>(ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and</p> <p>(b) possessing the following qualifications and experience:</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Master's Degree in Economics/Statistic/Mathematics/Public Administration/Business Administration from a recognised university or equivalent.</p> <p>(ii) 4 years' experience in personnel administration or investigation and interpretation of economic and statistical data or planning and research in personnel and administration or job analysis or job evaluation or training methods and techniques.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Knowledge of Computer programming:</p> <p>(ii) Experience of working on PC XT/AT with familiarity with MS-DOS/UNIX operating systems;</p> <p>(iii) Knowledge of D Base III plus or Lotus or similar package.</p> <p>(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation/contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).</p> <p>The age for appointment on short term contract shall ordinarily not exceed 55 years. However, if a person above 45 years of the age is selected, the period of contract would be reduced to such an extent which would ensure the completion of the contract when the person attains the age of 58 years.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Member/Chairman U.P.S.C.—Chairman 2. Joint Secretary (Administration)—Member 3. Director/Deputy Secretary concerned Division—Member 	<p>Consultation with the U.P.S.C. necessary on each occasion.</p>

सा. का. नि. . 299.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) भर्ती नियम, 1983 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करने हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, भर्ती नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनामन:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समोचन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपाबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सोधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी	6* (1990) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह, 'क' राजपत्रित	3000-100-3500- 125-4500 ₹.	चयन	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परीक्षा को अवधि, यदि कोई हो।
अर्हताएं। विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।

8

9

10

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

प्रोन्नत अधिकारियों के लिए 2 वर्ष।

भर्ती को पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरो जने वाले रिक्तियों को प्रतिशतता।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती को दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।

11

12

(i) 33-1/3% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा है)।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए:--

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनर्नियोजन।

(ii) 66-2/3% प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा

(जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा है)।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए:--

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनर्नियोजन

प्रोन्नति:--ऐसे अनुसंधान अधिकारी समूह "क" जिन्होंने इस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है, जिसमें न हो सकने पर ऐसे अनुसंधान अधिकारी समूह "क" जिन्होंने अनुसंधान अधिकारी समूह "क" (2200--4000 रु.) और अनुसंधान अधिकारी समूह "ख" (2000--3500 रु.) को श्रेणियों में कुल मिलाकर 8 वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा है:-- केन्द्र/राज्य सरकारों/पब्लिक सेक्टर उद्योगों/विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं/स्वायत्त/कानूनी निकायों आदि के ऐसे अधिकारी:--

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 2200--4000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने 2000--3500 रु. या समतुल्य वेतनमान में 8 वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:--

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/लोक प्रशासन/कारबार प्रबंध/कार्मिक प्रबंध में मास्टर डिग्री या समतुल्य; और

(ii) प्रशिक्षण पद्धति और तकनीक/वृत्ति प्रबंध/कार्मिक नीति योजना का अनुभव।

वांछनीय अनुभव:--

(i) कम्प्यूटर कोर्सेस/प्रशिक्षण का ज्ञान।

(ii) पी सी एक्स टो/ए टो के कार्यकरण का अनुभव और एम एस-डॉ और एस/यूनिक्स प्रचालन पद्धति की जानकारी;

(iii) डी बेस III प्लस, लोटस का बेस हों पैकेजों का ज्ञान;

(iv) तंत्र विश्लेषण और डिजाइन का अनुभव;

(v) मेनफ्रेम कम्प्यूटरों के कार्यकरण का अनुभव।

(पोषक प्रवर्गों के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा को अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्र/राज्य सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धरित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण:--अल्पकालिक संविदा पर नियुक्ति के लिए आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। किंतु यदि 55 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति का चयन कर लिया जाता है तो संविदा को अवधि को संविदा की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उस सीमा तक कम कर दिया जाएगा जब वह व्यक्ति 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए:—

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनर्नियोजन ।

प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के लिए ऊपर विहित सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अनुभव और अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधन पर रखा जाएगा जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

(सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन) ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति
(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/संविदा और पुनर्नियोजन के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (संबन्धित)—सदस्य
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन का भारसाधक), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग—सदस्य

[संख्या ए-12018/2/88-प्रशा.(I)]

ए. एन. साहनी, अवसर सचिव

G.S.R. 299.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Senior Research Officer (Department of Personnel and Administrative Reforms) Recruitment Rules, 1983 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Research Officer in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Senior Research Officer, Recruitment Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non Selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Research Officer	6* (1990) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted	Rs. 3000-100-3500-125-4500	Selection	Not applicable
Whether benefit of added years of service is admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972		Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications required for direct recruits will apply in case of promotees	
7		8		9	
No		Not applicable		Not applicable	
Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentages of the vacancies to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made		
10	11		12		
2 years for promotee Officers	(i) 33-1/3 % by promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract) For Ex-servicemen : Transfer on deputation/Re-employment. (ii) 66-2/3 % by transfer on deputation including short-term contract. For Ex-servicemen : Transfer on deputation/re-employment		Promotion : Research Officer Group 'A' with 5 years' regular service in the grade failing which Research Officers Group 'A' with combined regular service of 8 years in the grades of Research Officer Group 'A' (Rs. 2200-4000) and Research Officer Grop 'B' (Rs. 2000-3500). Transfer on deputation (including short-term contract) : Officers of Central/State Governments/Public Sector Undertakings/Universities/Research Institutions/Autonomous/Statutory bodies etc :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or (iii) with 8 years regular service in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and		

(b) possessing the following essential educational qualifications and experience :—

(i) Master's Degree in Economics/Statistics/Public Administration/Business Management Personnel Management from a recognised University or equivalent; and

(ii) Experience in Training Methods and Techniques/Career Management/Personnel Policy Planning.

Desirable experience :

(i) Knowledge of Computer programming;

(ii) Experience of working on PC XT/AT and familiarity with MS-DOS/UNIX operating system;

(iii) Knowledge of D Base III plus, Lotus or similar packages;

(iv) Experience in System Analysis and Design;

(v) Experience of working on mainframe Computers.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation/contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.

Note : The age for appointment on short term contract shall not exceed 55 years. However, if a person above 55 years of age is selected, the period of contract would be reduced to such an extent which would ensure the completion of the contract when the person attains the age of 58 years.

For Ex-servicemen :

Transfer on deputation/re-employment

The Armed Forces Personnel who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one years and having the qualifications and experience prescribed for deputationists as above shall also be considered. Such Officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed forces and thereafter they may be continued on re-employment.

(Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Group 'A' Departmental Promotion Committee
(for considering promotion)

Consultation with the Commission necessary for
transfer on deputation/contract and re-employment.

1. Chairman/Member, Union Public Service Commission
—Chairman
2. Additional Secretary/Joint Secretary (concerned)—Member
3. Joint Secretary (Incharge of Administration), Department
of Personnel and Training—Member

[No. A-12018/2/88-Ad. (I)]

A.N. SAWHNEY, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1990

सा. का. नि. 300 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (लेखाकार) भर्ती नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (लेखाकार) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (लेखाकार) भर्ती नियम, 1986 की अनुसूची के स्तंभ 11 में,—

(क) मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ख) 33 1/3% निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिसके तहत होने पर सीबी भर्ती द्वारा :—

- (1) ऐसे स्नातक समूह 'ब' पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, लेखाकारों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर,
- (2) ऐसे मैट्रिक पास लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष निरंतर नियमित सेवा की है, लेखाकारों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, और
- (3) ऐसे लिपिक जिन्होंने अनुभाग अधिकारी श्रेणी परीक्षा भाग 1 उत्तीर्ण कर ली है।
(उन व्यक्तियों का पारस्परिक बरीयता क्रम जो अर्हता प्राप्त करते हैं, उनकी पारस्परिक जेष्ठता के क्रम के अनुसार होगा। जो प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं सामूहिक रूप से पंक्ति में उनसे पहले होंगे जो बाद में परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं। समूह "ब" पदधारी लिपिकों से पंक्ति में नीचे होंगे।)"

(ख) टिप्पण में :—

- (1) परा 2 में "प्रतिनियुक्ति की अवधि" शब्दों से आरंभ और "तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी" शब्दों से समाप्त होने वाले

1228 GI/90—3.

कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति किए गए व्यक्ति प्राप्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उमों या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले जारित किसी अन्य कांडर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (2) पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापन किया जाएगा, अर्थात् :—

"यदि उपरोक्त मद (क) के अधीन किसी अधिकारी पर जेष्ठता के आधार पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है तो उससे जेष्ठ सभी व्यक्तियों पर भी, इस बात के होते हुए भी कि उन्होंने लिपिक के रूप में अपेक्षित वर्षों तक सेवा न की हो विचार किया जाना चाहिए (यदि उन्होंने, जहां परीक्षा लागू है, वहां सफलतापूर्वक परीक्षा पूरी कर ली)।

4. संपूर्ण विभाग के लिए बूँकि लेखाकारों के कांडर और पोषक कांडर केन्द्रीकृत नहीं किए गए हैं, विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में ये नियम प्रत्येक कांडर की लागू होंगे। उपरोक्त मद (क) और (ख) के अधीन विहित सेवा के अपेक्षित वर्ष संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में सुसंगत पोषक कांडर में आने चाहिए।

[फा. सं. ए-12018/6/89-ई. जी. I]

टिप्पण :—

- (1) मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3(i) तारीख 30-8-1986 के पृ. 3383—3386 में सा. का. नि. 673 तारीख 22-8-1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

- (2) मूल नियमों का संशोधन अधिसूचना सा. का. नि. सं. 612 तारीख 14-7-1988 द्वारा किया जो भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3(i) तारीख 30-7-1988 के पृ. 2309—2312 पर प्रकाशित हुए थे।

- (3) शुद्धित तारीख 5-9-1988 सा. का. नि. 740 के रूप में भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i) तारीख 17-9-1988 के पृ. 2785 पर प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 10th April, 1990

G.S.R. 300.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India hereby makes the following rules further to amend the Indian Audit and Accounts Department (Accountant) Recruitment Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Accountant) Recruitment (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Audit and Accounts Department (Accountant) Recruitment Rules, 1986, in column 11,—

(a) for item (b), the following shall be substituted, namely :—

“(b) 33-1/3 per cent by promotion from the following officials failing which by direct recruitment :—

(i) Graduate Group ‘D’ officials with three years continuous regular service in the grade on passing the departmental Examination for Accountants ;

(ii) Matriculate clerks with three years continuous regular service in the grade on passing the Departmental Examination for Accountants ; and

(iii) Clerks on passing Part I of the Section Officer's Grade Examination.

(The inter-se ranking of those who so qualify will be in the order of their inter-se seniority, those qualifying in any earlier examination ranking en-bloc higher than those who qualify in a later examination; Group ‘D’ officials will rank below clerks.”);

(b) in Note,—

(i) in paragraph 2, for the brackets and the words beginning with “The period of deputation” and ending with “not exceed three years”, the following shall be substituted, namely :—

“(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).”;

(ii) after paragraph 2, the following shall be inserted, namely :—

“3. If an officer is considered for promotion on seniority basis under item (a) above, all persons senior to him/her should also be considered (if they have successfully completed the probation where probation is applicable) notwithstanding that they may not have rendered the requisite number of years of service as clerk.

4. As the cadre of Accountants and the feeder cadre are not centralised for the whole department, the rules are applicable to each cadre in the various field offices of the Department. The requisite years of service prescribed under item

(a) and (b) above should be in the relevant feeder cadre in the field offices concerned.”

[F. No. A-12018/6/89-E.G.-I]

NOTE :—

(i) The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated 30-8-1986 at pages 2383—2386 vide GSR 673 dated 22-8-1986.

(ii) The principal rules were amended by notification GSR No. 612 dated 14-7-1988, published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated 30-7-1988 at pages 2308—2312 vide GSR 612 dated 14-7-1988.

(iii) Corrigendum dated 5-9-1988 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated 17-9-88 at page 2785 vide GSR 730.

सा. का. नि. 301.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (लेखा परीक्षक) भर्ती नियम, 1988 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (लेखा परीक्षक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (लेखा परीक्षक) भर्ती नियम 1988 की अनुसूची के स्तंभ 11 में,—

(क) मद (ii) (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ख) 10 प्रतिशत निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रोत्ति द्वारा, जिसके 6 हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा :—

(1) ऐसे स्नातक समूह “घ” पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष निरन्तर नियमित सेवा की है, लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर,

(2) ऐसे स्नातक लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष निरन्तर नियमित सेवा की है, लेखा परीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, और।

(3) ऐसे लिपिक जिन्होंने अनुभाग अधिकारी श्रेणी परीक्षा भाग-1 उत्तीर्ण कर ली है।

(उन व्यक्तियों का पारस्परिक वरीयता क्रम जो परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं, उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता के क्रम के अनुसार होगा और जो पूर्वतर परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं समूहिक रूप से पंक्ति में उनसे पहले होंगे जो बाद में परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं। समूह “घ” पदधारी लिपिकों के पंक्ति में नीचे होंगे।

(ख) टिप्पण में,

(i) पैरा 2 में, “प्रतिनियुक्ति की अवधि” शब्दों से आरंभ और “तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी” शब्दों से समाप्त होने वाले कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परीक्षक प्रबंध के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोत्ति की सीधी पंक्ति में हैं” प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति किए

एक व्यक्ति प्रशिक्षित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।”

(ii) पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

3. यदि उपरोक्त मद (i) (क) या (ii) (क) के अर्धन किसी अधिकारी पर ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है तो उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों पर भी, इस बात के होते हुए भी कि उन्होंने लिपिक के रूप में अपेक्षित वर्षों तक सेवा न की हो, विचार किया जाएगा यदि उन्होंने, जहां परिवर्द्धता लागू है, वह सफलतापूर्वक परिवर्द्धता पूरी कर ली है।

4. संपूर्ण विभाग के लिए चुंकि लेखा परीक्षकों के काडर और पोषक काडर केन्द्रीयकृत नहीं किए गए हैं अतः विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में ये नियम प्रत्येक काडर को लागू होंगे। उपरोक्त मद (i) (क), (ii) (क) और (ii) (ख) के अधीन विहित सेवा के अपेक्षित वर्ष-संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों में सुसंगत पोषक काडर में होने चाहिए।”

[फा. सं. ए-12018/4/89-ई. जी.-1]

डॉ. त्यागेश्वरन, अव्वर सचिव

टिप्पण—

(i) मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), तारीख 30-7-1988 के पृष्ठ 2322—2325 में सा. का. नि. सं. 615 तारीख 14-7-1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

G.S.R. 301.—In exercise of powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules to amend the Indian Audit and Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 1988, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Auditor) Recruitment (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Audit and Accounts Department (Auditor) Recruitment Rules, 1988, in column 11,—

(a) for item (ii)(b), the following shall be substituted, namely:—

“(b) 10 per cent of vacancies by promotion from the following officials, failing which by direct recruitment:—

(i) Graduate Group ‘D’ officials with three years continuous regular service in the grade on passing the Departmental Examination for Auditors;

(ii) Graduate Clerks with three years continuous regular service in the grade on passing the Departmental Examination for Auditors; and

(iii) Clerks on passing Part I of the Section Officer's Grade Examination.

(The inter-se ranking of those who qualify in the examination will be in the order of their inter-se seniority, those qualifying in any earlier examination ranking en-bloc higher than those who qualify in a later examination; Group ‘D’ officials will rank below Clerks).”;;

(b) in Note,—

(i) in paragraph 2, for the brackets and the words beginning with “(The period of deputation” and ending with “not exceed three years)”, the following shall be substituted, namely:—

“(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).”;;

(ii) after paragraph 2, the following shall be inserted, namely:—

“3. If an officer is considered for promotion on seniority basis under item (i)(a) or (ii)(a) above, all persons senior to him/her shall also be considered (if they have successfully completed the probation where probation is applicable) notwithstanding that they may not have rendered the requisite number of years of service as Clerk.

4. As the cadre of Auditors and the feeder cadres are not centralised for the whole department, the rules are applicable to each cadre in the various field offices of the department. The requisite years of service prescribed under items (i)(a), (ii)(a) and (ii)(b) above should be in the relevant feeder cadres in the field offices concerned.”

[F. No. A-12018/4/89-E.G. I]

D. THYAGESWARAN, Under Secy.

Note.—The principle rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated 30th July, 1988 at pages 2322—2325 vide GSR No. 615 dated 14th July, 1988.

उद्योग मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1990

सा.का.नि. 302.—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620क की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स तमिलनाडु आर्टिजंस बेनिफिट फंड लिमिटेड को, जो एक कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय तमिलनाडु राज्य में 39, मुथुविनायगर कोयल स्ट्रीट (प्रथमतः) कोयम्बतूर-641001 में है, एक निधि घोषित करती है और यह निदेश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (कंपनी विधि प्रशासन विभाग) की अभिसूचना सं. सा. का. नि. 978, तारीख 28 मई, 1963 की अनुसूची 3 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त निधि को लागू नहीं होंगे या यथास्थिति, उसके स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट

अपवादों, उपातरणों और अनुकूलनों सहित लागू होंगे और उक्त अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची 1 में, मद 112 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी अर्थात् :—

“113. मैसर्स तमिलनाडु आर्टिजन्स बेनिफिट फंड लिमिटेड” ।

[फा. सं. 37/10/89-सी.एल.-III]

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 978 दिनांक 28 मई, 1963 को अधिसूचित की गयी थी और तदन्तर यथा संशोधित की गयी :—

1. सा.का.नि. सं. 1681	दिनांक 11.10.63
2. सा.का.नि. सं. 853	दिनांक 4.6.64
3. सा.का.नि. सं. 297	दिनांक 12.2.65
4. सा.का.नि. सं. 1332	दिनांक 30.8.65
5. सा.का.नि. सं. 111	दिनांक 14.1.66
6. सा.का.नि. सं. 1543	दिनांक 1.10.66
7. सा.का.नि. सं. 607	दिनांक 29.4.67
8. सा.का.नि. सं. 608	दिनांक 29.4.67
9. सा.का.नि. सं. 1166	दिनांक 6.6.69
10. सा.का.नि. सं. 2707	दिनांक 18.11.69
11. सा.का.नि. सं. 1306	दिनांक 27.7.71
12. सा.का.नि. सं. 1	दिनांक 21.12.73
13. सा.का.नि. सं. 690	दिनांक 22.6.74
14. सा.का.नि. सं. 275	दिनांक 14.2.75
15. सा.का.नि. सं. 409	दिनांक 29.3.75
16. सा.का.नि. सं. 1300	दिनांक 11.9.76
17. सा.का.नि. सं. 426	दिनांक 8.3.78
18. सा.का.नि. सं. 728	दिनांक 28.4.78
19. सा.का.नि. सं. 1296	दिनांक 4.10.79
20. सा.का.नि. सं. 1100	दिनांक 9.10.80
21. सा.का.नि. सं. 1099	दिनांक 9.10.80
22. सा.का.नि. सं. 164	दिनांक 10.2.83
23. सा.का.नि. सं. 843	दिनांक 19.11.83
24. सा.का.नि. सं. 844	दिनांक 19.11.83
25. सा.का.नि. सं. 217	दिनांक 25.2.84
26. सा.का.नि. सं. 231	दिनांक 20.2.85
27. सा.का.नि. सं. 21	दिनांक 24.12.85
28. सा.का.नि. सं. 275	दिनांक 3.3.86
29. सा.का.नि. सं. 306	दिनांक 11.4.86
30. सा.का.नि. सं. 70	दिनांक 22.6.86
31. सा.का.नि. सं. 961	दिनांक 24.10.86
32. सा.का.नि. सं. 353	दिनांक 22.4.87
33. सा.का.नि. सं. 365	दिनांक 22.4.87
34. सा.का.नि. सं. 430	दिनांक 20.5.87
35. सा.का.नि. सं. 598	दिनांक 31.7.87
36. सा.का.नि. सं. 597	दिनांक 31.7.87
37. सा.का.नि. सं. 921	दिनांक 30.11.87
38. सा.का.नि. सं. 922	दिनांक 3.12.87
39. सा.का.नि. सं. 264	दिनांक 5.4.88
40. सा.का.नि. सं. 479	दिनांक 18.6.88
41. सा.का.नि. सं. 515	दिनांक 25.6.88
42. सा.का.नि. सं. 597	दिनांक 15.7.88
43. सा.का.नि. सं. 596	दिनांक 15.7.88
44. सा.का.नि. सं. 598	दिनांक 15.7.88

45. सा.का.नि. सं. 800	दिनांक 22.9.88
46. सा.का.नि. सं. 961	दिनांक 17.12.88
47. सा.का.नि. सं. 32	दिनांक 6.12.88
48. सा.का.नि. सं. 959	दिनांक 17.12.88
49. सा.का.नि. सं. 960	दिनांक 17.12.88
50. सा.का.नि. सं. 318	दिनांक 6.5.89
51. सा.का.नि. सं. 501	दिनांक 22.7.89
52. सा.का.नि. सं. 502	दिनांक 22.7.89
53. सा.का.नि. सं. 649	दिनांक 22.8.89
54. सा.का.नि. सं. 650	दिनांक 22.8.89
55. सा.का.नि. सं. 651	दिनांक 22.8.89
56. सा.का.नि. सं. 844	दिनांक 25.10.89
57. सा.का.नि. सं. 102	दिनांक 5.2.90
58. सा.का.नि. सं. 241	दिनांक 29.3.90

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 16th April, 1990

G.S.R. 302.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 620A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby declares M/s. 'Tamilnadu Artisans' Benefit Fund Limited, a company having its registered office at 39, Matruvinnayagar Kott Street (1st Floor), Coimbatore-641001, (Tamil Nadu) in the State of Tamil Nadu, to be a Nidhi and directs that the provisions of the said Act specified in Column (1) of Schedule III to the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry (Department of Company Law Administrations) No. G.S.R. 978, dated the 28th May, 1963, shall not apply, or as the case may be, shall apply with the exceptions, modifications and adaptations specified in the corresponding entry in column (2) thereof, to the said Nidhi, and makes the following amendment in the said notification, namely :—

In Schedule I to the said notification, after item 112 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be added, namely :—

“113. M/s. Tamilnadu Artisans' Benefit Fund Limited.”

[F. No. 37/10/89-CL-III]

Note :—The Principal Notification was notified vide GSR No. 978 dated 28th May, 1963 and subsequently amended vide :—

1. GSR No. 1681, dated 11-10-63.
2. GSR No. 853, dated 4-6-64.
3. GSR No. 297, dated 12-2-1965.
4. GSR No. 1332, dated 30-8-65.
5. GSR No. 111, dated 14-1-66.
6. GSR No. 1543, dated 1-10-66.
7. GSR No. 607, dated 29-4-67.
8. GSR No. 608, dated 29-4-67.
9. GSR No. 1466, dated 6-6-69.
10. GSR No. 2707, dated 18-11-69.
11. GSR No. 1306, dated 27-7-71.
12. GSR No. 1, dated 21-12-1973.
13. GSR No. 690, dated 22-6-74.
14. GSR No. 275, dated 14-2-75.
15. GSR No. 409, dated 29-3-75.
16. GSR No. 1300, dated 11-9-76.
17. GSR No. 426, dated 8-3-78.
18. GSR No. 728, dated 28-4-1978.

19. GSR No. 1296, dated 4-10-79.
20. GSR No. 1100, dated 9-10-80.
21. GSR No. 1099, dated 9-10-1980.
22. GSR No. 164, dated 10-2-83.
23. GSR No. 843, dated 19-11-83.
24. GSR No. 844, dated 19-11-83.
25. GSR No. 217, dated 25-2-84.
26. GSR No. 231, dated 20-2-85.
27. GSR No. 21, dated 24-12-85.
28. GSR No. 275, dated 3-3-86.
29. GSR No. 306, dated 11-4-86.
30. GSR No. 70, dated 22-6-86.
31. GSR No. 961, dated 24-10-86.
32. GSR No. 353, dated 22-4-87.
33. GSR No. 365, dated 22-4-87.
34. GSR No. 430, dated 20-5-87.
35. GSR No. 598, dated 31-7-87.
36. GSR No. 597, dated 31-7-87.
37. GSR No. 921, dated 30-11-87.
38. GSR No. 922, dated 3-12-87.
39. GSR No. 264, dated 5-4-88.
40. GSR No. 479, dated 18-6-88.
41. GSR No. 515, dated 25-6-88.
42. GSR No. 597, dated 15-7-88.
43. GSR No. 596, dated 15-7-88.
44. GSR No. 598, dated 15-7-88.
45. GSR No. 800, dated 22-9-88.
46. GSR No. 961, dated 17-12-88.
47. GSR No. 32, dated 6-12-88.
48. GSR No. 959, dated 17-12-88.
49. GSR No. 960, dated 17-12-88.
50. GSR No. 318, dated 6-5-89.
51. GSR No. 501, dated 22-7-89.
52. GSR No. 502, dated 22-7-89.
53. GSR No. 649, dated 22-8-89.
54. GSR No. 650, dated 22-8-89.
55. GSR No. 651, dated 22-8-89.
56. GSR No. 844, dated 25-10-89.
57. GSR No. 102, dated 5-2-90.
58. GSR No. 728, dated 29-3-90.

नई दिल्ली, 10 मई, 1990

सा.का.नि. 303.—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620 क की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स केलिज बेनिफिट फंड लिमिटेड को, जो एक कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय तमिलनाडु राज्य में 29, डां मुनिअप्पा रोड, किलपॉक, मद्रास-600010 में है, एक निधि घोषित करती है और यह निदेश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (कंपनी विधि प्रशासन, विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 978, तारीख 28 मई 1963 की अनुसूची 3 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त निधि को लागू नहीं होंगे या, यथास्थिति, उसके स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अपवादों, उपंतरणों और

अनुकूलनों सहित लागू होंगे और उक्त अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करता है. अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची 1 में मद 113 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

“114. मैसर्स केलिज, बेनिफिट फंड लिमिटेड”।

[फा.सं. 37/23/89-जी.एल. III]

यू.पी. माधुर, निदेशक

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 978 दिनांक 28 मई, 1963 की अधिसूचित की गयी थी और तदन्तर यथा संशोधित की गयी :—

1. सा.का.नि. सं. 1681	दिनांक 11.10.63
2. सा.का.नि. सं. 853	दिनांक 4.6.64
3. सा.का.नि. सं. 297	दिनांक 12.2.65
4. सा.का.नि. सं. 1332	दिनांक 30.8.65
5. सा.का.नि. सं. 111	दिनांक 14.1.66
6. सा.का.नि. सं. 1543	दिनांक 1.10.66
7. सा.का.नि. सं. 697	दिनांक 29.4.67
8. सा.का.नि. सं. 698	दिनांक 29.4.67
9. सा.का.नि. सं. 1466	दिनांक 6.6.69
10. सा.का.नि. सं. 2707	दिनांक 18.11.69
11. सा.का.नि. सं. 1306	दिनांक 27.7.71
12. सा.का.नि. सं. 1	दिनांक 21.12.73
13. सा.का.नि. सं. 690	दिनांक 22.6.74
14. सा.का.नि. सं. 275	दिनांक 14.2.75
15. सा.का.नि. सं. 409	दिनांक 29.3.75
16. सा.का.नि. सं. 1300	दिनांक 11.9.76
17. सा.का.नि. सं. 426	दिनांक 8.3.78
18. सा.का.नि. सं. 728	दिनांक 28.4.78
19. सा.का.नि. सं. 1296	दिनांक 4.10.79
20. सा.का.नि. सं. 1100	दिनांक 9.10.80
21. सा.का.नि. सं. 1099	दिनांक 9.10.80
22. सा.का.नि. सं. 164	दिनांक 10.2.83
23. सा.का.नि. सं. 843	दिनांक 19.11.83
24. सा.का.नि. सं. 844	दिनांक 19.11.83
25. सा.का.नि. सं. 217	दिनांक 25.2.84
26. सा.का.नि. सं. 231	दिनांक 20.2.84
27. सा.का.नि. सं. 21	दिनांक 24.12.85
28. सा.का.नि. सं. 275	दिनांक 3.3.86
29. सा.का.नि. सं. 306	दिनांक 11.4.86
30. सा.का.नि. सं. 70	दिनांक 22.6.86
31. सा.का.नि. सं. 961	दिनांक 24.10.86
32. सा.का.नि. सं. 353	दिनांक 22.4.87
33. सा.का.नि. सं. 365	दिनांक 22.4.87
34. सा.का.नि. सं. 430	दिनांक 20.5.87
35. सा.का.नि. सं. 598	दिनांक 31.7.87
36. सा.का.नि. सं. 597	दिनांक 31.7.87
37. सा.का.नि. सं. 921	दिनांक 30.11.87
38. सा.का.नि. सं. 922	दिनांक 3.12.87

39. सा.का.नि. सं.	264	दिनांक	5.4.88
40. सा.का.नि. सं.	479	दिनांक	18.6.88
41. सा.का.नि. सं.	515	दिनांक	25.6.88
42. सा.का.नि. सं.	597	दिनांक	15.7.88
43. सा.का.नि. सं.	596	दिनांक	15.7.88
44. सा.का.नि. सं.	598	दिनांक	15.7.88
45. सा.का.नि. सं.	800	दिनांक	22.9.88
46. सा.का.नि. सं.	961	दिनांक	17.12.88
47. सा.का.नि. सं.	32	दिनांक	6.12.88
48. सा.का.नि. सं.	959	दिनांक	17.12.88
49. सा.का.नि. सं.	960	दिनांक	17.12.88
50. सा.का.नि. सं.	318	दिनांक	6.5.89
51. सा.का.नि. सं.	501	दिनांक	22.7.89
52. सा.का.नि. सं.	502	दिनांक	22.7.89
53. सा.का.नि. सं.	649	दिनांक	22.8.89
54. सा.का.नि. सं.	650	दिनांक	22.8.89
55. सा.का.नि. सं.	651	दिनांक	22.8.89
56. सा.का.नि. सं.	844	दिनांक	25.10.89
57. सा.का.नि. सं.	102	दिनांक	5.2.90
58. सा.का.नि. सं.	241	दिनांक	29.3.90

New Delhi, the 10th March, 1990

G.S.R. 303.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 620A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby declares Messrs. Kellys Benefit Fund Limited a company having its registered office at 29, Dr. Muniyappa Road, Kilpauk, Madras-600010 in the State of Tamil Nadu, to be a Nidhi and directs that the provisions of the said Act specified in column (1) of Schedule III to the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry (Department of Company Law Administrations) No. G.S.R. 978 dated the 28th May, 1963 shall not apply, or as the case may be, shall apply with the exceptions, modifications and adaptations specified in the corresponding entry in column (2) thereof, to the said Nidhi and makes the following amendment in the said notification, namely :—

In Schedule I to the said notification, after item 113 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be added, namely :—

“114. Messrs. Kellys Benefit Fund Limited.”

[F. No. 37/23/89-CL-III]

U. P. MATHUR, Director

Note :—The Principal Notification was notified vide GSR No. 978 dated 28th May, 1963 and subsequently amended vide :—

1. GSR No. 1681, dated 11-10-63.
2. GSR No. 853, dated 4-6-64.
3. GSR No. 297, dated 12-8-65.
4. GSR No. 1332, dated 30-8-65.
5. GSR No. 111, dated 14-1-66.
6. GSR No. 1543, dated 1-10-66.
7. GSR No. 607, dated 29-4-67.
8. GSR No. 608, dated 29-4-67.
9. GSR No. 1466, dated 6-6-69.
10. GSR No. 2707, dated 18-11-69.

11. GSR No. 1306, dated 27-7-71.
12. GSR No. 1, dated 21-12-73.
13. GSR No. 690, dated 22-6-74.
14. GSR No. 275, dated 14-2-75.
15. GSR No. 409, dated 29-3-75.
16. GSR No. 1300, dated 11-9-76.
17. GSR No. 426, dated 8-3-78.
18. GSR No. 728, dated 28-4-78.
19. GSR No. 1296, dated 4-10-79.
20. GSR No. 1100, dated 9-10-80.
21. GSR No. 1099, dated 9-10-80.
22. GSR No. 164, dated 10-2-83.
23. GSR No. 843, dated 19-11-83.
24. GSR No. 844, dated 19-11-83.
25. GSR No. 217, dated 25-2-84.
26. GSR No. 231, dated 20-2-85.
27. GSR No. 21, dated 24-12-85.
28. GSR No. 275, dated 3-3-86.
29. GSR No. 306, dated 11-4-86.
30. GSR No. 70, dated 22-6-86.
31. GSR No. 961, dated 24-10-86.
32. GSR No. 353, dated 22-4-87.
33. GSR No. 365, dated 22-4-87.
34. GSR No. 430, dated 20-5-87.
35. GSR No. 598, dated 31-7-87.
36. GSR No. 597, dated 31-7-87.
37. GSR No. 921, dated 30-11-87.
38. GSR No. 922, dated 3-12-87.
39. GSR No. 264, dated 5-4-88.
40. GSR No. 479, dated 18-6-88.
41. GSR No. 515, dated 25-6-88.
42. GSR No. 597, dated 15-7-88.
43. GSR No. 596, dated 15-7-88.
44. GSR No. 598, dated 15-7-88.
45. GSR No. 800, dated 22-9-88.
46. GSR No. 961, dated 17-12-88.
47. GSR No. 32, dated 6-12-88.
48. GSR No. 959, dated 17-12-88.
49. GSR No. 960, dated 17-12-88.
50. GSR No. 318, dated 6-5-89.
51. GSR No. 501, dated 22-7-89.
52. GSR No. 502, dated 22-7-89.
53. GSR No. 649, dated 22-8-89.
54. GSR No. 650, dated 22-8-89.
55. GSR No. 651, dated 22-8-89.
56. GSR No. 844, dated 25-10-89.
57. GSR No. 102, dated 5-2-90.
58. GSR No. 241, dated 29-3-90.

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प का कार्यालय)

नई दिल्ली, 7 मई, 1990

सा.का.नि. 304 :- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूतपूर्व मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित सा.का.नि. 85, दिनांक 26-1-85 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय (अन्वेषक का पद) भर्ती नियम, 1984 में और संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्नोक्त नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) ये विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय (अन्वेषक का पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990 कहे जा सकेंगे।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय (अन्वेषक का पद) भर्ती नियम, 1984 में अनुसूची के लिए निम्नोक्त अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची

- | | |
|---|--|
| 1. पद का नाम | : अन्वेषक |
| 2. पदों की संख्या | : 100 (कार्यभार पर निर्भर विभिन्नता के अध्वधीन) |
| 3. वर्गीकरण | : वर्ग 'ग' अराजपत्रित, अलिपिक वर्गीय |
| 4. वेतनमान | : 1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रु. |
| 5. प्रवरण अथवा अप्रवरण पद | : प्रवरण |
| 6. क्या सी.सी.एस. (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के वधित वर्षों के लाभग्राह्य है। | : नहीं |
| 6क. सी.सी. भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा। | : 20-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक की छूट) |
| 7. सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं | टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, लाहोल एवं स्पीती जिला, एवं हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पंछी सब डिवीजन एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि होगी) ऐसे पदों के सम्बन्ध में जिनके लिए नियुक्ति रोजगार कार्यालय द्वारा की जाती है, आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि रोजगार कार्यालय द्वारा नाम प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि होगी। |
| 8. क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं। | : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य। |
| 9. परीक्षा की अवधि यदि कोई हो | : दो वर्ष |
| 10. भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | : (1) 50% प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
(2) 50% सीधी भर्ती द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा। |
| 11. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने पर वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाता है | प्रोन्नति : 1200-2040 रु. के वेतनमान में गैर केन्द्रीय सचिवालय सेवा उच्च श्रेणी लिपिक एवं वर्ग (घ) आशुलिपिकों (क्षेत्रीय कार्यालयों, क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्रों एवं वाद्य यंत्र विकास केन्द्र मद्रास के वर्ग "घ" आशुलिपिकों को छोड़कर) एवं क्रमशः 1200-2040 रु. के वेतनमान में स्टोरकीपर (कालीन योजना के अंतर्गत आने वाले स्टोरकीपरों को छोड़कर) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय एवं इसी अधीनस्थ कार्यालयों में उमी वर्ष कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा। |

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : 1200-2040 के वेतनमान में उमी वर्ष में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित केन्द्रीय सरकार कार्यालयों अथवा केन्द्रीय राज्य कार्यालयों में समतुल्य अथवा समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारी उनके पात्र कालम 7 में दी गई सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि उसी संगठन/विभाग में किसी अन्य स्वयं बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित इस नियुक्ति के तत्काल पश्चात नौ नव वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान : 1. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) -- अध्यक्ष
है तो इसका गठन क्या है ? 2. संयुक्त विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) -- सदस्य
3. संयुक्त विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) विपणन के प्रभारी -- सदस्य
4. विभाग से बाहर के उपयुक्त स्तर के क अधिकारी -- सदस्य
13. वे परिस्थितियाँ जिनमें संघ लोक सेवा : लागू नहीं होता ।
आयोग से परामर्श किया जाता है ।

[फाइल सं. 1/2/90/प्रशा.-3]

डी.के. मुखोपाध्याय, संयुक्त विकास आयुक्त
(हस्तशिल्प)
कृते विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

टिप्पणी : 1984 के मूल नियम और उसमें 1985 में किए गए संशोधन सं. 85 दिनांक 26-1-1985 एवं सं. का. नि. सं. 592 दिनांक 28-10-85 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए हैं ।

MINISTRY OF TEXTILES

[Office of the Development Commissioner (Handicrafts)]

New Delhi, the 7th May, 1990

G.S.R. 304—In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) (post of Investigator) Recruitment Rules, 1984, published with the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce No. G.S.R. 85, dated the 26th January, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) (Posts of Investigator) Recruitment (Amendment) Rules, 1990.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) (Post of Investigator) Recruitment Rules, 1984, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

1. Name of the post	Investigator
2. No. of post	100 (Subject to variation dependent on workload).
3. Classification	Group 'C', Non-gazetted,
4. Scale of pay	Non-Ministerial
5. Whether selection or non-selection post	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300.
6. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Selection. No
6A. Age limit for direct recruits	20-26 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division of J and K State, Lahaul and Spiti district and Pangri sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In respect of posts, the appointment to which is made through the Employment Exchanges, crucial date for determining the age limit will in each case be the last date upto which Employment Exchanges are asked to submit the names.

7. Educational and other qualifications required for direct recruits	Bachelor's Degree in any subject from a recognised University or its equivalent.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	No
9. Period of probation, if any	Two years
10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	(i) 50% by promotion, failing which by transfer on deputation and failing both, by direct recruitment (ii) 50% by direct recruitment failing which by transfer on deputation.
11. In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	Promotion : Non-Central Secretariat Service Upper Division Clerks and Grade 'D' Stenographers in the scale of Rs. 1200-2040 (excepting Stenographers Grade 'D' in the Regional Offices, Regional Design and Tech. Development Centres, and Development Centre for Musical Instruments, Madras) and Storekeepers (since merged and redesignated) in the scale of Rs. 1200-2040 respectively (excepting Storekeepers covered by the Carpet Scheme) in the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) and all its subordinate offices with at least 5 years' regular service in the grade. Transfer on deputation : Officers in the Central Government Offices or the State Government Offices holding equivalent or analogous posts or working in the grade of Rs. 1200-2040 with at least 5 years' regular service in the grade. They should possess qualifications prescribed for direct recruits in column 7. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Government shall ordinarily not exceed 3 years).
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	1. Development Commissioner (Handicrafts)— —Chairman 2. Joint Development Commissioner (Handicrafts) —Member 3. Joint Development Commissioner (Handicrafts) (Incharge of Marketing)—Member 4. An officer of appropriate status from outside the Department —Member
13. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Not applicable

[F. No. 1/2/90-Admn. III]

D.K. MUKHOPADHYAY, Joint Development
Commissioner (Handicrafts) for Development
Commissioner (Handicrafts)

Note : The Principal Rules of 1984 and the amendment made therein in 1985 have been published under G.S.R. No. 85 dated 26-1-1985 and G.S.R. No. 992 dated 28th Oct.' 85.

कृषि संवादन

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 27 मार्च 1990

सं.का.नि. 305 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, कृषि और सहकारिता विभाग, अर्थ और मांडिकी निदेशालय, विशेष सलाहकार (लागत अध्ययन) भर्ती नियम, 1986 में प्रो. संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और सहकारिता विभाग, अर्थ और मांडिकी निदेशालय, विशेष सलाहकार (लागत अध्ययन) भर्ती नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कृषि और सहकारिता विभाग, अर्थ और मांडिकी निदेशालय, विशेष सलाहकार (लागत अध्ययन) भर्ती नियम, 1986 की अनुसूची में :—

(1) स्तम्भ 2 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

1*

(1990)

* कर्मभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(ii) स्तम्भ 4 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“4500-150-5700 रुपये”

(iii) स्तंभ 12 में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने 4100-5300 रुपये के वेतनमान वाले पदों पर या समतुल्य पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की हो, या

(iii) जिन्होंने 3700-5000 रुपये के वेतनमान वाले पदों पर या समतुल्य पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की हो, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित अतिरिक्त अर्हताएं हों :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि या कृषि अर्थशास्त्र या प्रबंधशास्त्र में मास्टर डिग्री या समतुल्य अर्हता, और

(ii) कृषि क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान में (जिसके अंतर्गत फार्म अर्थिक विश्लेषण और अनेक कृषि संबंधी दम्पुओं की खेती पर आने वाली लागत भी है) 12 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अतिरिक्त अर्हताओं

(ii) से संगम विषय में पी.एच.डी. डिग्री।

(उसी संगठन या केन्द्रीय सरकार के पास किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति या संविदा का अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी।)

[सं. 13026/6/86-अर्थ प्रशासन]

बी० के गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के कृषि संवादन के कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना सं. 13013/1/85-अर्थ प्रशासन, तारीख 20 अक्तूबर, 1986 (सं.का.नि. सं. 1986 का 948) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Deptt of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 27th March, 1990

G.S.R. 305.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Agriculture and Cooperation, Directorate of Economics and Statistics, Special Adviser (Cost Studies) Recruitment Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Agriculture and Cooperation, Directorate of Eco-

nomics and Statistics, Special Adviser (Cost Studies) Recruitment (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Agriculture and Cooperation, Directorate of Economics and Statistics, Special Adviser (Cost Studies) Recruitment Rules, 1986,—

(i) in Column 2, for the entry, the following entry shall be substituted namely :—

“1*

(1990)

*Subject to variation dependent on workload.”; -

(ii) in column 4, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“Rs. 4500-150-5700.”;

(iii) in Column 12, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“TRANSFER ON DEPUTATION (including short term contract) : Officers under the Central Government or State Governments or Universities or Recognised Research Institutions and Public Sector Undertakings—

(i) holding analogous post on a regular basis; or

(ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 4100-5300 or equivalent; or

(iii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 3700-5000 or equivalent; and

(b) possessing—Essential :

(i) Master's degree in Agriculture or Agricultural Economics or Economics from a recognised University or equivalent; and

(ii) 12 years' experience in research relating to Agricultural discipline (including Farm Economic Analysis and Cost of Cultivation of various agricultural commodities).

Desirable :

Ph. D Degree from a recognised University relevant to Educational Qualifications (ii).

(Period of deputation or contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall not exceed 5 years)."

[No. 13026/6/86-EA]

B. K. GUPTA, Under Secy.

NOTE.—The Principal Rules were published in Part II Section 3 Sub-Section (i) of the Gazette of India under the notification of the Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, No. 13013/1/85-EA dated 20th October, 1986, (GSR No. 948 of 1986).

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1990

सा. का. नि. 306 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तारण निदेशालय (उद्यान कृषि अधिकारी) भर्ती नियम, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:— अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विस्तारण निदेशालय (उद्यान कृषि अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विस्तारण निदेशालय (उद्यान कृषि अधिकारी) भर्ती नियम, 1973 में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
उद्यान कृषि अधिकारी	1* (1990)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित	2700-75-280 0-द. रो. - 100-4000 रु.	लागू नहीं होता
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।			

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा

सेवा में जोड़े हुए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं

6

7

35 वर्ष से अधिक नहीं :

लागू नहीं होता

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्याथियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप में अभ्याथियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित परीक्षा की अवधि यदि कोई हो
अन्य अर्हताएं आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोक्त व्यक्तियों की
दशा में लागू होंगी या नहीं

8

9

10

आवश्यक : नागू नहीं होता सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के
(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में उद्यान में 1 वर्ष पुनर्नियोजन पर आने वाले
कृषि विशेषज्ञता सहित कृषि में एम.एस.सी./उद्यान व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष
कृषि (जिसके अंतर्गत पुष्प कृषि, आंतराकल्चर भी है)
में एम.एस.सी. या समतुल्य।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उच्च भूमि निर्माण/
उद्यान कृषि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित बी.
एस.सी. (कृषि) या समतुल्य।

(2) किसी सरकारी विभाग या किसी दयातिप्राप्त प्राइवेट
फर्म में उद्यान कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यान कृषि,
जिसके अंतर्गत वागवानी भी है, में पर्यवेक्षण हैसियत
में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण :—(1) अर्हताएं अथवा पुराहित प्रश्रयियों की
दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार
शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण :—(2) अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा
आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित
जनजातियों के अभ्यासियों की दशा में तब शिथिल की
जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर
संघ लोक सेवा आयोग को यह राय है कि उनके
लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यासियों
के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना
नहीं है।

वांछनीय :—(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
से कृषि/उद्यान कृषि या वनस्पति विज्ञान में डॉक्टरेट
डिग्री या समतुल्य।

(2) प्रशासनिक अनुभव।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/
स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की
प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।

11

12

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है)
स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

भूतपूर्व सैनिकों के लिए

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनर्नियोजन द्वारा

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है)/
स्थानान्तरण :—

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/लोक उद्यमों/अर्द्ध-सरकारी स्वायत्त या कानूनी
संगठन/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों
के अधीन ऐसे अधिकारी—

(क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(2) जिन्होंने 2000-3500 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर
3 वर्ष नियमित सेवा की है, या

11

12

(3) जिन्होंने 1640-2900 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकाधिक शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनर्नियोजन

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या

रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित और अर्हताएं और अनुभव है। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रदान की जाएगी जिन तारीख में उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)

(प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) (जिसमें निम्नलिखित होंगे)

चयन, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. संयुक्त सचिव (विस्तारण) | —अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) | —सदस्य |
| 3. संयुक्त सचिव (फसल) | —सदस्य |
| 4. निदेशक, प्रशासन, विस्तारण निदेशालय | —सदस्य |

[सं. 29-3/88-सी.ए.-4]

सोनी राम, अवसर सचिव

टिप्पण: पुष्टि में संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति का आर्थिक/व्यय, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी। किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति को बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगा।

गादटिप्पण: मूलनियम, भारत के राजपत्र सा.का.नि. सं. 1071 तारीख 29-9-73 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें सा.का.नि. सं. 744 तारीख 8-10-1983 द्वारा संशोधन किया गया।

New Delhi, the 18th April, 1990

G.S.R. 306.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the president hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Extension (Horticulture Officer) Recruitment Rules, 1973, namely :—

1. (i) These rules may be called the Directorate of Extension (Horticulture Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Directorate of Extension (Horticulture Officer) Recruitment Rules, 1973, for the Schedule the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
Horticulture Officer	1* (1990) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted	Rs. 2200-75-2800-EB- 100-4000.
Whether Selection post or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	
5	6	7	
Not applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The Crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Andaman and Nicobar islands or Lakshadweep).	Not applicable	
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	
8	9	10	
Essential : (i) M.Sc. in Agriculture with specialisation in Horticulture/M.Sc. in Horticulture (including Floriculture, Olericulture etc.) from a recognised University or equivalent). Or B.Sc. (Agriculture) with Post-Graduate Diploma in Landscape Architecture/Horticulture from a recognised University or equivalent.	Not applicable	1 Year for direct recruits. 2 Years for persons coming on re-employment.	

- (ii) 3 years' experience in a supervisory capacity in horticulture including gardening ranging over various fields of Horticulture in a Government Department or in a private firm of repute.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribe if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable :

- (i) Doctorate Degree in Agriculture/Horticulture or Botany from a recognised University or equivalent.
(ii) Administrative experience.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods

11

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/transfer/deputation to be made

12

By transfer on deputation (including short-term contract) Transfer failing which by direct recruitment.

For ex-servicemen :

By transfer on deputation/re-employment.

Transfer on deputation (including short-term contract)/Transfer : Officers under the Central/State Governments/Public Undertaking /Semi Government, Autonomous or Statutory Organisation/Agricultural Universities/Recognised Research institutions or Councils.

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
(ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; or
(iii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent; and
(b) possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under column 8.

For Ex-servicemen transfer on Deputation/Re-employment : Armed Forces Personnel who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col. 8 shall also be considered. Such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment. (Re-employment upto the age of superannuation with reference to Civil posts). (Period of deputation/contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—

1. Joint Secretary (Extension) —Chairman
2. Joint Secretary (Administration) —Member
3. Deputy Secretary (Crops) —Member
4. Director of Administration Directorate of Extension —Member

Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If however, these are not approved by the Union Public Service Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

[No. 29-3/88-C&A. IV]

SONA RAM, Under Secy.

Foot Note : The principal Rule was published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 1071 dated 29-9-1973 and subsequently amended vide G.S.R. No. 744 dated 8-10-1983.

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1990

मा. का. नि. 307:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उर्वरक निर्वहण प्रयोगशाला, फरीदाबाद (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात्

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम: केन्द्रीय उर्वरक निर्वहण प्रयोगशाला, फरीदाबाद (समूह 'ग' पद) (संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन का तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उर्वरक निर्वहण प्रयोगशाला, फरीदाबाद (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1979 का अनुसूची में कम संख्यांक 2 और उसमें संबंधित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीमा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
"2. लेखाकार	एक* (1990)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अग्रज- पत्रित अतनुसूचिकीय	1400-40-1800- द.रो.-50-2300 रूप	चयन	लागू नहीं होता
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				
सीमा भर्ती किए जाने वाले जाने वाले व्यक्तियों के लिए, परीक्षा की अवधि यदि कोई हो					
लिपि शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीमा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए, लिखित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोत्त व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			
8		9		10	
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		2 वर्ष	

भर्ती को पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा

11

12

प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा

प्रोन्नति : केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक सह-रखवाल जिसने पांच वर्ष सेवा की है और जिसने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली से रोकड़ तथा लेखा कार्य का सफलता-पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, जिसे, बजट और लेखा कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—

- (1) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
 - (2) जिन्होंने 1200-2040 रुपए की श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली से रोकड़ और लेखा कार्य का सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या जिन्हें बजट और लेखा से संबंधित कार्य का तीन वर्ष का अनुभव है।
- (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन (समूह "ग")

लागू नहीं होता

1. निदेशक, केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान —अध्यक्ष
2. मुख्य विश्लेषक, केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य
3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य
4. बाहर से एक राजपत्रित अधिकारी —सदस्य

[सं. 10-16/87-उर्वरक]

ए.के. गंधोर, डैरक अधिकारी (उर्वरक योजना)

New Delhi, 23rd April, 1990

G.S.R. 307.—in exercise of the powers conferred by the Proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Fertilizer Control Laboratory, Faridabad (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1979, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Central Fertilizer Control Laboratory, Faridabad (Group C posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Fertilizer Control Laboratory, Faridabad (Group C posts) Recruitment Rules, 1979, in the Schedule for serial number 2 and the entries relating thereto the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

1228 GI/90—5.

Sl. Name of the post No.	Number of Posts	Classification of the posts	Scale of pay
1	2	3	5
"2. Accountant	One (1990)* *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-gazetted Ministerial.	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300/-
Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruitment.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of appointment made by promotion/transfer.
6	7	8	9
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	
10	11	12	
Two years	Promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion : Upper Division Clerk/Upper Division Clerk-cum-Caretaker in Central Fertilizer Quality Control and Training Institute with five years regular service and having successfully undergone training in cash and accounts at the Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi; or having three years' experience in work of budget and accounts. By Transfer on deputation : Officials of Central Government:— (i) holding analogous posts; or (ii) with five years' regular service in the grade of Rs. 1200-2040 and having successfully undergone training in cash and accounts at the Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi or with three years' experience in work relating to budget and accounts. (period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years).	

Composition of Departmental Promotion Committee.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

13

14

Composition of Departmental Promotion Committee (Group C)

Not applicable".

1. Director, Central Fertilizer Quality Control and Training Institute.
—Chairman

2. Chief Analyst, Central Fertilizer Quality Control and Training Institute.—Member.

3. Administrative Officer, Central Fertilizer Quality Control and Training Institute.—Member.

4. One gazetted Officer from outside.—Member.

[No. 10-16/87-Fert. Plg.]

A.K. GAMBHIR, Desk Officer (Fert. Plg.)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1990

सा. का. नि. 308.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में अन्वेषक (पी. एफ. ए.) और कनिष्ठ अन्वेषक (पी. एफ. ए.) के पदों पर पर भर्ती का पद्धति का विनिर्धार करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय अन्वेषक (पी. एफ. ए.) और कनिष्ठ अन्वेषक (पी. एफ. ए.) भर्ती नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

लागू होना :— ये नियम इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची की स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पद/पदों को लागू होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य ग्रहणार्थ आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, ग्रहणार्थ और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहंता : वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनशेष है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्याप्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है :

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयनपद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े हुए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय हैं या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
	2	3	4		6	7
अन्वेषक (पी.एफ.ए.)	*4(चार) (1988)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराज- पत्रित अननुसूचित्वीय	1400-40-1800- द.रो.-50-2300	अचयन	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए या आदेशों/अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक (अनु- सूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक) शिथिल की जा सकती है। टिप्पणः—आयु सीमा अव- धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने लिए निश्चित की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिजोरम मणीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाङ्गल और स्पाति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उप-खंड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोवति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में डिग्री जिसमें रसायन एक विषय के रूप में रहा हो या कृषि या लोक स्वास्थ्य या फार्मसी या पशु चिकित्सा विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकी या डेरी प्रौद्योगिकी में डिग्री।	नहीं	2 वर्ष (केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए)

टिप्पणो :- अर्हताएं अन्यथा सूचित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

11

12

25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, 75 प्रतिशत स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति द्वारा ऐसे कनिष्ठ अन्वेषक (पी एफ ए) से जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा—

(क) ऐसे व्यक्तियों में से जो सदृश पद धारण किए हुए हैं
(ख) ऐसे व्यक्तियों से जिन्होंने केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन 1200-30-1560 द.रो. 40 द. 2040 रुपये की श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्हें खाद्य मानकीकरण से संबंधित खाद्य नमूना/मानिट्रन/सर्वेक्षण/अन्वेषण के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव है।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति:

लागू नहीं होता

(गुप्त पर भी विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

1. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता) अध्यक्ष
2. सहायक महानिदेशक (पी एफ ए) सदस्य
3. अवर सचिव (प्रशासन) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय—सदस्य
4. उप निदेशक प्रशासन—सदस्य

1	2	3	4	5
कनिष्ठ अन्वेषक (पी.एफ.ए.)	2 (1988) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपक्षित अननुसर्जनीय	1200-30-1560 द रो - 40-2040 रुपये	अवयव
6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य

11

12

प्रोन्नति द्वारा जिससे न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा

प्रोन्नति ऐसे क्षेत्रों सहितक से जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 8 वर्ष की सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण—

(क) ऐसे व्यक्तियों से जो सदृश पद धारण किए हुए हैं;

(ख) ऐसे व्यक्तियों से जिन्होंने केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन 975/1040 950/1500 रुपये की श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्हें खाद्य मानकीकरण से संबंधित खाद्य नमूना/मानिट्रन/सर्वेक्षण/अन्वेषण कार्य में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव है।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)

संयुक्त "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति

लागू नहीं होता

(युक्ति पर भी विचार करने के लिए)

जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. निदेशक, (प्रशासन और सतर्कता)—अध्यक्ष
2. सहायक सहायनिदेशक (पी एफ ए) —सदस्य
3. अवर सचिव (प्रशासन), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय—सदस्य
4. न्य निदेशक, प्रशासन—सदस्य

[सं ए.—12018/5/88-प्रशासन II स्थापना.1]

जो के चानना, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 20th April, 1990

G.S.R. 308 :— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Investigator (PFA) and Junior Investigator (PFA) in the Directorate General of Health Services, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate General of Health Services Investigator (PFA) and Junior Investigator (PFA) Recruitment Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule.

5. Disqualification—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification
1	2	3
1. Investigator (PFA)	Four *(1988) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C' Non-gazetted, non-minis- terial.

Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
4	5	6
Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	Non-selection	Not applicable
Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
7	8	9
<p>'Not exceeding 25 years'</p> <p>(Relaxable for Government servants upto 40 years (in the case of Schedule Caste/Schedule Tribes candidates upto 45 years) in accordance with the orders/instructions issued by the Central Government in this regard).</p> <p>Note:— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>A degree in Science with Chemistry as one of the subjects or a Degree in Agriculture or Public Health or Pharmacy or in Veterinary Science or in Food Technology or Dairy Technology from a University or Institute established in India by law.</p> <p>Note:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p>	No
Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation transfer to be made.
10	11	12
Two years (for direct recruits only)	25% by promotion failing which by transfer on deputation 75% by transfer/transfer on deputation failing both by direct recruitment.	<p>By promotion : from Junior Investigator (PFA) with 5 years of regular service in the grade.</p> <p>By transfer/transfer on deputation:</p> <p>(a) from persons holding analogous posts.</p> <p>(b) from persons in the grade of Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040 with 5 years regular service in the grade under Central Government/State Government/Union Territory Administration and having a minimum of 3 years experience in the field of food sampling Monitoring/Survey/Investigation work relating to Food Standardisation.</p> <p>(Period of deputation including the period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 5 years).</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13		14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation also) consisting of:—		Not applicable
1. Director (Administration and Vigilance)—Chairman		
2. Assistant Director General (PFA) —Member		
3. Under Secretary (Admn.) Ministry of Health and Family Welfare —Member		
4. Deputy Director Administration—Member		
1	2	3
2. Junior Investigation (PFA)	Two *(1988) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Services, Group 'C' Non-gazetted, Non-ministerial
4	5	6
Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040	Non-selection	Not applicable
7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable
10	11	12
Nil	By promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion : from Field Assistant (PFA) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. Transfer on deputation : (a) from persons holding analogous posts. (b) from persons in the grade of Rs. 975-1540-/950-1500, with eight years regular service in the grade. Under Central Government/State Government/Union Territory Administration and having a minimum of 3 years experience in the field of food sampling monitoring/survey/Investigation work relating to food Standardisation. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.)
13		14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation also) consisting of:—		Not applicable.
1. Director (Administration and Vigilance)—Chairman		
2. Assistant Director General (PFA)—Member		
3. Under Secretary (Admn.) Ministry of Health and Family Welfare —Member		
4. Deputy Director Administration—Member		

ग्रहरी विकास मंत्रालय
नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1990

सा.का. नि. 309-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, [केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अपर महानिदेशक) निर्माण भर्ती नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं अर्थात् :—

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अपर महानिदेशक निर्माण) भर्ती संशोधन नियम, 1990 है।
(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अपर महानिदेशक) (निर्माण) भर्ती नियम, 1986 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची ही रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सोधे भर्ती किए जाने वाले के व्यक्तियों लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े हुए फायदा केन्द्रीय (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय हैं या नहीं	वर्षों का सिविल सेवा 1972 के अधीन अनुज्ञेय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
अपर महानिदेशक 2 (1990) (निर्माण)	संघ-स्तर के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	संघ-स्तर के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	7300-100-7600 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
सोधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं							
सोधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं							
परिवर्तन की अवधि यदि कोई हो,							
लागू नहीं होता							
लागू नहीं होता							
लागू नहीं होता							
भर्ती की पद्धति/भर्ती सोधे होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता							
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/नियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।							

11

12

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति :—

- (i) ऐसा मुख्य इंजीनियर (सिविल) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।
(ii) ऐसा मुख्य इंजीनियर (विद्युत) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पणः—(i) प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी श्रेणियों में विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रतिनिदेश से तैयार की जाएगी।

- (ii) 1-1-1986 के पूर्व 2500-2750 रु. के वेतनमान में मुख्य इंजीनियर स्तर 1 के रूप में की गई सेवा को 5900-6700 रु. की श्रेणी में पात्रता सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

- (iii) यदि अपेक्षित वर्षों की सेवा करने वाले कनिष्ठ व्यक्ति पर विचार किया जाता है तो ज्येष्ठ व्यक्ति पर भी इस तथ्य के होने पर भी उसने अपेक्षित वर्षों की सेवा नहीं की है, विचार किया जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सरचना

भर्ती करने में विग परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

1. अध्यक्ष/सदस्य/संघ लोक सेवा आयोग --अध्यक्ष
2. सचिव या विशेष सचिव, शहरी विकास--सदस्य
3. महानिदेशक (निर्माण) --सदस्य

[फा. सं. 22011(1)87ई डबल्यू 1]

बी. एस. रामन, अवर सचिव

टिप्पणी:--मूल नियम, सा. का. नि. 951 (अ) तारीख 8-7-1986 द्वारा द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा. का. नि. 1148 (अ) 13-10-1986 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 25th April, 1990

G.S.R. 309.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to further amend the Central Public Works Department (Additional Director General) (Works) Recruitment Rules, 1986, namely :—

(i) These rules may be called the Central Public Works Department (Additional Director General) (Works) Recruitment (Amendment) Rules, 1990.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the Schedule to the Central Public Works Department (Additional Director General) (Works) Recruitment Rules, 1986, the following schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Additional Director General (Works)	2* (1990) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 7300-100-7600	Selection	Not applicable
Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	
7	8	9	10	11	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion	

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
---	---	---

12

13

14

Promotion:

- (i) Chief Engineer (Civil) with three years' regular service in the grade.
(ii) Chief Engineer (Electrical) with three years' regular service in the grade.

NOTE:

- (i) The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grades.
(ii) Service as Chief Engineer, Level-I in the scale of Rs. 2500-2750 prior to 1-1-1986 will count for the purpose of reckoning eligibility service in the grade of Rs. 5900-6700.
(iii) If a Junior with the requisite years of service is considered the senior will also be considered not with standing the fact that he does not possess the requisite years of service.

- Group 'A' Departmental Promotion Consultation with the Committee : Union Public Service Commission not necessary.
1. Chairman/Member, Union Public Service Commission.
—Chairman
2. Secretary or special Secretary, Ministry of Urban Development—Member.
3. Director General (Works)
—Member

[F. No. 22011/1/87-EW. I]

V.S. RAMAN, Under Secy.

Note: The Principal rules were published vide G.S.R. 951 (E) dated 8-7-1986 and amended vide G.S.R. No. 1148 (E) dated 13-10-1986.

होदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1990

सां.का.नि. 3.10.— कुलपति, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में परिनियम 17(i) और परिनियम 18 के साथ पठित इ.गा.रा. मु.वि. अधिनियम, 1985 (1985 का 50वां) की धारा 26(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए जिनमें अध्यापक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी शामिल हैं, छुट्टियां नियंत्रित करने का निम्नलिखित अध्यादेश (अध्यादेश सं. 2) करते हैं।

विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए जिनमें अध्यापक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी भी शामिल हैं,

छुट्टियां नियंत्रित करने का अध्यादेश

1. संक्षिप्त नाम और प्रवृत्तता का विस्तार

इस अध्यादेश को जैसा कि परिशिष्ट "क" में विनिर्दिष्ट है होदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए जिनमें अध्यापक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी शामिल हैं, छुट्टियां नियंत्रित करने का अध्यादेश कहा जाएगा।

ये अध्यादेश 20 सितम्बर, 1985 से लागू समझे जाएंगे।

2. निर्वाचन

यदि इन अध्यादेशों के निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका समाधान प्रबंध बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

[सं. ए.जी.सी./आई. 2/89]
के. नारायणन, कुल सचिव
परिशिष्ट "क"

कर्मचारियों के लिए जिनमें शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी शामिल हैं, छुट्टी विनियमन अध्यादेश

(क) स्थायी कर्मचारी

देखें छुट्टियों के प्रकार :

(1) स्थायी कर्मचारियों को निम्न प्रकार की छुट्टियां स्वीकार्य होंगी—

- (i) कार्य (ड्यूटी) के रूप में मानी गई छुट्टियां
आकस्मिक छुट्टी
विशेष आकस्मिक छुट्टी
कार्य छुट्टी

(ii) कार्य द्वारा अर्जित छुट्टी

अर्जित छुट्टी

अर्धवेतन छुट्टी

परिवर्तित छुट्टी

(iii) कार्य द्वारा अर्जित न होने वाली (अनर्जित) छुट्टी

असाधारण छुट्टी

अर्जनशील छुट्टी

(iv) छुट्टी के खाते में जमा न होने वाली छुट्टी—

(क) शैक्षणिक कार्यों के लिए छुट्टी—

अध्ययनार्थ छुट्टी

विश्राम छुट्टी

(ख) स्वास्थ्य के आधार पर छुट्टी

प्रसूति छुट्टी

विशेष नियोज्यता छुट्टी

संगरोध छुट्टी

प्रबंधक बोर्ड आपवादिक मामलों में किसी अन्य प्रकार की छुट्टी जिसके लिए कारण बताए गए हों, ऐसी शर्तों पर दे सकता है जिन्हें वह उचित समझता है।

आकस्मिक छुट्टी

2. (i) आकस्मिक छुट्टी कार्य द्वारा अर्जित नहीं की जाती। किसी कर्मचारी को मंजूर की जाने वाली कुल आकस्मिक छुट्टियाँ एक कैलेंडर वर्ष में 12 दिन से अधिक नहीं होगी।

(ii) आकस्मिक छुट्टी विशेष आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी नहीं जा सकती। इसके साथ बैकल्पिक, जिनमें सार्वजनिक छुट्टी और रविवार अवकाश के दिन शामिल हैं, जोड़े जा सकते हैं। आकस्मिक छुट्टी के दौरान आने वाली छुट्टियाँ अथवा रविवार आकस्मिक छुट्टियों में नहीं गिनी जाएगी।

विशेष आकस्मिक छुट्टी

3. (i) किसी कर्मचारी की विशेष आकस्मिक छुट्टी जो एक कैलेंडर वर्ष में 10 दिन से अधिक नहीं होगा, निम्नलिखित कारणों से मंजूर की जा सकती है:

(क) विश्वविद्यालय, लोक सेवा आयोग, परीक्षा बोर्ड अथवा अन्य इसी प्रकार के निकायों/संस्थानों की परीक्षा संचालित करने के लिए ;

(ख) सांविधिक बोर्ड आदि से संबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए ;

(ग) विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा आयोजित साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा शैक्षिक सम्मेलन, संगोष्ठी या सेमिनार या सांस्कृतिक अथवा खेल कूद सम्बंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए ;

(घ) ऐसा अन्य कार्य करने के लिए जिसे कुलपति द्वारा शैक्षणिक कार्य के रूप में स्वीकार किया गया हो।

टिप्पणी—जिन स्थानों पर ऐसा सम्मेलन/गतिविधि होती है; उन स्थानों पर आने जाने के वास्तविक दिनों को दस दिन की गणना करते समय दस दिन की देय छुट्टी में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ii) इसके अतिरिक्त अधोलिखित सीमा तक भी विशेष आकस्मिक छुट्टी मंजूर की जा सकती है।

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन नसबंदी आपरेशन (वैस्केक्टोमी अथवा सेल्फिजेक्टोमी) कराने के लिए। इस मामले में छुट्टी की सीमा छह कार्य दिवस होगी।

(ख) उस महिला कर्मचारी को जो अप्रासंगिक नसबंदी कराती है। इस मामले में छुट्टी की सीमा चौदह दिन होगी।

(iii) विशेष आकस्मिक छुट्टी आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर न तो इकट्ठी हो सकती है और न ही किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है। यह सार्वजनिक छुट्टियों के साथ मिलाकर दी जा सकती है।

कार्यार्थ छुट्टी

4. (i) कार्यार्थ छुट्टी निम्नलिखित स्थितियों में दी जा सकती है:

(क) विश्वविद्यालय को और से अथवा निबंधन स्वीकार करने से पहले विश्वविद्यालय के पूर्व अनुमोदन सम्मेलनों/कांग्रेसों/संगोष्ठियों/सेमिनारों और उसी प्रकार की अन्य गतिविधियों में भाग लेना;

(ख) इन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किए जाने वाले और कुलपति द्वारा मंजूर किए जाने वाले ऐसी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के निबंधन पर उन संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देना ;

(ग) किसी अन्य भारतीय विदेशी विश्वविद्यालय, संस्था अथवा संगठन में कार्य करना। विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त किए जाने पर अथवा विश्वविद्यालय के लिए किसी अन्य प्रकार का कार्य करना और

(घ) भारत सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों अथवा शैक्षणिक अथवा सार्वजनिक निकाय द्वारा नियुक्त प्रतिनिधिमंडल अथवा समिति के लिए कार्य करना।

(ii) विश्वविद्यालय के सामान्य शैक्षणिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए छुट्टी की अवधि ऐसी होनी चाहिए जिसे मंजूरीदाता प्राधिकारी प्रत्येक कार्य के लिए उसे आवश्यक समझता हो छुट्टी की अधिकतम अवधि एक वर्ष की हो।

(iii) छुट्टी पूरे वेतन पर मंजूर की जा सकती है परन्तु शर्त यह है कि यदि सामान्य खर्चों की बांछित राशि के अतिरिक्त कर्मचारी को कोई फेलोशिप अथवा मानदेय अथवा किसी अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता मिलती हो तो उसे विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार घटाए गए वेतन और भत्तों पर कार्यार्थ छुट्टी मंजूरी की जाए।

(iv) कार्यार्थ छुट्टी, अर्जित छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी असाधारण छुट्टी के साथ मिलाई जा सकती है।

अर्जित छुट्टी

5. (i) कर्मचारियों को स्वीकार्य अर्जित छुट्टी

(क) कर्मचारी के छुट्टी के खाते में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में पहली जनवरी और पहली जुलाई की पंद्रह-पंद्रह दिन की अर्जित छुट्टी दो किस्तों में जमा कर दी जाएगी।

(ख) किसी कर्मचारी की पिछली छमाही के अंत में जमा छुट्टी अगली छमाही में जमा कर दी जाएगी परन्तु इस प्रकार से जमा छुट्टी और छह महीने के दौरान जमा छुट्टियों की अधिकतम सीमा 240 दिन से अधिक नहीं होगी (30-6-1986 तक यह सीमा 180 दिन थी)

(ग) इस खंड के प्रायोजनों के लिए इतर विभाग सेवा में बिताई गई अवधि में कार्य माना जाएगा बशर्ते कि इस प्रकार की अवधि का छुट्टी वेतन के लिए अंशदान कर दिया गया हो।

5. (ii) किसी कर्मचारी को एक ही समय में मंजूर की जाने वाली अर्जित छुट्टी धारा 20 की उप धारा (12) और (13) की व्यवस्थाओं के अधीन 120 दिन से अधिक नहीं होगी। परंतु 120 दिन से अधिक अर्जित छुट्टी अनुभाग अधिकारी अथवा उसके समकक्ष अधिकारी से कम पद के अधिकारी के अतिरिक्त कर्मचारियों को उसी स्थिति में मंजूर की जाएगी जबकि पूरी छुट्टियां अथवा उसका कुछ भाग भारत के बाहर बांगलादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल बर्मा और पाकिस्तान में व्यतीत किया गया हो। परंतु इस उप-खंड के अंतर्गत यदि 120 दिन की अवधि से अधिक की अर्जित छुट्टी प्रदान की जाती है तो भारत में बिताई गई ऐसी छुट्टी की अवधि कुल मिला कर उपर्युक्त सीमाओं से अधिक नहीं होगी।

5. (iii) अर्जित छुट्टी की गणना

(क) किसी कर्मचारी के छुट्टी के खाते में जिस कैलेंडर वर्ष में वह नियुक्त होता है उस कैलेंडर वर्ष के आधे वर्ष में की जाने वाली प्रत्येक पूरे कैलेंडर महीने की सेवा के लिए 21/2 दिन की दर से छुट्टियां जमा हो जाएंगी।

(ख) (i) छह महीनों की अवधि में जिसमें कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाली हो अथवा सेवा से त्यागपत्र दे दे तो वह छह महीनों में जमा छुट्टी सेवा निवृत्ति अथवा त्यागपत्र की तारीख तक प्रत्येक पूरे कैलेंडर महीने के लिए 21/2 दिन की दर में से ही दी जाएगी।

(ii) जब कोई कर्मचारी सेवा से हटाया जाए अथवा बर्खास्त किया जाए अथवा सेवा काल में उसकी मृत्यु हो जाए तो जिस कैलेंडर महीने में उसे हटाया गया हो अथवा बर्खास्त किया गया हो अथवा नौकरी करते हुए उसकी मृत्यु हो गई हो उस से पहले कैलेंडर महीने के अंत तक प्रत्येक पूरे कैलेंडर महीने के लिए उसे 21/2 की दर से ही अर्जित छुट्टियों का लाभ मिलेगा।

(ग) यदि किसी कर्मचारी ने असाधारण छुट्टी ली है और अथवा अनुपस्थिति की कुछ अवधि को छह महीनों में अकार्य दिवस माना गया हो तो अगले छह महीनों के शुरू में उसके छुट्टी के खाते में दी जाने वाली छुट्टी का लाभ इस प्रकार की छुट्टी/अकार्य दिवसों की अवधि का 1/10 तक कम हो जाएगा परंतु इसकी अधिकतम सीमा 15 दिन होगी।

(ब) अर्जित छुट्टी का लाभ देते समय दिन के अंश का पूरा दिन कर दिया जाएगा।

अर्धवेतन छुट्टी

6. (i) प्रत्येक कर्मचारी के अर्धवेतन छुट्टी के खाते में अर्धवेतन छुट्टी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में दस-दस दिनों की दो किस्तों में क्रमशः पहली जनवरी और पहली जुलाई को जमा की जाएगी।

(ii) (ख) उस आधे वर्ष के लिए जिसमें सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त होने वाला हो या सेवा से त्यागपत्र दे दे तो छुट्टी सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र की तारीख तक प्रत्येक पूरे कैलेंडर वर्ष के लिए 5/3 दिन की दर से जमा की जाएगी।

(ग) यदि किसी कर्मचारी को हटाया जाए अथवा निलंबित किया जाए या सेवा में रहने हुए उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे कैलेंडर मास के, जिसमें उसे सेवा से हटाया जाए अथवा निलंबित किया जाए अथवा उसकी मृत्यु हो जाए ठीक

पूर्ववर्ती कैलेंडर मास के अंत तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर मास के लिए 5/3 दिन की दर से अर्धवेतन छुट्टी दी जाएगी।

(घ) जब अनुपस्थिति अथवा निलंबन की अवधि को किसी छमाही में अकार्य दिवस माना गया हो तो अगली छमाही के शुरू होने पर अर्धवेतन छुट्टी के खाते में जमा की जाने वाली छुट्टी में से अकार्य दिवस की अवधि का 1/8 वां हिस्से को कटौती की जाएगी परंतु यह कटौती 10 दिन से अधिक नहीं होगी।

(iii) इस नियम के अंतर्गत छुट्टी चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर अथवा निजी कार्य के लिए दी जा सकती है।

(iv) अर्धवेतन छुट्टी के खाते में छुट्टी जमा करते समय दिन के किसी अंश को पूरा दिन माना जाएगा।

टिप्पणी:—कर्मचारी 1-1-86 से पूर्व अवधि के लिए प्रत्येक पूरे बड़े की सेवा के लिए 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी का हकदार होगा।

परिवर्तित अवकाश :

7. स्थायी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाणपत्र पर परिवर्तित छुट्टी जो देय अर्ध वेतन छुट्टी की आवसी मात्रा से अधिक नहीं होगी, निम्न-लिखित शर्तों पर प्रदान की जाएगी :

(1) जब परिवर्तित छुट्टी प्रदान की जाएगी तो उससे दुगुनी छुट्टियां देय अर्ध वेतन छुट्टी में से घटा दी जाएगी।

(2) किसी भी कर्मचारी को इस अध्यादेश के अधीन कोई भी परिवर्तित छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि छुट्टी मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी को इस बात का विश्वास न हो कि कर्मचारी छुट्टी की समाप्ति पर काम पर लौट आएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी जिसे परिवर्तित छुट्टी प्रदान की गई हो, कार्य पर वापस आए बगैर सेवा से त्याग पत्र दे दे अथवा अवेछा पूर्वक सेवा निवृत्त हो जाए तो परिवर्तित छुट्टी को अर्धवेतन छुट्टी माना जाएगा और उससे परिवर्तित छुट्टी के छुट्टी वेतन और अर्ध वेतन छुट्टी के बीच का अंतर वसूल किया जाएगा।

(4) पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम 180 दिन तक की अर्ध वेतन छुट्टी (चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना) परिवर्तित कराई जा सकती है बशर्ते कि ऐसी छुट्टी के बारे में छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी यह प्रमाणित करे कि वह अध्ययन के अनुमत पाठ्यक्रम के लिए इस्तेमाल की है जो विश्वविद्यालय के हित में है।

टिप्पणी:—परिवर्तित छुट्टी कर्मचारी के अनुरोध पर उस स्थिति में भी प्रदान की जा सकती है जब उसके खाते में अर्जित छुट्टी शेष हो।

असाधारण अवकाश :

8. (i) स्थायी कर्मचारियों को असाधारण छुट्टी निम्नलिखित स्थितियों में प्रदान की जा सकती है—

(क) जब उसे अन्य प्रकार की कोई छुट्टी देय न हो, अथवा

(ख) जब अन्य प्रकार की छुट्टी देय हो परंतु कर्मचारी असाधारण छुट्टी प्रदान करने के लिए लिखित आवेदन करे।

परन्तु शर्त यह है कि निम्नलिखित (ii) से (iv) तक के उप खंडों के उपबंधों को छोड़कर जो शिक्षकों पर लागू होती हैं, किमी कर्मचारियों का विश्वविद्यालय से बाहर कोई पद अथवा फेलोशिप ग्रहण करने के लिए असाधारण छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी।

- (2) कुलपति संबंधित संस्था के अनुरोध पर और अध्यापक के आवेदन पर सरकार, किसी विश्वविद्यालय, किसी अनुसंधान संस्थान अथवा इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण संस्था के अधीन पद अथवा फेलोशिप ग्रहण करने के लिए असाधारण छुट्टी प्रदान कर सकते हैं यदि कुलपति के मत में इस प्रकार की छुट्टी विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हो। यह छुट्टी केवल उस अध्यापक को दी जा सकती है जो अपने पद पर स्थायी हो और उसने विश्वविद्यालय में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो। परन्तु आगे यह भी शर्त है कि ऐसी छुट्टी इस पर उप खंड और निम्नलिखित उप खंड (iii) के अंतर्गत स्वीकृत छुट्टी समाप्त होने के पश्चात् ही प्रदान की जाएगी।

ऐसी छुट्टी का आवेदन संबंधित विद्यापीठ के निदेशक के माध्यम से भेजा जाएगा तथा निदेशक विषय विशेष के अध्यापन कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए निदेशक अपनी सिफारिशें देगा।

किसी अध्यापक को मंजूर की गई छुट्टी की अवधि समाप्त होने पर इयूटी पर वापस न आने की स्थिति में तो उसकी सेवाएं उसे मंजूर की गई छुट्टी की अवधि के शुरू होने की तारीख से समाप्त की जा सकती हैं। उसे प्रयोजन के लिए मंजूर की गई छुट्टी (जिसमें उसी दौरान ली गई अन्य प्रकार की छुट्टियां शामिल हैं) के दौरान जो भी वेतन और भत्तों की रकम ली हो विश्वविद्यालय को लौटानी होगी।

- (3) कुलपति अपने निर्णय से किसी भी स्थायी अध्यापक को असाधारण अवकाश भी प्रदान कर सकते हैं जिसका किसी विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान अथवा इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण संस्था में अध्यापन या अनुसंधान कार्य के लिए चयन हो गया हो बशर्ते कि उसने विश्वविद्यालय में कम से कम दो वर्ष तक सेवा की हो और उसका आवेदन विश्वविद्यालय के माध्यम से भेजा और अंग्रेषित किया गया हो। ऐसे मामलों में छुट्टी अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि के लिए होगी। किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के होते हुए भी जो किसी अध्यापक को देय हो यदि वह विश्वविद्यालय से बाहर अध्यापक का पद ग्रहण करता है तो उस छुट्टी की पूरी अवधि बिना वेतन की होगी। इस प्रकार बितंई गई छुट्टी की अवधि की गणना वरिष्ठता के लिए की जाएगी। पेंशन अंशदायी भविष्य निधि लाभों के लिए इस अवधि की गणना तब तक नहीं की जाएगी जब तक पेंशन अंशदायी भविष्य निधि का अंश अध्यापक द्वारा अथवा विदेशी नियोक्ता द्वारा नहीं कर दिया जाता।

यदि अध्यापक मंजूर की गई असाधारण छुट्टी की अवधि के समाप्त होने पर विश्वविद्यालय में पुनः अपनी इयूटी पर न आए तो यह समझा जाएगा कि उसने विश्वविद्यालय में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है।

- (4) निम्नलिखित उप खंड (7) के उपबंधों के अधीन किसी अध्यापक को उपर्युक्त उप खंड (2) और (iii) के अंतर्गत मंजूर की गई कुल असाधारण छुट्टी उसकी सम्पूर्ण सेवा के दौरान पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (5) असाधारण छुट्टी सर्वेन 'बिना वेतन' के होगी। असाधारण छुट्टी के दौरान भत्तों के भुगतान पर संबंधित नियम लागू होंगे।

- (6) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर वेतन वृद्धि के लिए असाधारण छुट्टी की गणना नहीं की जाएगी।

(क) चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ली गई छुट्टी।

(ख) ऐसे मामलों में जिनमें कुलपति संतुष्ट हों कि छुट्टी उन कारणों से ली गई थी जिन पर कर्मचारी का कोई बर्तन नहीं था जैसे नागरिक अशांति अथवा जिम्हूनि उसे इयूटी पर आने या लौटने में असमर्थ कर दिया था प्राकृतिक विपदा बशर्ते कि कर्मचारी के खाते में कोई अन्य प्रकार की छुट्टी शेष न हो।

(ग) उच्च अध्ययन जारी रखने के लिए ली गई छुट्टी।

(घ) शैक्षिक पद अथवा फेलोशिप अथवा शोध सह शैक्षिक पद अथवा तकनीकी या शैक्षणिक महत्व के कार्य को स्वीकार करने के लिए मंजूर की जाने वाली छुट्टी।

- (7) असाधारण छुट्टी को आकस्मिक छुट्टी और विशेष छुट्टी आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर किसी अन्य छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता बशर्ते कि इयूटी से लगातार अनुपस्थित रहने की कुल अवधि किसी भी स्थिति में कुल पांच वर्ष से अधिक न हो।

- (8) प्राधिकारी जिसे छुट्टी प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है यदि चाहे तो बिना छुट्टी की अनुपस्थिति की अवधियों को पूर्व व्याप्ति सहित असाधारण छुट्टी में परिवर्तित कर सकता है।

अर्जनशोध्य छुट्टी (Leave not due)

- (1) अर्जनशोध्य छुट्टी, कुलपति के विवेक से किसी स्थायी कर्मचारी को उसके पूरी सेवा काल के दौरान 360 दिन की अवधि के लिए प्रदान की जा सकती है जो एक बार में 90 दिन से अधिक नहीं होगी और कुल मिलाकर 180 दिन की होगी जिसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। कर्मचारी द्वारा ऐसी छुट्टी बाद में अर्जित अर्ध वेतन छुट्टी में से काट ली जाएगी।

टिप्पणी:—जून, 1988 से अर्जनशोध्य छुट्टी केवल चिकित्सा आधार पर ही स्वीकार्य है।

- (2) अर्जनशोध्य छुट्टी तब तक नहीं प्रदान की जाएगी जब तक कुलपति संतुष्ट न हों कि ऐसी उचित संभावना है कि कर्मचारी छुट्टी की समाप्ति पर इयूटी पर वापस आ जाएगा और मंजूर की गई छुट्टी अर्जित कर लेगा।

- (3) यदि कोई कर्मचारी जिसे अर्जनशोध्य छुट्टी प्रदान की जाती है इयूटी पर आए बिना सेवा से त्याग पत्र दे दे अथवा स्वेच्छा-पूर्वक सेवानिवृत्त हो जाए तो अर्जनशोध्य छुट्टी रद्द की दी जाएगी और उसकी सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र उसी दिन से माना जाएगा जिस दिन से इस प्रकार की छुट्टी शुरू हुई थी और उससे छुट्टी वेतन वसूल कर लिया जाएगा। जब कोई कर्मचारी अर्जनशोध्य छुट्टी का लाभ प्राप्त करने के बाद इयूटी पर आ जाए लेकिन वह अपने छुट्टी के खाने में शेष अर्जित छुट्टी समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र दे तो उसे शेष अर्जित छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन वापस करना होगा। परन्तु सेवा निवृत्ति यदि उसके (i) अस्वस्थ होने के कारण पूरी सेवा के लिए अयोग्यता हो जाने पर दी गई हो अथवा उसकी मृत्यु हो गई हो, या (ii) यदि कर्मचारी को स्थायी तौर पर जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया हो तो उससे कोई छुट्टी वेतन वसूल नहीं किया जाएगा।

अध्यापनाथ छुट्टी

10. (क) अध्यापकों के लिए

- (i) विशेष अध्ययन अथवा अनुसंधान जारी रखने के लिए अथवा विश्वविद्यालय संगठन और शिक्षा पद्धतियों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिए अध्ययनार्थ छुट्टी स्थायी पूर्णकालिक प्रोफेसर रीडर को जिसकी लगातार सेवा कम से कम तीन वर्ष की हो, मंजूर की जाएगी बशर्ते कि आवेदक जिस अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा अनुसंधान पाठ्यक्रम को करने का इच्छुक हो उससे विश्वविद्यालय को लाभ होने की संभावना हो तो परंतु यदि प्रबंध बोर्ड चाहे तो किसी मामले में विशेष परिस्थितियों में तीन वर्ष की लगातार सेवा की शर्त से छूट दे सकता है।
- (ख) अध्ययनार्थ छुट्टी उस स्थायी पूर्णकालिक प्राध्यापक को मंजूर की जा सकती है जिसकी लगातार सेवा दो वर्ष से कम की नहीं है। विशेष अध्ययन या अनुसंधान करने के लिए जो विश्वविद्यालय संगठन में और शिक्षा पद्धतियों में उसके काम से सीधा जुड़ा हो और जिसमें कार्य की पूर्ण योजना दी गई हो।

स्पष्टीकरण :

सेवा अवधि को गणना करते समय उस अवधि को भी गिना जाए जिसमें कर्मचारी परिवीक्षा पर था बशर्ते कि -

- (क) कर्मचारी आवेदन करने की तारीख के समय अध्यापक हो; और
- (ख) उसका कोई सेवा-विच्छेद न हुआ हो।

- (ii) अध्ययनार्थ छुट्टी कुलपति द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर अध्ययनार्थ प्रदान की जाएगी। यह छुट्टी कुछ आपवादिक मामलों को छोड़कर जिनमें प्रबंध संतुष्ट हो कि इस प्रकार छुट्टी का बहुमा शैक्षणिक आधार पर अपरिहार्य है और विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक है, दो वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी।

अध्ययनार्थ छुट्टी की अवधि किसी भी हिसाब में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (iii) अध्ययनार्थ छुट्टी उस अध्यापक को मंजूर नहीं की जाएगी जिसकी अध्ययनार्थ छुट्टी की समाप्ति के बाद जिस तारीख को ड्यूटी पर वापस आने की संभावना हो उन तारीख से तीन वर्ष के अंदर सेवा-निवृत्त होने वाला हो।

- (iv) अध्ययनार्थ छुट्टी एक बार से अधिक भी मंजूर की जा सकती है बशर्ते कि अध्यापक को अध्ययन छुट्टी अथवा विश्राम छुट्टी की पहली अवधि पूरी होने पर ड्यूटी पर वापस आए हुए कम से कम पांच वर्ष का समय बीत चुका हो। बाद की अध्ययनार्थ छुट्टी की अवधि के लिए अध्यापक को पहली छुट्टी की अवधि के दौरान किए गए कार्य का उल्लेख करना होगा और प्रस्तावित अध्ययन छुट्टी की अवधि के दौरान किए जाने वाले कार्य का व्यौरा भी देना होगा।

- (v) किसी भी अध्यापक को जिसे अध्ययन छुट्टी मंजूर की गई है, प्रबंध बोर्ड की अनुमति के बगैर अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा अनुसंधान कार्यक्रम को बिल्कुल बदल देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अध्ययन पाठ्यक्रम मंजूर की गई अध्ययन छुट्टी के पहले ही पूरा हो जाए तो अध्यापक को अध्ययन पाठ्यक्रम की सम्पत्ति पर ड्यूटी पर वापस आना पड़ेगा यदि बची हुई छुट्टी की अवधि को साधारण छुट्टी के रूप में मान लेने की प्रबंध बोर्ड की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो।

- (vi) (क) निम्नलिखित उप-खंडों (ii) और (iii) के अधीन प्रोफेसर और रीडरों को प्रथम वर्ष में पूरे वेतन और दूसरे वर्ष में आधे वेतन पर अध्ययनार्थ छुट्टी मंजूर की जाएगी और उसके बाद

किसी प्रकार का वेतन स्वीकार नहीं होगा। जिन प्राध्यापकों को अध्ययन छुट्टी मंजूर की जाएगी वे अध्ययनार्थ छुट्टी के दौरान कुल परिलब्धियां प्राप्त करते रहने के पात्र होंगे।

- (ख) अध्यापक अध्ययनार्थ छुट्टी की अवधि के दौरान सामान्यतया मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूरक भत्ता लेने का हकदार नहीं होगा। परंतु कुलपति यदि चाहें तो किसी मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे भत्तों के आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से भुगतान की स्वीकृति दे सकते हैं।

- (vii) जिस अध्यापक को अध्ययन छुट्टी मंजूर की गई है उसे दी गई छालवृत्ति, फैंसोक्षिप अथवा किसी सहमति की राशि से वेतन और भत्तों के साथ मंजूर की गई अध्ययनार्थ छुट्टी में कोई बाधा नहीं पड़ेगी परंतु इस प्रकार प्राप्त की गई छालवृत्ति जिसके लिए अध्ययनार्थ छुट्टी मंजूर की जाए उसे वेतन और भत्तों का निष्प्रेरण करते समय शामिल किया जाएगा।

- (viii) यदि किसी अध्यापक को जिसे अध्ययन छुट्टी मंजूर की गई हो, अध्ययनार्थ छुट्टी की अवधि के दौरान अंशकालीन रोजगार के पारिश्रमिक प्राप्त करने और उसे अपने पास रखने की तो अनुमति होगी किन्तु उसे साधारणतया अध्ययन छुट्टी वेतन प्रदान नहीं किया जाएगा लेकिन उन मामलों में जहाँ अंशकालिक रोजगार के संबंध में प्राप्त की गई पारिश्रमिक की राशि बहुत बड़ी मानी जाए, प्रबंध बोर्ड प्रत्येक मामले में दिए जाने वाले अध्ययन छुट्टी का वेतन नियत कर सकता है।

टिप्पणी : जिस अध्यापक को अध्ययनार्थ छुट्टी मंजूर की गई है उसका यह कर्तव्य होगा कि यदि उसे अध्ययनार्थ छुट्टी के दौरान किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से किसी भी रूप में कोई विस्मय सद्गुण प्राप्त हुई तो उसके बारे में विश्वविद्यालय को तत्काल सूचित करे।

- (ix) अध्ययनार्थ छुट्टी, अर्जित छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी, असाधारण छुट्टी के साथ मिलाई जा सकती है बशर्ते कि छुट्टी पर जाने पर ड्यूटी से अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि पांच वर्ष से अधिक न हो और अध्यापक ने अपनी जमा अर्जित छुट्टी अध्ययनार्थ छुट्टी के शुरू होते ही ले ली हो।

- (x) जिन अध्यापकों को अध्ययनार्थ छुट्टी मंजूर की गई है उन्हें जब कभी उनकी आवश्यक वेतन वृद्धि (वृद्धियां) देय होगी/होंगी, मंजूर की जाएगी/जाएंगी। परंतु अध्ययनार्थ छुट्टी पर जो अध्यापक होंगे उनको देय परिलब्धियों की राशि उपर्युक्त उपखंडों (vii) और (viii) के उपबंधों के अधीन कम कर दी जाएगी।

- (xi) यदि अध्यापक अपनी अध्ययनार्थ छुट्टी के समाप्त होने पर विश्वविद्यालय में ड्यूटी पर वापस आ जाए और जिस अवधि के लिए उसने बांड भरा है उसकी अवधि तक सेवा कर ले तो अध्ययनार्थ छुट्टी को पेंशन/अंशदायी भविष्य निधि के लिए सेवा माना जाएगा।

- (xii) किसी अध्यापक को मंजूर की गई अध्ययनार्थ छुट्टी को, यदि वह उसे उसकी मंजूरी की तारीख के 12 महीने के अंदर न ले तो उसे मंजूर की गई अध्ययन छुट्टी रद्द समझी जाएगी। परंतु इस प्रकार अध्ययनार्थ छुट्टी के रद्द होने के बावजूद अध्यापक पुनः ऐसी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है।

- (xiii) अध्ययनार्थ छुट्टी का लाभ लेने वाले अध्यापक को यह वचनपत्र देना होगा कि वह अध्ययनार्थ छुट्टी की अवधि से दुगुनी अवधि के लिए अथवा तीन वर्ष की अवधि के लिए

कीमें में जो भी कम हो, तत्प्राप्त सेवा करता रहेगा। इस अवधि की गणना अध्ययनार्थ छुट्टी समाप्त होने के पश्चात् छुट्टी पर लौटने की तारीख से की जाएगी।

(xiv) कोई अध्यापक —

- (क) जो उसे मंजूर की गई अध्ययनार्थ छुट्टी की अवधि के अंदर अपनी पढ़ाई पूरी करने में असमर्थ हो अथवा
- (ख) जो अपनी अध्ययनार्थ छुट्टी की समाप्ति पर विश्वविद्यालय की सेवा पर पुनः आने में असमर्थ रहे अथवा
- (ग) जो विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर ले परन्तु पुनः कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् सेवा की निर्धारित अवधि पूरी किए बिना सेवा छोड़ दे अथवा
- (घ) जो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त अवधि में बर्खास्त अथवा सेवा मुक्त कर दिया जाए तो उसे अध्ययन पाठ्यक्रम के संबंध में वेतन छुट्टी, वेतन और भत्ते तथा उस पर हुए अन्य व्यय अथवा उसे अथवा उसके लिए दी गई राशि वापस करनी होगी :

परन्तु यदि किसी अध्यापक ने अध्ययन छुट्टी से लौटने पर बोर्ड के अंतर्गत विश्वविद्यालय की कम से कम आधी अवधि तक सेवा की है तो उसे उपर्युक्त परिकलित राशि की आधी राशि विश्वविद्यालय को वापस करनी होगी। यदि अध्यापक को वेतन और भत्तों के बगैर अध्ययनार्थ छुट्टी मंजूर की गई है तो उसे विश्वविद्यालय को अपने चार महीनों के वेतन और भत्तों के बराबर रकम और विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययन पाठ्यक्रम के दौरान किए गए खर्च का भुगतान करना होगा।

स्पष्टीकरण :

यदि कोई अध्यापक जो अध्ययनार्थ छुट्टी बढ़वाना चाहे और उसकी अध्ययनार्थ छुट्टी बढ़ाई जाए और वह पहले मंजूर की गई छुट्टी की समाप्ति पर अपनी सेवा पर पुनः न आए तो इस अध्यादेश के अंतर्गत वसूली के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वह अपनी छुट्टी की समाप्ति पर सेवा पर लौटा ही नहीं।

(क) प्रबंध बोर्ड उपर्युक्त के बावजूद आदेश कर सकता है कि इस अध्यादेश की कोई शर्त उस अध्यापक पर लागू नहीं होगी जिसे बांड के अंतर्गत निर्धारित सेवा-काल में चिकित्सा आधार पर सेवा निवृत्त होने की अनुमति दे दी गई है। यह भी शर्त है कि प्रबंध बोर्ड किसी अन्य आपवादिक मामले में कुछ अन्य कारणों के लिए इस अध्यादेश के अंतर्गत अध्यापक द्वारा वापस की जाने वाली राशि को छोड़ सकता है अथवा उसे कम कर सकता है।

(xv) अध्यापक छुट्टी स्वीकृति हो जाने के बाद छुट्टी पर जाने में पहले विश्वविद्यालय को एक बांड भर कर देगा जिससे वह स्वयं उपर्युक्त उपखंडों (xiii) और (xiv) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य होगा और वित्त अधिकारी की संतुष्टि के लिए उस राशि के लिए प्रचल संपत्ति की प्रतिभूति अथवा किसी बीमा कंपनी का निष्ठा बांड अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा मॉरटी देगा अथवा दो स्थायी अध्यापकों की जमानत दिलाएगा जो उपर्युक्त उपखंड (xiv) के अनुसार विश्वविद्यालय को राशि वापस करेगा।

(xvi) अध्यापक अपने अध्ययन की छमाही रिपोर्ट अपने पर्यवेक्षक अथवा संस्था के प्रमुख के माध्यम से कुल सचिव अथवा इस प्रयोजन के लिए किसी प्राधिकृत अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट इस प्रयोजन के लिए मनोनीत अधिकारी के पास अध्ययन छुट्टी की प्रत्येक छमाही की समाप्ति के एक महीने के अंदर मिल जानी चाहिए। यदि निर्दिष्ट समय के अंदर यह रिपोर्ट अधिकारी को प्राप्त न हो तो इस रिपोर्ट

के प्राप्त न होने पर छुट्टी डेटम का हस्तान्तरण स्थगित किया जा सकता है।

10. (ख) अध्यापकों से इनर कर्मचारियों के लिए अध्ययनार्थ छुट्टी मंजूर करने की शर्तें —

(i) विश्वविद्यालय की सेवा की अनिवार्यताओं को देखते हुए अध्ययनार्थ छुट्टी उस कर्मचारी को मंजूर की जा सकती है जो भारत अथवा भारत के बाहर कोई विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम करने के लिए जिसमें व्यावसायिक अथवा तकनीकी विषय में उच्चतर अध्ययन अथवा प्रशिक्षण विशेष शामिल हो जाना चाहे और जो उसके कार्य क्षेत्र में सीधा और निकट का संबंध रखता हो।

(ii) अध्ययनार्थ छुट्टी निम्न स्थितियों में भी मंजूर की जा सकती है :—

(1) उस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन-यात्रा के लिए जिसमें कर्मचारी नियमित शैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण-शैक्षणिक पाठ्यक्रम में भाग न ले सकता हो यदि यह प्रमाणित हो जाए कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन-यात्रा विश्वविद्यालय के हित की दृष्टि से निश्चित रूप से लाभकारी है और कर्मचारी के कार्य क्षेत्र से संबंधित है; और

(2) लोक प्रशामन के ढांचे या पृष्ठभूमि में संबंधित अध्ययन के प्रयोजन के लिए भी वशत कि ;

(क) बोर्ड ने अध्ययन विशेष अथवा अध्ययन यात्रा की मंजूरी दे दी हो और

(ख) अध्ययन के लिए की गई छुट्टियों के दौरान कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य की पूरी रिपोर्ट उसके वापस आने पर प्रस्तुत करना आवश्यक हो।

(3) पाठ्यक्रम का किसी कर्मचारी के कार्य से सीधा या निकट संबंध न हो परन्तु उससे कर्मचारी के रूप में उसके मस्तिक को उदार बनाने तथा उसकी योग्यता में सुधार और लोक सेवा की अन्य शाखाओं में नियुक्त कर्मचारियों के साथ और अधिक सहयोग करने योग्य बनाने की संभावना हो।

(iii) अध्ययनार्थ छुट्टी नव तक मंजूर नहीं की जाएगी यदि—

(1) कृलपति द्वारा यह प्रमाणित न किया जाए कि प्रस्तुत अध्ययन या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के हित की दृष्टि से लाभकर है ;

(2) वह शैक्षणिक या सहित्यिक विषय से इनर विषयों के अध्ययन के लिये न हो।

(iv) भारत के बाहर ऐसे विषयों के अध्ययन के लिये अध्ययनार्थ छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी जिनकी समुचित पुष्टि भारत में ही मौजूद है।

(v) उस कर्मचारी को अध्ययनार्थ छुट्टी नहीं दी जायेगी :—

(1) जिसने विश्वविद्यालय में पांच वर्ष से कम सेवा की हो,

(2) जो छुट्टी समाप्त होने पर वापस आने की तारीख से तीन वर्ष के अंदर सेवा निवृत्त होने वाला है या सेवा-निवृत्त हो सकता है।

(vi) जो कर्मचारी इतनी बार छुट्टी लेता है जिसके कारण उसके नियमित कार्य से उसका संपर्क छूट जाने या उसके छुट्टी पर रहने के कारण संबंध संबंधी कठिनाइयाँ उत्पन्न होने की संभावना होती हो उसे अध्ययनार्थ छुट्टी नहीं दी जाएगी।

(vii) किसी कर्मचारी को अध्ययनार्थ छुट्टी देने की अधिकतम सीमा इस प्रकार होगी—

- (क) एक बार में 12 महीने तक की, तथा
(ख) उनके संपूर्ण सेवाकाल में (अध्ययन या प्रशिक्षण के लिये किसी अन्य नियम के अन्तर्गत मंजूर की गई इसी प्रकार छुट्टी की मिलाकर कुल 24 महीने की।

(viii) अध्ययनार्थ छुट्टी के लिये आवेदन—

- (क) अध्ययनार्थ छुट्टी के विकास के लिये प्रत्येक आवेदन संबंध बोर्ड को समुचित माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
(ख) कर्मचारी अपने आवेदन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख करे कि वह कौन सा एक या अधिक पाठ्यक्रम लेने का इरादा रखता है और कौन सी परीक्षा वह देना चाहता है।

(2) यदि कर्मचारी के लिये अपने आवेदन में अध्ययन का पूरा विवरण देना संभव न हो या यदि भारत से बाहर जाने के बाद उसे अपने कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन करना पड़ता है जिसका अनुभवगत आस्त में किया जा चुका है तो उसे उसका पूरा विवरण शीघ्र कुलपति को प्रस्तुत करना होगा और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो जब तक इस संबंध में कुलपति से अनुमति प्राप्त न कर ले तब तक पाठ्यक्रम को आरंभ करने या इस संबंध में उसके द्वारा ऐसे किए गए खर्च का वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

(ix) अध्ययनार्थ छुट्टी की मंजूरी

- (1) (क) प्रत्येक कर्मचारी को जिम्मे अध्ययनार्थ छुट्टी या ऐसे पाठ्यक्रम के विस्तार की मंजूरी लेनी है उसे अध्ययनार्थ छुट्टी पर जाने से पहले या ऐसी बढ़ाई गई अध्ययनार्थ छुट्टी को आरंभ करने से पहले निर्धारित काम में एक बांड प्रस्तुत करना होगा।

- (ख) बांड पर दो जमानतियों से हस्ताक्षर कराए जाएंगे जो उसके समान पदधारी या उससे उच्चतर पदाधिकारी हों।

(2) कर्मचारी को पाठ्यक्रम पूरा करने पर पास की गई परीक्षा या विशेष पाठ्यक्रमों के प्रमाण पत्र जिनको उसने पूरा किया है, उनके आरंभ तथा पूरा होने की तारीख आदि का उल्लेख करते हुए कुलपति को प्रस्तुत करने होंगे साथ ही पाठ्यक्रम प्रभारी की यदि कोई अभ्युक्ति हो तो वह भी देनी होगी।

(x) अध्ययनार्थ छुट्टी तथा अन्य प्रकार की छुट्टी को मिलाने से रखा रखना।

- (1) अध्ययनार्थ छुट्टी कर्मचारी के छुट्टी रोज से नहीं काटी जाएगी।

(2) अध्ययनार्थ छुट्टी अन्य प्रकार की छुट्टियों के साथ मिलाई जा सकती है। परन्तु किसी भी स्थिति में असाधारण छुट्टी के अलावा यह छुट्टी अन्य छुट्टी के साथ मिलाकर कर्मचारी के नियमित कार्य से 28 महीने की कुल अनुपस्थिति से अधिक नहीं होगी।

(3) जिस कर्मचारी को अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाकर अध्ययनार्थ छुट्टी मंजूर की गई है, यदि वह अन्य प्रकार की छुट्टी के दौरान पाठ्यक्रम लेना या आरंभ करना चाहे और नियम में दी गई शर्तों को पूरा करता हो तो उसके लिये अध्ययन अर्थात् ले सकता है। परन्तु इस तरह की छुट्टी की अवधि और पाठ्यक्रम यदि एक ही समय में पड़ते हों तो इस प्रकार की छुट्टी अध्ययनार्थ छुट्टी नहीं मानी जायेगी।

(xi) पाठ्यक्रम के बाद की अध्ययनार्थ छुट्टी का विनियमन—यदि कर्मचारी को दी गई अध्ययनार्थ छुट्टी की अवधि से पहले ही पाठ्यक्रम पूरा हो जाये ऐसी स्थिति में कर्मचारी को अपने 1228 GI/90-7.

पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद अपने कार्य पर उपस्थित होना होगा। यद्यपि कि कर्मचारी ने शेष छुट्टी की अवधि असाधारण छुट्टी के रूप में मानने के लिये कुलपति से पहले ही मंजूरी प्राप्त न कर ली हो।

(xii) अध्ययनार्थ छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन

(1) भारत के बाहर अध्ययनार्थ छुट्टी के दौरान कर्मचारी को उतना ही छुट्टी वेतन मिलेगा जितना वेतन वह अध्ययनार्थ छुट्टी आरंभ करने के तुरन्त पहले विश्वविद्यालय में ले रहा था। इसके साथ ही उसे महंगाई भत्ते व मकान किराया भत्ते की अलावा अध्ययन अर्थात् भी मिलेगा जिनकी दरें और शर्तें भारत सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले अध्ययन भत्ते की दरों और शर्तों की ध्यान में रखते हुए कुलपति निश्चित करेंगे।

(2) (क) कर्मचारी को भारत में अध्ययनार्थ छुट्टी के दौरान उतना ही छुट्टी वेतन मिलेगा जितना वेतन वह अध्ययनार्थ छुट्टी आरंभ करने के तुरन्त पहले विश्वविद्यालय में ले रहा था। इसके अलावा उपखंड (xiii) प्रावधानों के अनुसार उसे महंगाई भत्ते और मकान किराया भत्ता दिया जायेगा।

(ख) उपर्युक्त खंड (क) के अन्तर्गत छुट्टी वेतन का पूरी दर पर भुगतान सभी किया जायेगा जब कर्मचारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति, वृत्तिका या अंशकालिक कार्य करके कोई पारिश्रमिक नहीं ले रहा है।

(ग) यदि कर्मचारी अध्ययनार्थ छुट्टी के दौरान किस प्रकार को छात्रवृत्ति वृत्तिका या अंशकालिक कार्य करके पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो उस राशि को इस उप खंड के अधीन मिलने वाले छुट्टी वेतन में से कम कर दिया जाएगा यद्यपि कि छुट्टी वेतन की राशि उस छुट्टी वेतन की राशि से कम न की जाए जो उस अध्ययन छुट्टी के दौरान मिलती।

(घ) भारत में पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययनार्थ छुट्टी के दौरान अध्ययन अर्थात् नहीं दिया जाएगा।

(xiii) अध्ययन भत्ते के अलावा स्वीकार्य भत्ते:

(1) अध्ययनार्थ छुट्टी के पहले 120 दिन के लिए कर्मचारी को मकान किराया भत्ता उस स्थान पर समय-समय पर स्वीकार्य दर से दिया जाएगा जिस स्थान से वह अध्ययनार्थ छुट्टी पर गया था। 120 दिन के बाद कर्मचारी को मकान किराया भत्ता इस शर्त पर दिया जाएगा जब समय-समय पर इस आशय का प्रमाण-पत्र देता रहे कि वह उसी मकान में लगातार रह रहा है और उसने उस पूरे मकान को या उसके किसी हिस्से को किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर नहीं दिया है।

(2) कर्मचारी को उपर्युक्त उपखंड (1) के अंतर्गत स्वीकृत अध्ययनार्थ छुट्टी के दौरान स्वीकार्य मकान किराया भत्ता दिया जाएगा और जहाँ स्वीकार्य है वहाँ महंगाई भत्ता तथा अध्ययन भत्ता भी दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा।

(xiv) अध्ययनार्थ छुट्टी के दौरान याता अर्थात् जिस कर्मचारी को अध्ययनार्थ छुट्टी मंजूर की गई है उसे संप्रसारणतः याता भत्ता नहीं दिया जाएगा। किन्तु श्रबन्ध बोर्ड आपकादिक परिस्थितियों में इस तरह के भत्ते की स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

(xv) अध्ययन के लिए मुक्त का व्यय—जिस कर्मचारी को अध्ययनार्थ छुट्टी की मंजूरी दी गई है वह साधारणतया अध्ययन शुरू की तारीख से देना किन्तु प्रबन्ध बोर्ड आपकादिक मामलों में इस तरह के व्ययों को मंजूरी दे सकता है।

परन्तु यदि कोई कर्मचारी किसी भी स्रोत से छात्रवृत्ति या वृत्तिका ले रहा है या जिसने छुट्टी वेतन के प्रतिरिक्त अंशकालिक कार्य से मिलने वाली वृत्तिका को ले या उसे रखने की मंजूरी ले रखी है तो उसको अध्ययन शुल्क पर होने वाला खर्च नहीं दिया जाएगा।

(xvi) अध्ययनार्थ छुट्टी के बाद त्यागपत्र या सेवा निवृत्ति या पाठ्यक्रम पूरा न करना।

(1) यदि कोई कर्मचारी अध्ययनार्थ छुट्टी की अवधि के बाद अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हुए बिना या अपने कार्य पर उपस्थित होने के बाद तीन वर्ष के अन्दर त्यागपत्र दे दे या सेवा निवृत्ति हो जाए या फिर सेवा से अलग हो जाए या पाठ्यक्रम पूरा न कर पाए और इस प्रकार वह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत न कर पाए तो उसे निम्नलिखित राशि वापस करनी होगी:—

छुट्टी वेतन, अध्ययन भत्ते, शुल्क के व्यय, यात्रा भत्ते और यदि विश्वविद्यालय ने उस पर कुछ अन्य खर्च किए हों तो वे उसी दर पर भय ब्याज के जो उस समय सरकारी ऋणों पर लागू की मांग की तारीख से उसके त्याग पत्र को मंजूर करने या सेवा निवृत्ति की अनुमति देने में पहले या उसके अन्यथा सेवा छोड़ने में पहले उससे मांगी गई राशि।

परन्तु उन कर्मचारियों के मामले को छोड़कर जो अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाए यह नियम उस कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जिसे अध्ययनार्थ छुट्टी से वापस आने के बाद स्वास्थ्य के आधार पर सेवा निवृत्ति की अनुमति दी गई हो।

(2) (क) जिस कर्मचारी ने अध्ययनार्थ छुट्टी ले ली है उसकी छुट्टी को अध्ययनार्थ छुट्टी के आरंभ होने की तारीख में छुट्टी के खाते में मौजूद नियमित छुट्टी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अध्ययनार्थ छुट्टी से भिन्नकर ली गई किसी भी प्रकार की नियमित छुट्टी को इस प्रयोजन के लिए समायोजित कर लिया जाएगा। यदि फिर भी अध्ययन छुट्टी की अवधि शेष रहती है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता तो उसे असाधारण छुट्टी माना जाएगा।

(ख) कर्मचारी की उपर्युक्त उपखंड (2) के अन्तर्गत वापस की जाने वाली राशि के प्रतिरिक्त यदि उसे स्वीकार्य छुट्टी वेतन की राशि से कुछ अधिक छुट्टी वेतन वास्तव में दे दिया गया है या वह अधिक राशि उसे अध्ययनार्थ छुट्टी के परिवर्तन के बाद वापस करनी होगी।

(3) प्रबन्ध बोर्ड इस नियम की व्यवस्थाओं के बावजूद यदि विश्वविद्यालय के हित की दृष्टि से या किसी मामले अथवा एक ही जैसे कई मामलों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक अथवा समीचीन समझे तो आदेश जारी करके संबंधित कर्मचारी या कर्मचारी वर्ग को वापस ली जाने वाली राशि से छूट दे सकता है या उसकी राशि को कम कर सकता है।

11. अध्यापकों के लिए विश्राम छुट्टी:—

(i) विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक स्थायी अध्यापकों को जो अपनी सेवा के तीन वर्ष पूरे कर चुके हैं अपनी योग्यता तथा विश्वविद्यालय के लिए अपनी उपादेयता में वृद्धि करने के लिए अध्ययन या अनुसंधान या शैक्षणिक कार्य करने के लिए विश्राम छुट्टी ली जा सकती है। यह छुट्टी उस अध्यापक को नहीं दी जाएगी जो विश्वविद्यालय से एक वर्ष के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाला है।

(ii) छुट्टी की अवधि अध्यापक द्वारा इससे पहले विश्राम छुट्टी से वापस आने के बाद विश्वविद्यालय में उसकी क्रमशः 3 वर्ष से कम या 6 वर्ष की वास्तविक कार्य अवधि के अनुसार 6 महीने या 12 महीने से अधिक नहीं होगी परन्तु यह शर्त भी है कि अध्यापक को विश्राम छुट्टी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके पिछली अध्ययनार्थ छुट्टी अन्य किसी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद वापस आने की तारीख से तीन वर्ष पुरे न हो चुके हों।

(iii) अध्यापक को उसकी विश्राम छुट्टी के दौरान उन्हीं दरों पर (बशर्त कि निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया हो) पूरा वेतन दिया जाएगा जो उसके विश्राम छुट्टी पर जाने के तुरन्त पहले की। परन्तु विश्वविद्यालय उसके त्याग पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति या ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेगा जिस पर अनिश्चित खर्च हो।

(iv) अध्यापक विश्राम छुट्टी के दौरान भारत या विदेश के किसी दूसरे संगठन में स्थायी नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा। फिर भी यदि किसी उच्च अध्ययन संस्था में स्थायी नियुक्ति से इनर अध्येता वृत्ति या अनुसंधान छात्रवृत्ति या मानदेय के साथ तदर्थ अध्यापन और अनुसंधान कार्य या किसी अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने की उम्मेद अनुमति दी जा सकती है बशर्त कि ऐसे मामलों में प्रबन्ध बोर्ड यदि चाहे तो घटाए गए वेतन और भत्तों पर विश्राम छुट्टी को मंजूरी दे सकता है।

(v) अध्यापक को विश्राम छुट्टी अवधि की में नियत तारीख से अधिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। उसकी छुट्टी समाप्त होने पर यदि वह विश्वविद्यालय में फिर से कार्य करता है तो पेंशन/अंसदानी विषय निधि के प्रयोजन के लिए उसकी छुट्टियों की अवधि सेवा काल के रूप में मानी जाएगी।

टिप्पणी : 1. विश्राम छुट्टी के दौरान जो भी कार्यक्रम हों उनका पूरा विवरण छुट्टी के आवेदन के साथ विश्वविद्यालय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना होगा।

2. अध्यापक को छुट्टी से वापस आने पर छुट्टी के दौरान किए गए अध्ययन अनुसंधान या अन्य कार्य की प्रकृति की रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।

प्रसूति छुट्टी

12. (i) ऐसी महिला कर्मचारी को जिसकी दो से कम बच्चे जीवित हैं छुट्टी के आरंभ होने की तारीख से 90 दिन की पूरे वेतन सहित प्रसूति छुट्टी मंजूर की जा सकती है।

(ii) ऐसी महिला कर्मचारी को (चाहे उसके बच्चों की संख्या कुछ भी हो जिसका गर्भलाय या गर्भपात हो गया है चिकित्सक के प्रमाण पत्र सहित आवेदन देने पर प्रसूति छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है बशर्त कि वह 6 मन्ताह में अधिक न हो।

(iii) प्रसूति छुट्टी अतिरिक्त छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी या असाधारण छुट्टी के साथ मिलाई जा सकती है परन्तु किसी भी मांगी गई छुट्टी के साथ प्रसूति छुट्टी के आवेदन के साथ चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न हो।

(iv) खंड 12(iii) के प्रावधानों के बावजूद कोई भी छुट्टी (जिसमें 60 दिन तक की परिवर्तित छुट्टी तथा प्रसूति छुट्टी के अन्तर्गत मांगी गई अधिकाधिक एक वर्ष की अर्जनशोध्य छुट्टी शामिल है) आवेदन करने पर बिना किसी चिकित्सा प्रमाण-पत्र के मंजूर की जा सकती है।

विशेष नियोग्यता छुट्टी

(क) जानबूझ कर पहुंचाई गई चोट के लिए विशेष नियोग्यता छुट्टी

13. (i) ऐसे किसी कर्मचारी को विशेष नियोग्यता छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है जो पदीय कार्य के निष्पादन या उसकी पदीय हैमियन के फलस्वरूप जान बूझकर पहुंचाई गई चोट के कारण नियोग्य हो गया हो।

(2) ऐसी छुट्टी उस स्थिति में मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि जिस घटना से नियोग्यता हुई है उस घटना की तारीख से तीन महीने के अन्दर वह जाहिर न हो गई हो और नियोग्य व्यक्ति ने उसकी तत्काल सूचना न दे दी हो।

परन्तु शर्त यह कि यदि ऐसी घटना की तीन महीने बाद नियोग्यता प्रकट हुई हो तो ऐसे मामलों में छुट्टी मंजूर करने के लिए सम्बन्ध अधिकारी यदि नियोग्यता के कारण से संतुष्ट हो जाए तो ऐसी छुट्टी मंजूर कर सकता है।

(iii) मंजूर की गई छुट्टी की अवधि प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई हो जो किसी भी स्थिति में 24 महीने से अधिक की नहीं होगी।

(iv) विशेष नियोगिता छुट्टी को अन्य किसी भी तरह की छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।

(v) विशेष नियोगिता छुट्टी एक बार से अधिक मंजूर की जा सकती है यदि नियोगिता बढ़ जाए या भविष्य में फिर उभर आए तो इस तरह की छुट्टी मंजूर की जा सकती है। परन्तु एक ही नियोगिता के कारण दी जाने वाली छुट्टी की अवधि 24 महीने से अधिक न होगी।

(vi) पेंशन के लिए सेवा के पश्चालन में विशेष नियोगिता छुट्टी को सेवाकाल माना जाएगा तथा इस अध्यादेश के उपखंड (vii) के खंड (ख) के प्रावधान के अधीन मंजूर की गई छुट्टी के अलावा उसे वह छुट्टी में से नहीं काटी जाएगी।

(vii) इस प्रकार की छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन कितने ही दिन की ऐसी छुट्टी के पहले 120 दिन के लिए जिसमें उपर्युक्त उपखंड (v) के अंतर्गत स्वीकृत छुट्टी भी शामिल है की बराबर अर्जित छुट्टी के दौरान मिलने वाला छुट्टी वेतन होगा; और

(क) इस तरह की छुट्टी की अवधि के लिए अर्ध वेतन के दौरान मिलने वाली छुट्टी वेतन के बराबर होगी। परन्तु शर्त यह कि यदि कर्मचारी चाहे तो उसे उपर्युक्त उपखंड (क) के अंतर्गत छुट्टी वेतन पहले 120 दिन की अवधि के लिए दिया जा सकता है और ऐसी स्थिति में उस छुट्टी की अवधि उसकी अर्ध वेतन छुट्टी में से काट दी जाएगी।

(ख) आकस्मिक बोट के विशेष नियोगिता छुट्टी

(viii) इस अध्यादेश के भाग (क) के प्रावधान उस कर्मचारी पर भी लागू होंगे जिसकी नियोगिता आकस्मिक रूप से लगी बोट के कारण हुई या उसके पदोप कार्य के निष्पादन या उसकी पदोप हैसियत के कारण या किसी विशेष कार्य के निष्पादन के फलस्वरूप लगी किसी बीमारी के कारण हुई जिसका यह प्रभाव हो कि उसके बार-बार बीमार पड़ने या बोट लगने का खतरा उम्र साधारण खतरे से भी बढ़ जाए जो उसके पक्ष के साथ जुड़ा हुआ हो।

(iv) ऐसे मामलों में विशेष नियोगिता छुट्टी की मंजूरी पर निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:—

(क) यदि नियोगिता किसी बीमारी के कारण हुई है तो उसे प्राधिकृत चिकित्सा अधिकार द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि नियोगिता उस विशेष कार्य के निष्पादन के सीधे परिणाम स्वरूप हुई है,

(ख) यदि कर्मचारी के सेवाकाल में ही इस तरह की नियोगिता हुई है तो छुट्टी मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी का यह मत होना चाहिए कि वह आपवादिक प्रकृति की है; तथा

(ग) जिस अनुपस्थिति की अवधि की प्राधिकृत चिकित्सा अधिकार द्वारा सिफारिश की गई है उसका कुछ भाग अध्यादेश के अधीन छुट्टी के अधीन आता हो और कुछ भाग पर अन्य प्रकार की छुट्टी के नियम लागू हों और अर्जित छुट्टी के लिए स्वीकार्य छुट्टी वेतन के बराबर छुट्टी वेतन पर मंजूर की गई विशेष नियोगिता छुट्टी की अवधि 120 दिन से अधिक न हो।

संगरोध छुट्टी

14. (i) यदि किसी कर्मचारी परिवार या घर में किसी को गंभीर रोग हो जाने के कारण उसका डूटो से अनुपस्थिति रहना आवश्यक हो जाए तो ऐसी छुट्टी संगरोध छुट्टी कहलाती है।

(ii) संगरोध छुट्टी चिकित्सा अधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर अधिक से अधिक 21 दिन की दी जा सकती है आपवादिक मामलों में छुट्टी की अवधि 30 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। यदि संगरोध कारण उमर सीमा से अधिक छुट्टी लेना आवश्यक हो तो इस तरह की छुट्टी को

साधारण छुट्टी माना जाएगा। संगरोध छुट्टी की अर्जित छुट्टी अर्ध वेतन छुट्टी या असाधारण छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।

(iii) किसी कर्मचारी के संगरोध छुट्टी पर रहने के कारण उसे अपने कार्य से अनुपस्थित नहीं माना जाएगा और उस वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

15. (ख) परिवीक्षाधीन कर्मचारी

किसी कर्मचारी को जिसकी नियुक्ति मूल रिक्त स्थान पर परिवीक्षा की निश्चित शर्तों पर परिवीक्षार्थी के रूप में की गई है उसे परिवीक्षा अवधि में उसी प्रकार छुट्टी मिलेगी जो उसे उस स्थिति में स्वीकार्य होती यदि वह परिवीक्षाधीन न होकर मूल पद पर नियुक्त किया जाता। यदि परिवीक्षार्थी की सेवाएं किसी कारणवश समाप्त करने का प्रस्ताव किया जाए तो उसको दी हुई कोई भी छुट्टी उस तारीख के जिसको उसका परिवीक्षा काल समाप्त होता है या उससे पहले की तारीख के जिसकी उसकी सेवाएं प्रबंध बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी के आदेश से अन्य किसी कारण से समाप्त कर दी गई हो, बाद तक नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति परिवीक्षार्थी के रूप में उसकी उपयुक्तता आने के लिए किसी ऐसे पद पर की जाए जो मूलतः रिक्त न हो तो उसे तब तक जब तक मूल रूप से उसकी पुष्टि नहीं आए छुट्टी के प्रयोजन अस्थायी कर्मचारी माना जाएगा।

यदि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय का स्थायी कर्मचारी है और उस उच्च पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त कर दिया जाए तो परिवीक्षा अवधि में उसे उन छुट्टी नियमों के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा जो स्थायी पद पर मिल रहा था।

16. (ग) सेवा निवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति

यदि कर्मचारी सेवा निवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्त हो तो इन अध्यादेशों के प्रावधान उस पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे उसने उस तारीख को पहली बार सेवा में प्रवेश किया हो। पुनर्नियुक्त पेशवरों को भी जिन्हें छुट्टी के मामलों में नवनिर्भूत माना जाता है निम्नांकित खंड 20 के उपखंड 12 के अंतर्गत सजात छुट्टी की स्वीकृति दी जा सकती है।

17. (घ) अस्थायी कर्मचारी

अस्थायी कर्मचारियों पर इन अध्यादेशों के भाग (क) के प्रावधान लागू होंगे परन्तु उन पर निम्नांकित शर्तें और अपवाद भी लागू होंगे:

(1) अर्जित छुट्टी

(क) अस्थायी कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी की तरह ही अर्जित छुट्टी का हकदार होगा।

(2) अर्ध वेतन छुट्टी

अस्थायी कर्मचारी को अर्ध-वेतन छुट्टी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी को यह विश्वास न हो जाए कि इस तरह की छुट्टी बितावे के बाद कर्मचारी पुनः अपने कार्य पर लौट आएगा।

(3) परिवर्तित छुट्टी—

अस्थायी कर्मचारी स्थायी कर्मचारी की तरह ही अर्ध वेतन छुट्टी के किसी भी हिस्से को परिवर्तित करने का हकदार होगा।

(4) असाधारण छुट्टी

अस्थायी कर्मचारियों मामलों में असाधारण छुट्टी को अर्जित किसी भी स्थिति में निम्नलिखित सीमा से अधिक नहीं होगा।

(क) एक बार में तीन सप्ताह

(ख) यदि कर्मचारी अपनी सेवा के लगातार तीन वर्ष पूरे कर चुका हो तथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी का आवेदन करे तो, छुट्टी की अवधि 6 महीने होगी।

(ग) यदि कर्मचारी का किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में तपेदिक, कैसर या कुष्ठ रोग का उपचार चल रहा हो तो छुट्टी की अवधि 18 महीने होगी।

(घ) (i) अध्ययन आरंभ करने के लिए 24 महीने की छुट्टी दी जा सकती जिसे प्रमाणित करना पड़ेगा कि यह अध्ययन विश्वविद्यालय के लाभ के लिए होगा। परन्तु शर्त यह है कि जिस तारीख से असाधारण छुट्टी शुरू हो उस तारीख को कर्मचारी ने अपनी सेवा के लगातार तीन वर्ष पूरे कर लिए हों। जिन मामलों में यह शर्त पूरी न की जा सके उनमें उतने ही दिनों की असाधारण छुट्टी अन्य किन्हीं प्रकार की देय तथा मांगी गई छुट्टी के क्रम में स्वीकृत की जा सकती है (यदि कर्मचारी ने ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर अपनी सेवा के लगातार तीन वर्ष पूरे कर लिए हों तो उपर्युक्त (क) के अंतर्गत 3 महीने की असाधारण छुट्टी को सम्मिलित करके।

(ii) यदि अस्थायी कर्मचारी असाधारण छुट्टी की अधिकतम अवधि के समाप्त होने पर जो उसे मंजूर की गई थी ड्यूटी पर वापस न आए या कोई कर्मचारी जिसे थोड़े दिनों की छुट्टी मंजूर की गई थी किसी ऐसी अवधि तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहे जो उसे दो गई असाधारण छुट्टी को मिलाकर उस सीमा से अधिक हो जाए जिस सीमा तक उसे वह छुट्टी उपर्युक्त (i) के अधीन दी जा सकती थी तो यदि प्रबंध बोर्ड मामले की आपवादिक परिस्थितियों को देखते हुए कोई अन्य निर्णय न ले यह माना जाएगा कि उसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है और वह फलतः विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं रहा है।

(ङ) यदि असाधारण छुट्टी दो बार ली गई हो और बीच में अन्य प्रकार की छुट्टी भी ली गई हो तो ऐसे मामलों में उपर्युक्त उपबन्ध (क) से (घ) तक के प्रावधानों के अनुसार एक ही बार में ली गई लगातार असाधारण छुट्टी माना जाएगा।

(5) अर्जन शोध छुट्टी, अध्ययनार्थ छुट्टी तथा विश्राम छुट्टी अस्थायी कर्मचारी अर्जनशोध छुट्टी, अध्ययनार्थ छुट्टी तथा विश्राम छुट्टी के हकदार नहीं होंगे।

टिप्पणी:—अस्थायी कर्मचारियों को तपेदिक, कुष्ठ रोग, कैसर या मानसिक रोग से पीड़ित होने पर उपचार के लिए अर्जनशोध छुट्टी की मंजूरी दी जा सकती है बशर्ते कि (i) इस तरह की छुट्टी के आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया हो (ii) कर्मचारी ने कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो (iii) जिस पद से कर्मचारी छुट्टी पर जा रहा है वह उसके छुट्टी से वापस आने तक बना रहे (iv) और इस तरह की छुट्टी कर्मचारी की कुल सेवा अवधि में 360 दिन से अधिक की न हो। इसके साथ ही स्थायी कर्मचारियों पर लागू होने वाली अन्य शर्तें भी लागू होंगी।

(6) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी

18. संविदा पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को संविदा की शर्तों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जाएगी।

(ब) अवैतनिक तथा तदर्थ कर्मचारी

19. (i) विश्वविद्यालय के अवैतनिक कर्मचारी, विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक अस्थायी कर्मचारियों पर लागू शर्तों के अनुसार ही छुट्टी के हकदार होंगे।

(ii) जिन कर्मचारियों की पूर्णतया तकनीकी कारणों से तदर्थ नियुक्ति की गई है उन्हें इन व्यापदेशों के अंतर्गत अस्थायी कर्मचारियों

को मिलने वाले लाभ दिए जाएंगे। तदर्थ नियुक्ति के अन्य सभी मामलों में तदर्थ कर्मचारियों को जो थोड़े समय के लिए नियुक्ति किए गए हैं पूर्ण की गई सेवा अवधि में 2-1/2 दिन प्रतिमास की दर से अर्जित छुट्टी दी जा सकती है।

(छ) सामान्य

(i) सामान्य शर्तें :

20. (i) छुट्टी—किस प्रकार अर्जित की जाती है: छुट्टी केवल कार्य द्वारा ही अर्जित की जाती है। विश्रामोत्तर सेवा में व्यर्तित की गई अवधि को ड्यूटी माना जाएगा बशर्ते कि इस प्रकार की अवधि के लिए छुट्टी वेतन के अंशदान का भुगतान किया गया हो।

(2) छुट्टी का अधिकार

छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है। छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम अधिकारी विश्वविद्यालय के हित में बिना किसी कारण बताए किसी भी तरह की छुट्टी को अस्वीकृत अवकाश रद्द कर सकता है।

(ख) ऐसे कर्मचारी की छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी जिसे सक्षम प्राधिकारी ने पदच्युत सेवा से निकालने या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय ले लिया है और न ही किसी ऐसे कर्मचारी की छुट्टी मंजूर की जाएगी जो निलम्बित हो।

(3) छुट्टी पर रहने की अधिकतम अवधि :

(क) किसी भी कर्मचारी को लगातार पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी।

(ख) यदि कोई कर्मचारी लगातार पांच वर्ष की छुट्टी से वापस ड्यूटी पर नहीं आए या जब कर्मचारी पांच वर्ष की छुट्टी समाप्त होने के बाद भी विश्रामोत्तर सेवा में या निलम्बित की छोड़ कर ऐसी अवधि तक जो उसे मंजूर की गई छुट्टी को मिलाकर पांच वर्ष से अधिक हो ड्यूटी पर लौटकर न आए तो यदि प्रबंध बोर्ड मामले की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए कोई अन्य निर्णय न ले तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवा से निकाल दिया जाएगा।

(4) छुट्टी के लिए आवेदन

छुट्टी के लिए आवेदन हमेशा पहले ही करना चाहिए और अपनी मामलों में तथा अन्य संतोषजनक कारणों को छोड़ कर छुट्टी पर जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से छुट्टी मंजूर करवा लेनी चाहिए।

टिप्पणी:—जब तक ऐसी छुट्टी की मंजूरी का आदेश जारी न हो जाए कर्मचारी को स्थान छोड़ कर नहीं जाना चाहिए।

(5) छुट्टी का आरंभ और समाप्ति साधारण छुट्टी उस तारीख से आरंभ होती है जिस दिन वे कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आता है और ड्यूटी समाप्त उस दिन होती है जब कर्मचारी ड्यूटी पर उपस्थित हो जाता है।

(ख) रविवाः तथा अन्य अधिकृत अवकाश के दिन जिनमें बकल्पिक छुट्टियां भी शामिल हैं छुट्टी मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से छुट्टी में पहले और बाद में जोड़े जा सकते हैं।

(6) छुट्टी समाप्त होने से पूर्व कार्य पर पुनः उपस्थित होना : जो कर्मचारी छुट्टी पर है वह यदि सक्षम प्राधिकारी से जिसने उसकी छुट्टी मंजूर की थी उससे अनुमति न ले ले छुट्टी की अवधि पूरी होने से पहले ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो सकता है।

(ख) सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी लेने वाले कर्मचारी को ऊपर (क) में दी गई किसी बात के बावजूद सेवानिवृत्ति की अनुमति देने और छुट्टी पर वापस आने के अनुरोध से केवल प्रबंध बोर्ड की सहमति से ही रोक जा सकता है।

(7) चिकित्सा के आधार पर छुट्टी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश किया जाए :

कर्मचारी को चिकित्सा के आधार पर छुट्टी के लिए आवेदन करने पर विश्वविद्यालय के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से या किसी चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है तो किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश करना होगा। परन्तु छुट्टी की मंजूरी देने वाले सक्षम प्राधिकारी आवेदक को चिकित्सा बोर्ड के सामने उपस्थित होने के लिए कह सकता है।

चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर छुट्टी या छुट्टी बढ़ाने की मंजूरी उस समय के बाद नहीं दी जा सकती जब से चिकित्सा अधिकारी या बोर्ड ने उसे स्थायी रूप से प्राण सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।

(8) चिकित्सा छुट्टी के आधार पर छुट्टी लेने के बाद कार्यभार ग्रहण करना :

कोई कर्मचारी जिसे (आकस्मिक छुट्टी से इतर छुट्टी) चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर छुट्टी की मंजूरी दी गई हो, स्वस्थता प्रमाण पत्र पेश किए बिना छुट्टी पर नहीं आ सकता है।

(9) छुट्टी के दौरान रोजगार

कोई कर्मचारी विश्वविद्यालय की लिखित स्वीकृति के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यापार या कारोबार, व्यक्तिगत ट्यूशन, कोई अन्य काम जिसमें वेतन या मानदेय मिलता है, नहीं कर सकता है पर यह निषेध किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा, लोक संघ आयोजन, शिक्षा बोर्ड या इसी प्रकार का समितियों/संस्थाओं या किसी साहित्यिक कार्य या प्रकाशन या रेडियो या विस्तार व्याख्यान कुलपति की अनुमति लेकर किए गए अन्य किसी शैक्षणिक कार्य पर लागू नहीं होता है।

ऐसे कर्मचारी के छुट्टी वेतन पर जिसे छुट्टी के दौरान रोजगार करने की स्वीकृति मिल गई है, प्रशासन बोर्ड द्वारा लगाए गए प्रतिबंध लागू होंगे।

(10) छुट्टी लिए बिना अनुपस्थिति या स्वीकृत छुट्टी से अधिक समय तक छुट्टी पर रहना :

यदि कोई कर्मचारी बिना छुट्टी लिए या स्वीकृत छुट्टी समाप्त होने के बाद भी अनुमति लिए बिना अनुपस्थित रहे तो उस अनुपस्थिति के दौरान उसे कोई छुट्टी भत्ता या वेतन नहीं मिलेगा। यदि छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी उसकी छुट्टी की अवधि और न बढ़ा तो वह अवधि बिना वेतन छुट्टी मानकर उसकी छुट्टी के खाते में से कम कर दी जाएगी। जानबूझकर छुट्टी से अनुपस्थित रहने को कदाचार माना जाएगा।

11. सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी :

कर्मचारी की छुट्टी मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी दस अर्जित छुट्टी सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के बराबर तथा दस भाग वेतन दे सकता है। छुट्टी लेने की अनुमति के 240 दिनों से अधिक न हो बशर्त कि ऐसी छुट्टी सेवानिवृत्ति की तारीख तक हो तथा उसमें सेवानिवृत्ति की तारीख भी शामिल हो।

टिप्पणी:—सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के रूप में स्वीकृत छुट्टी में असाधारण छुट्टी शामिल नहीं होगी।

(12) सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने की तारीख के बाद छुट्टी के बदले छुट्टी नकद भुगतान :

(1) किसी कर्मचारी को निम्नलिखित तारीखों के बाद छुट्टी की मंजूरी नहीं की जाएगी।

(i) सेवानिवृत्ति की तारीख

(ii) उसकी सेवा समाप्ति की अंतिम तारीख

(iii) तारीख जब वह कुलपति को नोटिस देकर सेवानिवृत्त हो रहा है या विश्वविद्यालय उसे नोटिस देकर या उसकी सेवा शर्तों के अनुसार ऐसे नोटिस के बदले वेतन और भत्ते देकर उसे सेवानिवृत्त कर रहा है।

(iv) सेवा से त्यागपत्र देने की तारीख :

(2) (क) कोई कर्मचारी यदि उसकी सेवा पर लागू होने वाली शर्तों के अनुसार निर्धारित अर्जित होने पर सेवानिवृत्त होता है तो छुट्टी मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी स्वयंसेव यह आदेश जारी करेगा कि सेवानिवृत्ति की तारीख तक यदि उसकी कोई अर्जित छुट्टी बकाया है तो छुट्टी वेतन के बराबर उसे नकद राशि दी जाए बशर्त कि यह अर्जित छुट्टी 240 दिन से अधिक की न हो।

(ख) खंड (क) के अनुसार नकद राशि की गणना निम्नलिखित रूप से की जाएगी और उसका भुगतान एक बार में एक मुश्त ही किया जाएगा। मकान किराया भत्ता या नगर भत्ता नहीं दिया जाएगा।

नकद राशि सेवानिवृत्ति की तारीख को देय वेतन + उस तारीख को देय महंगाई भत्ता $30 \times$ सेवानिवृत्ति की तारीख को देय अग्रपुस्त अर्जित छुट्टियों की संख्या जो 240 दिन से अधिक न हों।

(iii) छुट्टी की मंजूरी देने वाला अधिकारी सेवानिवृत्ति की आयु होने पर सेवानिवृत्त होने वाले किसी कर्मचारी को यदि निर्लब्ध होने या उसके विरुद्ध अनुशासनिक या आपराधिक कार्यवाही शेष के कारण यह सोचते हैं कि कार्यवाही संपन्न होने के बाद यह संभव है कि उससे कुछ पैसे वसूल कि जाएं तो ऐसी स्थिति में वह अर्जित छुट्टी के बराबर समस्त नकद राशि या उसका कुछ भाग रोके रख सकता है। कार्यवाही संपन्न हो जाने के बाद विश्वविद्यालय को दस घन इस प्रकार रोके गए धन से वसूल कर बाकी उसे वापस मिल सकता है।

(iv) (क) यदि लोक सेवा के हित में किसी कर्मचारी का सेवाकाल उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद बढ़ा दिया गया है तो उसे निम्नलिखित छुट्टी या नकद राशि दी जा सकती है :

(i) बढ़ाई गई अवधि के दौरान इस प्रकार की अवधि से संबंधित अर्जित छुट्टियां तथा जो अर्जित छुट्टियां उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक बाकी थी। खंड 5 में निर्धारित छुट्टियों के अनुसार यथास्थिति अधिकतम दर 120/240 दिन की हो सकती है।

(ii) बढ़ाई गई अवधि समाप्त होने के बाद खंड 20(12) के अनुसार दी गई अवधि के अनुसार नकद राशि (ii) सेवानिवृत्ति के समय बकाया अर्जित छुट्टियां तथा बढ़ाई गई अवधि के दौरान अर्जित छुट्टियां। इनमें से जो छुट्टियां बढ़ाई गई अवधि के दौरान ले ली गई हैं उन्हें इनमें से कम कर दिए जाने पर अधिकतम 240 दिन से अधिक न हों।

(ख) उपर्युक्त (क) के उपखंड (ii) के अंतर्गत देय नकद राशि की गणना खंड 20 (12) (ii) (ख) में दिए गए तरीके से की जाएगी।

(V) किसी भी कर्मचारी का जो सेवानिवृत्त होता है या जो खंड 20 (12) (i) (iii) में उल्लिखित तरीकों से सेवानिवृत्त किया जाता है, छुट्टी की मंजूरी देने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित छुट्टी जो 240 दिन से अधिक न हो तथा उसकी बकाया अर्ध वेतन छुट्टियों के बराबर नकद राशि की मंजूरी स्वयमेव दी जानी चाहिए। परन्तु शर्त यह है कि यह अवधि जिस तारीख को वह इस प्रकार सेवानिवृत्त हो रहा है या सेवानिवृत्त किया जाता है और सामान्य अवस्था में उसकी सेवा पर लागू होने वाली शर्तों के अधीन निर्धारित आयु तक पहुंचने के बाद सेवानिवृत्ति होने के बीच की अवधि से अधिक न हो। नकद राशि अर्जित छुट्टी और या अर्ध वेतन छुट्टी पर स्वीकार्य तथा उस छुट्टी पर स्वीकार्य कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या उसे सेवानिवृत्त करने की तारीख को लागू दर से मंहगाई भत्ते के जो उस पहले 240 दिन के छुट्टी वेतन पर देय है बराबर होगी। पेंशन और पेंशन के समकक्ष राशि या दूसरे सेवानिवृत्त लाभों आंग पेंशन पर तदर्थ महायुता/श्रेणीबद्ध महायुता अर्ध वेतन छुट्टी की अवधि के लिए दिए गए छुट्टी वेतन में से जिसके लिए नकद समकक्ष राशि देय है काट ली जाएगी। इस प्रकार परिकल्पित की गई राशि का एक बार एकमुश्त में ही सिपटान के तौर पर भुगतान कर दिया जाएगा। मकान किराया भत्ता या नगर भत्ता नहीं दिया जाएगा।

परन्तु यदि अर्ध वेतन छुट्टी के लिए पेंशन और दूसरे पेंशन लाभों से कम हो तो अर्ध वेतन छुट्टी के नकद समकक्ष राशि नहीं दी जाएगी।

(vi) (क) (i) यदि कर्मचारी की सेवाएं नोटिस द्वारा समाप्त कर दी जाएं या नोटिस के बजाय वेतन और भत्ता दे दिया जाए या उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उसे छुट्टी मंजूरी करने समकक्ष नकद राशि का जो 240 दिन के अधिकतम छुट्टी वेतन से अधिक न हो उसके परिवार को भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा इस प्रकार की समकक्ष नकद राशि में से मृत्यु तथा सेवानिवृत्त उपग्रहण की समकक्ष पेंशन के कारण कोई कटौती नहीं की जाएगी।

टिप्पणी :—इस नियम के अनुसार स्वीकार्य छुट्टी वेतन के समकक्ष नकद राशि के अतिरिक्त मृत कर्मचारी के परिवार को मंहगाई भत्ता भी मिलेगा जो इस संबंध में अलग से प्रादेश जारी करने पर ही दिया जाएगा।

(ii) सेवा के लिए अग्रिम होने की स्थिति में छुट्टी वेतन के समकक्ष नकद राशि की जाएगी :—

किसी कर्मचारी की जो निश्चित प्राधिकारी द्वारा या सेवा के लिए पूरी तरह से और स्थाई रूप से अग्रिम घोषित कर दिया गया है, छुट्टी की मंजूरी देने वाला सक्षम प्राधिकारी सेवा से अग्रिम होने से पहले की उसकी बकाया छुट्टियों के बराबर छुट्टी वेतन की समकक्ष नकद राशि स्वयमेव देगा बशर्ते कि छुट्टी की अवधि जिसके लिए उसे नकद राशि मिलेगी उससे आगे की तारीख तक नहीं है जिसमें सामान्य अवस्था में सेवा शर्तों के अनुसार सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित की गई आयु पर वह सेवानिवृत्त होता है। इस प्रकार अदा की गई नकद राशि खंड 20 (12) (5) के अंतर्गत परिकल्पित छुट्टी वेतन के बराबर होगी। अस्थायी या अर्धस्थायी कर्मचारी को सेवा से अग्रिम होने की तारीख को उसे देय अर्धवेतन छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन के समकक्ष नकद राशि की मंजूरी दी जाएगी।

टिप्पणी :—उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिन पर अग्रदायी भविष्य निधि नियम लागू होते हैं, विश्वविद्यालय की अग्रदायी निधि के अग्रदायी के लिए छुट्टी वेतन की समकक्ष नकद राशि में से कटौती नहीं की जाएगी।

वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिस तारीख को वह सेवानिवृत्त हो रहा है, उसकी बकाया अर्जित छुट्टी जो 240 दिन से अधिक न हो, के नकद समकक्ष राशि की मंजूरी स्वयमेव दी जा सकती है।

(ii) यदि कोई कर्मचारी पद त्याग करे या नौकरी छोड़ तो छुट्टी की मंजूरी देने वाला सक्षम प्राधिकारी सेवानिवृत्ति की तारीख तक उसकी बकाया अर्जित छुट्टी की राशि, जो 240 दिन से अधिक न हो, की नकद समकक्ष राशि की मंजूरी स्वयमेव दे सकता है।

(iii) कर्मचारी जिसकी पुनर्नियुक्ति सेवानिवृत्ति के बाद हुई है अपनी पुनर्नियुक्ति की समाप्ति के बाद छुट्टी की मंजूरी देने वाले सक्षम प्राधिकारी पुनर्नियुक्ति की समाप्ति की तारीख तक उसकी बकाया अर्जित छुट्टियों की जो 240 दिन से अधिक न हों, मंजूरी स्वयमेव दे सकता है। (इसमें वह समय भी शामिल है जिसके लिए नकद भुगतान की स्वीकृति सेवानिवृत्ति के समय दी गई थी।

(ख) उपर उल्लिखित उपखंड vi (क) के अंतर्गत देय नकद समकक्ष राशि की गणना 20 (12) (ii) (ख) के अनुसार की जाएगी और उपर्युक्त उपखंड vi (क) (iii) के अनुसार अभिकलन या नकद समकक्ष राशि के लिए पुनर्नियुक्ति की समाप्ति की तारीख को दिया जाने वाला वेतन वही होगा जो पुनर्नियुक्ति से पहले के पद के वेतन क्रम के अनुसार और पेंशन दूसरे सेवानिवृत्त लाभों और उस वेतन के अनुरूप मंहगाई भत्ते के समकक्ष पेंशन के समायोजन के पहले नियत किया गया था।

(13) उस कर्मचारी की देय छुट्टी जिसकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो जाए :—

(i) ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसकी मृत्यु कार्यकाल में ही हो जाए, छुट्टी वेतन के जो यदि वह जीवित रहता और अर्जित छुट्टी जाने पर उसे मृत्यु के तत्काल बाद की तारीख को स्वीकार्य होता

(14) कर्मचारी की मृत्यु इत्यादि होने पर छुट्टी वेतन के समकक्ष नकद राशि का भुगतान :

सेवाकाल में, सेवानिवृत्ति या सेवा की समाप्ति के बाद परन्तु उपर उल्लिखित उपखंड (12) और (13) के अंतर्गत दिए गए छुट्टी वेतन के समकक्ष नकद राशि पाने से पहले कर्मचारी की मृत्यु होने पर वह निम्नलिखित को देय होगी :—

(i) यदि मृत कर्मचारी पुरुष है तो (उसकी) विधवा को या यदि एक से अधिक विधवाएं हों तो उनमें सबसे बड़ी जीवित विधवा को या यदि मृत कर्मचारी महिला है तो उसके पति को।

टिप्पणी :—सबसे बड़ी होने का निर्धारण आयु के अनुसार न करके जीवित विधवा के विवाह की तारीख के अनुसार किया जाएगा।

(ii) विधवा या पति न होने की स्थिति में उसके सबसे बड़े जीवित बेटे या गोद लिए बेटे को;

(ii) यदि उपर दिए (i) और (ii) में से कोई न हो तो सबसे बड़ी जीवित अविवाहिता बेटी को;

(i) उपर उल्लिखित (i) से (iii) में से कोई न हो तो सबसे बड़ी जीवित विधवा बेटी को;

(v) उपर उल्लिखित (i) से (iv) में से कोई न हो तो पिता को,

(vi) उपर उल्लिखित (i) से (v) में से कोई न हो तो माता को

- (vii) ऊपर उल्लिखित (i) से (vi) में से कोई न हो तो सबसे बड़े जीवित भाई को वित्तकी प्राप्ति 18 वर्ष से कम हो;
- (viii) ऊपर उल्लिखित (i) (vii) में से कोई भी न हो तो सबसे बड़ी जीवित अविवाहिता बहन को, और
- (ix) ऊपर उल्लिखित कोई भी न हो तो सबसे बड़ी विधवा बहन को;

(15) एक प्रकार की छुट्टी को दूसरी में परिवर्तित करना—

(क) विश्वविद्यालय संबंधित कर्मचारी के अनुरोध पर प्रारम्भ में ली गई किसी प्रकार की छुट्टी (जिसमें असाधारण छुट्टी भी शामिल है) को किसी दूसरे प्रकार की छुट्टी में भूतलवो प्रभाव सहित परिवर्तित कर सकता है परन्तु ऐसे परिवर्तन का दावा कर्मचारी अपना अधिकार समझ कर नहीं कर सकता।

(ख) यदि एक प्रकार की छुट्टी दूसरे प्रकार में परिवर्तित की जाती है तो छुट्टी वेतन की राशि और स्वीकृत भत्तों की गणना फिर से की जाएगी और स्थास्थिति बकाया छुट्टी वेतन और भत्तों की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा या ज्यादा दी गई राशि वसूल कर ली जाएगी।

(16) छुट्टी के दौरान वेतन वृद्धि—यदि वेतन वृद्धि आकस्मिक छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी, कार्यावधि छुट्टी, अध्ययनार्थ छुट्टी या विश्राम छुट्टी के अलावा किसी अन्य छुट्टी के दौरान पड़ती है, तो वेतन वृद्धि की सामान्य तारीख पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस तारीख से उसकी वेतन वृद्धि दी जाएगी जब कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करेगा। यह बात उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां वेतन वृद्धि के लिए छुट्टी को नहीं गिना जाता।

(17) छुट्टी वर्ष—यदि इन अध्यादेशों के प्रयोजन के लिए अलग से उल्लेख न किया जाए तो वर्ष शब्द का तात्पर्य कैलेंडर के आरम्भिक सत्र से लेकर कैलेंडर सत्र के अंत तक के वर्ष से है।

(ii) छुट्टी की मंजूरी देने के लिए मसम प्राधिकारी

21. कुलपति को छुट्टी की स्वीकृति देने की शक्ति प्राप्त है और यदि वह चाहें तो विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति सौंप सकते हैं।

(iii) छुट्टी वेतन

(22) (1) कोई कर्मचारी जो आकस्मिक या विशेष आकस्मिक छुट्टी पर है उसे छुट्टी से अनुपस्थित नहीं माना जाता और उसके वेतन में कोई अवरोध नहीं होता। कार्यावधि छुट्टी अध्ययनार्थ छुट्टी और विश्राम छुट्टी के दौरान कर्मचारी की क्रमशः खंड 4, 10 और 11 के प्रावधानों के अनुसार वेतन मिलेगा।

(2) अर्जित छुट्टी ने वाले कर्मचारी का छुट्टी पर जाने से पहले मिलने वाले वेतन के बराबर वेतन मिलेगा।

(3) परिवर्तित छुट्टी लेने वाला कर्मचारी उपखंड 22 (2) के अनुसार स्वीकार्य छुट्टी वेतन का हकदार है।

(4) अर्ध वेतन छुट्टी या अर्ध राशि छुट्टी लेने वाला कर्मचारी, उपखंड 22 (2) में निर्दिष्ट राशि के अर्ध के बराबर छुट्टी वेतन पाने का हकदार है।

(5) असाधारण छुट्टी लेने वाला कर्मचारी किसी भी प्रकार के छुट्टी वेतन का हकदार नहीं होगा।

(6) विशेष नियमित छुट्टी लेने वाला कर्मचारी खंड 13 के अधीन स्वीकार्य छुट्टी वेतन का हकदार है।

(7) प्रसूति छुट्टी तथा संगरोध छुट्टी लेने वाला कर्मचारी उस अवधि का हकदार है जो छुट्टी पर जाने के समय उसे मिल रहा था

(8) छुट्टी के दौरान भंडाई, मकान किराया और नगर भत्तों के अनुपात पर इन भत्तों के अभाव से संबंधित स्थितियों के प्रावधान लागू होंगे।

(9) कोई कर्मचारी जिसे खंड 20 (12) के अधीन अनिवार्य मेवा निवृत्ति/सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने जैसी भी स्थिति हो, की तारीख के बाद तक छुट्टी की स्वीकृति दी गई है, इस प्रकार की छुट्टी के दौरान खंड 20 (12) (ख) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार स्वीकार्य छुट्टी वेतन पाने का हकदार होगा।

(10) कर्मचारी को पुनर्नियुक्ति के दौरान अर्जित छुट्टी की मंजूरी देने के मामले में छुट्टी वेतन उसे मिलने वाले वेतन के आधार पर दी जाएगी। जिससे पेंशन और पेंशन के समान दूसरे मेवा निवृत्ति लाभ शामिल नहीं होंगे।

(4) इन अध्यादेशों के अनुसार नियम बनाना

(23) कुलपति इन अध्यादेशों के अनुसार नियम बना सकते हैं तथा यह बातें सकते हैं कि इन मामलों में कौन-सी कार्य विधि अपनाई जाए—

(i) छुट्टी देने के लिए तथा छुट्टी अनुमति समाप्त होने से पहले काम पर लौटने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र बनाना—

(ii) छुट्टी पर जाने या छुट्टी से लौटने पर छुट्टी की मंजूरी देना तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश करना

(iii) छुट्टी वेतन का भुगतान

(iv) सेवा रिकार्ड रखना और

(v) छुट्टी खाते रखना।

(24) अध्यादेश—ये अध्यादेश इन पर लागू नहीं होंगे (क) वे लोग जिन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा या विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रावधानों के अनुसार विशेष प्रावधान किए गए हैं या (ख) एक सीमित समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर आने वाले लोग (ग) समेकित वेतन या दिहाड़ी पर नियुक्ति लोग (घ) कार्य प्रभाविता कर्मचारियों और (ङ) वे लोग जिसकी भुगतान आकस्मिक निधि से किया जाता है।

(25) संशोधन—जब तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व-विद्यालय के 1988 के अधिनियम से कोई प्रतिकूल बात न हो, 1972 के केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमों में किसी प्रकार के संशोधन का अर्थ इन अध्यादेशों के संबंध प्रावधानों का संशोधन माना जाएगा, या कोई आदेश या केन्द्रीय प्रकाश द्वारा जारी किए गए या किए जाने वाले प्रशासनिक अनुदेश इन अध्यादेशों के अंतर्गत आदेश या प्रशासनिक अनुदेश समझे जाएंगे। संशोधन आदेश उस तारीख से प्रभावी होंगे जिससे केन्द्रीय सरकार उन्हें लागू करती है। उपर्युक्त प्रावधान अध्यापकों की छुट्टी, छुट्टी और अध्यापकों की विश्राम छुट्टी पर लागू नहीं होंगे।

छट

26. यदि प्रबंध बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इन में से किसी विशेष मामले में किसी अध्यादेश से अनावश्यक कठिनाई हो रही है, तो कारणों का उल्लेख करते हुए प्रबंध बोर्ड उसे उस खंड की जरूरतों तथा अपवादों के अनुसार इस हद तक तथा उन स्थितियों में उनमें छूट दे सकता है जिन्हें वह उस मामले को न्यायोचित तरीकों से निपटाने में आवश्यक समझे।

अध्ययनार्थ छुट्टी मंजूर होने पर बकाया समय द्वारा निष्काटित किया जाने वाला बंधन।

सह करार जो आज—तारीख—19—

को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1988 (1985 का 50) के अधीन जो एक निगमित निकाय है जिसे आरी (एक पक्ष) विश्वविद्यालय कहा जाएगा के और

(i)	का निवासी (जिसे इस के आगे (इसका पता) बाध्यताधारी कहा जाएगा): और	इसके साथ स्वयं प्रमाणों के साथ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं साक्षी संख्या-1 हस्ताक्षर
(ii)	का निवासी और	(नाम : संख्या-2 हस्ताक्षर
(iii)	का निवासी	हस्ताक्षर
जिन्हें आगे (ii) और (iii) को सम्मिलित (तीसरे भाग का) प्रतिभू कहा जाएगा।		(नाम : अमानती संख्या -1
बाध्यकारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत है तथा बाध्यताधारी ने निम्नलिखित कारणों से अध्ययनार्थ छुट्टी के लिए आवेदन किया है।		साक्षी संख्या-1 हस्ताक्षर
और विश्वविद्यालय ने इस शर्त पर अध्ययनार्थ छुट्टी देना मंजूर किया है कि अध्ययन पूरा होने पर बाध्यताधारी फिर से विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेगा और विश्वविद्यालय में कम से कम वर्षों तक का' करेगा। बाध्यताधारी ने यह शर्त मंजूर कर ली है और प्रतिभू ने भी विश्वविद्यालय को आश्वस्त किया है कि बाध्यकारी अपना दायित्व निष्ठापूर्वक निभाएगा		(नाम : हस्ताक्षर
1. जैसा पहले कहा गया है बाध्यताधारी अध्ययन समाप्त करने के बाद विश्वविद्यालय में फिर से कार्य करने के लिए प्रतिशब्द है तथा विश्वविद्यालय में कम से कम वर्षों तक नौकरी करेगा।		अमानती संख्या-2
2. यदि बाध्यताधारी अध्ययनार्थ छुट्टी के दौरान अपना अध्ययन पूरा नहीं कर पाता या अध्ययनार्थ छुट्टी समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय का कार्यभार फिर से ग्रहण नहीं करता या कार्यभार ग्रहण करने के बाद सेवा करने के स्वीकृत किए गए समय के समाप्त होने से पहले किसी भी समय विश्वविद्यालय की सेवाओं से इस्तीफा देता है, उपर्युक्त समय के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा बरखास्त कि जाने या हटाए जाने पर बाध्यताधारी और प्रतिबाध्यताधारी द्वारा अध्ययनार्थ छुट्टी के दौरान विश्वविद्यालय से पेशगी प्राप्त किया गया धन निर्णीत हर्जाना और धन वापसी के रूप में विश्वविद्यालय को या वह जिसे भी कहे, वापस करेंगे। यदि बाध्यताधारी अध्ययनार्थ छुट्टी में वापस आने पर 18 महीने नौकरी करता है तब बाध्यता धारों और प्रतिभू को निर्णीत हर्जाने के रूप में आधा मूल्य ही देना पड़ेगा।		संख्या-2 हस्ताक्षर
3. बाध्यताधारी और प्रतिभू ऊपर लिखित धारा (2) के अनुसार उस राशि पर 6% प्रति वर्ष का दर से ब्याज भी देंगे।		(नाम : साक्षी संख्या-1 हस्ताक्षर
4. बाध्यताधारी और प्रतिभू दोनों का विश्वविद्यालय को रकम अदा करने का संयुक्त दायित्व हमेशा और विश्वविद्यालय उन सबसे या अलग-अलग किसी से भी इस देय राशि को वसूल करने में सक्षम होगा।		(नाम : संख्या-2 हस्ताक्षर
5. ऊपर लिखित एक लगातार चलने वाला प्रतिभूति है समय बढ़ाने की स्वीकृति मिलने के कारण या अन्य स्थान कार्य या विश्वविद्यालय की वृद्धि या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुग्रह या बाध्यताधारी या किसी प्रतिभू के प्रति विश्वविद्यालय द्वारा की गई रियायत के कारण कम या रद्द नहीं की जा सके। और विश्वविद्यालय इस देय राशि को उन सबने या उनमें से किसी एक से वसूल करने में सक्षम रहेगा।		(नाम : संख्या-2 हस्ताक्षर
6. विश्वविद्यालय समय-समय पर अपने स्वनिर्णय द्वारा, प्रतिभू से बिना पूछे बाध्यताधारी को अध्ययनार्थ छुट्टी बढ़ा सकता है तथा प्रतिभू हर प्रकार से अध्ययन छुट्टी के मूल तथा बढ़े हुए समय के लिए भी, इन रकमों को अदा करने के लिए जिम्मेदार होंगे।		(नाम : संख्या-2 हस्ताक्षर
7. यदि विश्वविद्यालय द्वारा भारत के बाहर भुगतान किया जाता है तो बाध्यताधारी और अमानतियों को अदायगी के समय चाहे सरकारी विनिमय दर के अनुसार उसकी समकक्ष राशि भारतीय मुद्रा में अदा करनी होगी।		(नाम : संख्या-2 हस्ताक्षर

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi, the 24th April, 1990

G.S.R. 310.—In exercise of the powers conferred on him under Section 26(2) of the IGNOU Act, 1985 (No. 50 of 1985), read with Statute 17(1) and Statute 18 in the Second Schedule of the Act ibid, the Vice-Chancellor makes the following Ordinance (Ordinance No. 2) for governing leave of all employees of the Indira Gandhi National Open University, including Teachers and other Academic Staff.

ORDINANCE GOVERNING LEAVE OF ALL EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY INCLUDING TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF

1. Short title and Extent of Application.—The ordinance as set out in Annexure 'A' may be called "Ordinance for regulating leave of all employees of the Indira Gandhi National Open University, including Teachers and other Academic Staff".

These Ordinances shall be deemed to have come into force on 20th September, 1985.

2. Interpretation.—If any question arises as to the interpretation of these Ordinances it shall be resolved by the Board of Management.

[No. AD(G)/Ord. 2(1) 89]
NARAYANAN, Registrar

ANNEXURE 'A'

ORDINANCE FOR

REGULATION LEAVE TO EMPLOYEES (INCLUDING TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF)

(A) PERMANENT EMPLOYEES

Kinds of leave admissible :

1. The following kinds of leave would be admissible to permanent employees—

- (i) Leave treated as duty—
Casual leave
Special Casual leave
Duty leave
- (ii) Leave earned by duty—
Earned leave
Half Pay leave
Commuted leave
- (iii) Leave not earned by duty—
Extraordinary leave
Leave not due
- (iv) Leave not debited to leave account—
(a) Leave for academic pursuits—
Study leave
Sabbatical leave
(b) Leave on grounds of health—
Maternity leave
Special disability leave
Quarantine leave

The Board of Management may, in exceptional cases, grant, for the reasons to be recorded, any other kind of leave, subject to such terms and conditions as it may deem fit to impose.

CASUAL LEAVE

- 2. (i) Casual leave is not earned by duty. Total casual leave granted to an employee shall not exceed twelve days in a calendar year.
- (ii) Casual leave cannot be combined with any other kind of leave except special casual leave. It may be combined with holidays including restricted holidays and Sundays. Holidays or Sundays falling within the period of casual leave shall not be counted as casual leave.

SPECIAL CASUAL LEAVE

- 3 (i) Special casual leave not exceeding ten days in a calendar year may be granted to an employee—
(a) to conduct examination of a University, Public Service Commission, Board of Examination or other similar bodies/institutes ;
(b) to inspect academic institutions attached to a Statutory Board etc ;
(c) to participate in a literary, scientific or educational conference, symposium or seminar or cultural or athletic activities conducted by Bodies recognised by the University Authorities ;
(d) to do such other work as may be approved by the Vice-Chancellor as academic work.

NOTE—In computing the ten days leave admissible, the days of actual journey, if any, to and from the places where such Conference/activity takes place will be excluded.

- (ii) In addition, special casual leave to the extent mentioned below may also be granted—
(a) to undergo sterilization operation (Vasectomy or Salpingectomy) under Family Planning Programme. Leave in this case will be restricted to six working days.
(b) to a female employee who undergoes non-puerperal sterilization. Leave in this case will be restricted to fourteen days.
(iii) Special casual leave cannot be accumulated nor can it be combined with any other kind of leave except casual leave. It may be granted in combination with holidays.

DUTY LEAVE

- 4. (i) Duty leave may be granted for—
(a) attending conferences/congresses/symposia/seminars and other activities of similar nature, on behalf of the University or where invitations are accepted with the prior approval of the University;
(b) delivering lectures in Institutions and Universities at the invitation of such Institutions or Universities received by this University and accepted by the Vice-Chancellor ;
(c) working in another Indian or foreign University, institution or organisation when so deputed by the University, or for performing any other duty for the University; and
(d) working on a delegation or Committee appointed by the Govt. of India, State Governments, UGC, Universities or any other academic or Public body.
(ii) The duration of leave should be such as may be considered necessary by the sanctioning authority on each occasion, taking into account the normal academic programmes of the University and subject to a maximum period of one year.
(iii) The Leave may be granted on full pay, Provided that if the employee receives a fellowship or honorarium or any other financial assistance beyond the amount needed for normal expenses, he will be sanctioned duty leave on reduced pay and allowances as per University regulations in this regard.
(iv) Duty leave may be combined with earned leave, half pay leave or extraordinary leave.

EARNED LEAVE

- 5 (i) Earned leave admissible to employees
(a) The leave account of the employee shall be credited with earned leave in advance in two instalments of fifteen days each on the first day of January and July of every calendar year.
(b) The leave at the credit of an employee at the close of the provision half year shall be carried forward to the next half year subject to the condition that the leave so carried forward plus the credit for the half year do not exceed maximum limit of 240 days (180 days upto 30-6-1986).
(c) A period spent in foreign service shall count as duty for the purposes of this clause if contribution towards leave salary is paid on account of such period.
(ii) Subject to the provisions of sub-clause (12) & (13) of clause 20, the maximum earned leave that may be sanctioned to an employee at a time shall not

exceed 120 days. Earned leave exceeding 120 days may, however, be sanctioned to employees other than employees below the rank of Section Officer or equivalent rank when the entire leave or a portion thereof is spent outside India, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Nepal, Burma and Pakistan.

Provided that where earned leave for a period exceeding 120 days is granted under this sub-clause the period of such leave spent in India shall not in the aggregate exceed the aforesaid limits.

5(iii) Calculation of earned leave

- (a) Earned leave shall be credited to the leave account of an employee at the rate of 2-1/2 days for each completed calendar month of service which he is likely to render in a half year of the calendar year in which he is appointed.
- (b) (i) The credit for the half year in which an employee is due to retire or resigns from service shall be afforded only at the rate of 2-1/2 days per completed calendar month upto the date of retirement or resignation.
- (ii) When an employee is removed or dismissed from service or dies while in service, credit of earned leave shall be allowed at the rate of 2-1/2 days per completed calendar month up to the end of the calendar month in which he is from service or dies in service.
- (c) If an employee has availed of extraordinary leave and/some period of absence has been treated as dies-non in a half year, the credit to be afforded to his leave account at the commencement of the next half year shall be reduced by 1/10th of the period of such leave and or dies-non subject to the maximum of 15 days.
- (d) While affording credit of earned leave fractions of a day shall be rounded off to the nearest day.

HALF PAY LEAVE

6. (i) The half pay leave account of every employee shall be credited with half pay leave in advance in two instalments of ten days each on the first day of January and July of every calendar year.
- (ii) (a) The leave shall be credited at the rate of 5/3 days of each completed calendar month of which the employee is likely to render in the half year of the calendar year in which he is appointed.
- (b) The credit for the half year in which the employee is due to retire or resign from the service shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar year upto the date of retirement or resignation.
- (c) In case of removal or dismissal from service or death while in service half pay leave shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar month upto the end of calendar month preceding the calendar month in which the employee is removed or dismissed from service or dies in service.
- (d) Where a period of absence or suspension has been treated as dies-non in a half year the credit to be afforded to half pay leave on account at the commencement of the next half year shall be reduced by 1/8th of the period of dies-non subject to a maximum of ten days.
- (iii) The leave under this rule may be granted on medical certificate or on private affairs.
- (iv) While affording the credit of half pay leave fraction of a day shall be rounded off to the nearest day.

NOTE—For the period prior to 1-1-86 the employee shall be entitled to half pay leave of 20 days in respect of each completed year of service.

COMMUTED LEAVE

7. Commuted leave not exceeding half the amount of half pay leave due may be granted on medical certificate to a permanent employee subject to the following conditions :

- (i) When commuted leave is granted, twice the amount of such leave shall be debited against the half pay leave due.
- (ii) No commuted leave shall be granted under this ordinance unless the authority competent to sanction leave has reason to believe that the employee will return to duty on its expiry.
- (iii) Where an employee who has been granted commuted leave resigns from service or at his request is permitted to retire voluntarily without returning to duty, the commuted leave shall be treated as half pay leave and the difference between the leave salary in respect of commuted leave and half pay leave shall be recovered :
- (iv) Half pay leave upto a maximum of 180 days may be allowed to be commuted during the entire service (without production of medical certificate) where such leave is utilised for an approved course of study certified to be in the University's interest by the leave sanctioning authority.

NOTE—Commuted leave may be granted at the request of the employee even when earned leave is due to him.

EXTRAORDINARY LEAVE

8. (i) A permanent employee may be granted extraordinary leave—

- (a) When no other leave is admissible; or
- (b) When other leave is admissible, the employee applies in writing for the grant of extraordinary leave. Provided, however, that save under the provisions of sub-clauses (ii) to (iv) below, which are applicable to Teachers no extraordinary leave shall be granted to an employee for holding an appointment or a fellowship outside the University.
- (ii) The Vice-Chancellor may grant on the request from the institution concerned and on application of the teacher, extraordinary leave to hold an appointment or a fellowship under a Government, a University, a Research Institute or other similar important institution, if in the opinion of the Vice-Chancellor, such leave does not prejudice the interests of the University. This leave can be allowed only to a teacher who has been confirmed in the post held by him and has served the University for a period of atleast two years. Provided further that such leave shall not be granted until after the expiry of leave sanctioned under this sub-clause and sub-clause (iii) below.

The application for such leave shall be sent through the Director of the School concerned and the latter shall give his recommendations taking into account the strength of teaching staff of the particular discipline.

In case of his future to return to duty immediately at then end of the period of leave sanctioned to him the services of a teacher shall be liable to be terminated from the date of commencement of the period of leave granted to him. He shall also refund to the University pay and allowances if any, received by him during the leave (including other kinds of leave taken in continuation) sanctioned to him for the purpose.

- (iii) The Vice-Chancellor may also grant, at his discretion, extraordinary leave to a permanent teacher who has been selected for a teaching or research assignment in a University, a Research Institute or other similar important institution provided he has served the University for a period of atleast two years and the application had been sent through and for-

warded by the University. The leave in such cases shall not exceed a maximum period of two years. Notwithstanding any other leave which may be due to a teacher, the entire period for which the teacher holds the appointment outside the University shall be without pay. The period so spent shall count for seniority. The period shall not count for pensionary/Contributory Provident Fund benefits unless the pensionary contributory provident fund contributions are paid by the teacher or the foreign employer.

If the teacher does not resume his duties in the University at the end of the period of extraordinary leave granted to him, he shall be treated as having resigned the post held by him in the University.

- (iv) Subject to the provisions of sub-clause (vii) below, the total amount of extraordinary leave granted to a teacher under sub-clauses (ii) and (iii) above shall not exceed five years during his entire service.
- (v) Extraordinary leave shall always be without pay. Payment of allowances during the period of extraordinary leave shall be governed by the relevant rules.
- (vi) Extraordinary leave shall not count for increment except in the following cases—
 - (a) Leave taken on medical certificate.
 - (b) Cases where the Vice-Chancellor is satisfied that the leave was taken due to causes beyond the control of the employee, such as inability to join or rejoin duty due to civil commotion or a natural calamity, provided the employee has no other kind of leave to his credit.
 - (c) Leave taken for prosecuting higher studies.
 - (d) Leave granted to accept a teaching post or fellowship or research-cum-teaching post or an assignment for technical, or academic work of importance.
- (vii) Extraordinary leave may be combined with any other leave except casual leave and special casual leave provided that the total period of continuous absence from duty shall in no case exceed five years in all.
- (viii) The authority empowered to grant leave may commute retrospectively periods of absence without leave into extraordinary leave.

LEAVE NOT DUE

9. (i) Leave not due may, at the discretion of the Vice-Chancellor be granted to a permanent employee for a period not exceeding 360 days during the entire service, out of which not more than 90 days at a time and 180 days in all may be otherwise than on medical certificate. Such leave shall be debited against the half pay leave earned by him subsequently.

NOTE : From June 1988, leave not due is admissible only on medical grounds.

- (ii) Leave not due shall not be granted unless the Vice-Chancellor is satisfied that as far as can reasonably be foreseen, the employee will return to duty on the expiry of the leave and earn the leave granted.
- (iii) An employee to whom leave not due is granted resigns from service or permitted to retire voluntarily without resuming duty, the leave not due shall be cancelled, his retirement or resignation taking effect from the date on which such leave had commenced and the leave salary recovered. Where an employee resumes duty after availing of leave not due, but resigns before the debit balance in his leave account is wiped out, he shall be liable to refund the leave salary to the extent of the debit balance of leave :
Provided no leave salary shall be recovered if the retirement is by reason of ill health, incapacitating the employee for full service or in the event of his death or (ii) if the employee is compulsorily retired permanently.

STUDY LEAVE

10.A FOR TEACHERS

- (i) (a) Study leave may be granted to a permanent whole-time Professor/Reader with not less than three years continuous service to pursue a special line of study or research or to make a special study of the various aspects of University Organisation and methods of education, if the University is likely to benefit by the course of study or programme of research which the applicant wishes to undertake:

Provided that the Board of Management may, in the special circumstances, of the case, waive the condition of three years service being continuous.

- (b) Study leave may be granted to a permanent whole-time Lecturer with not less than two years continuous service, to pursue a special line of study or research directly related to his work in the University Organisation and methods of education giving full plan of work.

Explanation :

In computing the length of service, the time during which a person was on probation may be reckoned provided—

- (a) the person is a teacher on the date of the application; and
- (b) there is no break in service.
- (ii) Study leave shall be granted on the recommendation of Committee constituted for the purpose by the Vice-Chancellor. The leave shall not be granted for more than two years save in very exceptional cases in which the Board of Management is satisfied that such extension is unavoidable on academic grounds and necessary in the interest of the University. The period of Study leave shall in no case exceed three years.
- (iii) Study leave shall not be granted to a teacher who is due to retire within three years of the date on which he is expected to return to duty after the expiry of study leave.
- (iv) Study leave may be granted more than once provided that not less than five years have elapsed after the teacher returned to duty on completion of earlier spell of Study Leave or Sabbatical Leave. For subsequent spell of Study Leave, the teacher shall indicate the work done during the period of earlier leave as also give details of work to be done during the proposed spell of Study Leave.
- (v) No teacher who has been granted Study Leave shall be permitted to alter substantially the course of study or the programme of research without the permission of the Board of Management. When the course of study falls short of the study leave sanctioned, the teacher shall resume duty on the conclusion of the course of study unless the previous approval of the Board of Management to treat the period of shortfall as ordinary leave has been obtained.
- (vi) (a) Subject to the provisions of sub-clause (vii) and (vii) below, Study Leave may be granted on full pay for the first year and on half pay for the second year and no pay shall be admissible thereafter to Professors and Readers. The Lecturers granted Study Leave would be entitled to continue to draw their total emoluments for the duration of the Study leave.
- (b) The teacher shall not ordinarily be entitled to house rent allowance or city compensatory allowance during the period of study leave. Provided that the Vice-Chancellor may, in view of the special circumstances of a case, sanction the payment of such allowances in part or in full.
- (vii) The amount of scholarship, fellowship or other financial assistance that a teacher granted study leave has

been awarded will not preclude his being granted study leave with pay and allowances but the scholarship etc., so received shall be taken into account in determining the pay and allowances on which the study leave may be granted.

- (viii) If a teacher, who is granted study leave is permitted to receive and retain any remuneration in respect of part-time employment during the period of study leave, he shall ordinarily not be granted any study leave salary, but in cases, where the amount of remuneration received in respect of part-time employment is not considered adequate, the Board of Management may determine the study leave salary payable in each case.

Note : It shall be the duty of the teacher granted study leave to communicate immediately to the University financial assistance in any form received by him during the course of study leave from any person of institution whatsoever.

- (ix) Subject to the maximum period of absence from duty on leave not exceeding five years, study leave may be combined with earned leave, half pay leave, extraordinary leave provided that the earned leave at the credit of the teacher shall be availed of at the commencement of the study leave.
- (x) The teachers granted study leave will also be sanctioned necessary increment (s) as and when due. However the amount of emoluments payable to the teachers on study leave shall be reduced subject to the provisions of sub-classes (vii) and (viii) above.
- (xi) Study leave shall count as service for pension/contributory provident fund provided the teacher rejoins the University on the expiry of his study leave and serves for the period for which Bond has been executed.
- (xii) Study leave granted to a teacher shall be deemed to be cancelled, in case it is not availed of within 12 months of its sanction. Provided that where study leave granted has been so cancelled the teacher may apply again for such leave.
- (xiii) A teacher availing of study leave shall undertake that he shall serve the University continuously for double the period of study leave or for a period of three years whichever is less, to be calculated from the date of resuming duty after expiry of the study leave.
- (xiv) A teacher—

- (a) who is unable to complete his studies within the period of study leave granted to him or
- (b) who fails to rejoin the service of the University on the expiry of his study leave, or
- (c) who rejoins the University but leaves the service without completing the prescribed period of service after rejoining the service, or
- (d) who within the said period is dismissed or removed from service by the University.

shall be liable to refund to the University the amount of leave salary and allowances and other expenses, incurred on the teacher or paid to him or on his behalf in connection with the course of study :

Provided that if a teacher has served the University for a period of not less than half the period of service under the Bond on return from study leave he shall refund to the University half of the amount calculated as above. In case the teacher has been granted study leave without pay and allowances, he shall be liable to pay the University an amount equivalent to his four months pay and allowances last drawn as well as other expenses incurred by the University during the course of study.

Explanation:

If a teacher, who asks for extension of study leave and is not granted the extension, does not rejoin on the expiry of the Leave originally sanctioned, he will be deemed to have failed to rejoin the service on the expiry of his leave for the purpose of recovery of the dues under this ordinance :

- (a) Notwithstanding the above, the Board of Management may order that nothing in this ordinance shall apply to a teacher who within the prescribed period of service under the bond is permitted to retire from service on medical grounds. Provided further that the Board of Management may, in any other exceptional case, waive or reduce, for reasons to be recorded, the amount refundable by a teacher under this ordinance.
- (av) After the leave has been sanctioned the teacher shall, before availing of the leave, execute a bond* in favour of the University binding himself for the fulfilment of the conditions laid down in sub-clauses (xiii) and (xiv) above and give security of immovable property to the satisfaction of the Finance Officer or a Fidelity Bond of an Insurance Company, or a Guarantee by a Scheduled Bank or furnish security of two permanent teachers for the amount which might become refundable to the University in accordance with sub-clause (xiv) above.

*Appendix 1

- (xvi) The teacher shall submit to the Registrar or any other Officer so authorised six monthly reports of progress in his studies from his Supervisor or the Head of the Institution. This report shall reach the Officer so designated within one month of the expiry of every six months of the study leave. If the report does not reach the Officer within the time specified, the payment of leave salary may be deferred till the receipt of such report.

10. B FOR EMPLOYEES OTHER THAN TEACHERS

Conditions for grant of Study leave:

- (i) Study leave may be granted to an employee with due regard to the exigencies of service of the University to enable him to undergo, in or out of India, a special course of study consisting of higher studies or specialised training in a professional or a technical subject having a direct and close connection with the sphere of his duty.
- (ii) Study leave may also be granted—
 - (1) for a course of training or study tour in which an employee may not attend a regular academic or semi-academic course if the course of training or the study tour is certified to be of definite advantage to the University from the point of view of its interest and is related to the sphere of duties of the employee; and
 - (2) for the purpose of studies connected with the framework or background of public administration subject to the conditions that
 - (a) the particular study or study tour should be approved by the Board of Management; and
 - (b) the employee should be required to submit, on his return, a full report on the work done by him while on study leave.
 - (3) for the studies which may not be closely or directly connected with the work of an employee, but which are capable of widening his mind in a manner likely to improve his abilities as an employee and to equip him better to collaborate with those employees employed in other branches of the public service.
- (iii) Study leave shall not be granted unless—
 - (1) it is certified by the Vice-Chancellor that the proposed course of study or training shall be of definite advantage from the point of view of the interests of the University ;
 - (2) it is for prosecution of studies in subjects other than academic or literary subject.

(iv) Study leave out of India shall not be granted for the prosecution of studies in subjects for which adequate facilities exist in India.

(v) Study leave shall not be granted to an employee—

- (i) who has rendered less than five years service under the University ;
- (ii) who is due to retire, or has the option to retire from the University service within three years of the date on which he is expected to return to duty after the expiry of the leave.

(vi) Study leave shall not be granted to an employee with such frequency as to remove him from contact with his regular work or to cause cadre difficulties owing to his absence on leave.

(vii) The maximum amount of study leave which may be granted to an employee shall be—

- (a) twelve months at any one-time, and
- (b) during his entire service, twenty-four months in all (inclusive of similar kind of leave for study or training granted under any other rule).

(viii) Applications for study leave :

- (1) (a) Every application for study leave shall be submitted through proper channel to the Board of Management.
- (b) The course or courses of study contemplated by the employee and any examination which he proposes to undergo shall be clearly specified in such application.
- (2) Where it is not possible for the employee to give full details in his application, or if, after leaving India, he is to make any change in the programme which has been approved in India, he shall submit the particulars as soon as possible to the Vice-Chancellor and shall not, unless prepared to do so at his own risk, commence the course of study or incur any expenses in connection therewith until he receives the approval of the Vice-Chancellor.

(ix) Sanction of Study Leave

- (1) (a) Every employee who has been granted study leave or extension of such study leave shall be required to execute a bond in the prescribed form before the study leave or extension of such study leave granted to him commences.
- (b) The bond shall be signed by two sureties who are holding posts of equal or higher status.
- (2) On completion of the course of study, the employee shall submit to the Vice-Chancellor the certificates of study undertaken, indicating the date of commencement and termination of the course with the remarks, if any, of the authority in charge of the course.
- (x) Accounting of Study leave and combination with leave of other kinds.
- (1) Study leave shall not be debited against the leave account of the employee.
- (2) Study leave may be combined with other kinds of leave, but in no case the grant of this leave in combination with leave, other than extra-ordinary leave, shall involve a total absence of more than twenty-eight months from the regular duties of the employee.
- (3) An employee granted study leave in combination with any other kind of leave may, if he so desires, undertake or commence a course of study during any other kind of leave and subject to the other conditions laid down in rule being satisfied, draw study allowance in respect thereof.

Provided that the period of such leave coinciding with the course of study shall not count as study leave.

(xi) Regulation of Study Leave extending beyond course of study

When the course of study falls short of study leave granted to an employee, he shall resume duty on the conclusion of the course of study, unless the previous sanction of the Vice-Chancellor has been obtained to treat the period of shortfall as ordinary leave.

(xii) Leave salary during study leave

(1) During study leave availed of outside India, an employee shall draw leave salary equal to the pay that the employee drew while on duty with the University immediately before proceeding on such leave and in addition the dearness allowance, house rent allowance besides study allowance will be admissible at such rates and on such conditions as may be decided by Vice-Chancellor taking into consideration the rates of study allowance and the conditions thereof prescribed by Government of India in respect of its employees.

(2) (a) During study leave availed of in India, an employee shall draw leave salary equal to the pay that the employee drew while on duty with the University immediately before proceeding on such leave and in addition the dearness allowance and house rent allowance as admissible in accordance with the provisions of sub-clause (xiii).

(b) Payment of leave salary at full rate under clause (a) above shall be subject to furnishing a certificate by the employee to the effect that he is not in receipt of any scholarship, stipend or remuneration in respect of any part-time employment.

(c) The amount, if any, received by an employee during the period of study leave as scholarship or stipend or remuneration in respect of any part-time employment shall be adjusted against the leave salary payable under this sub-rule subject to the condition that the leave salary shall not be leave salary payable under this sub-rule subject to leave salary during half pay leave.

(d) No study allowance shall be paid during study leave for courses of study in India.

(xiii) Admissibility of allowances in addition to study allowance

(1) For the first 120 days of the study leave, house rent allowance shall be paid at the rates admissible to the employee from time to time at the station from where he proceeded on study leave. The continuance of payment of house rent allowance beyond 120 days shall be subject to the production of a certificate to the effect that the employee continues to occupy the accommodation and has not sublet either in whole or in part from time to time.

(2) Except for house rent allowance as admissible under sub-clause (1) above and the dearness allowance and the study allowance, where admissible, no other allowance shall be paid to an employee in respect of the period of study leave granted to him.

(xiv) Travelling allowance during study leave

An employee to whom study leave has been granted shall not ordinarily be paid travelling allowance but the Board of Management may in exceptional circumstances sanction the payment of such allowance.

(xv) Cost of fees for study

An employee to whom study leave has been granted shall ordinarily be required to meet the cost of fees paid for the study but in exceptional cases, the Board of Management may sanction the grant of such fees :

Provided that in no case shall the cost of fees be paid to an employee who is receipt of scholarship or stipend from whatever source or who is permitted to receive or retain, in addition to his leave salary, any remuneration in respect of part-time employment.

(xvi) Resignation or retirement after study leave or non-completion of the course of study.

- (1) If an employee resigns or retires from service or otherwise quits service without returning to duty after a period of study leave or within a period of three years after such return to duty or fails to complete the course of study and is thus unable to furnish the certificates he shall be required to refund—

the actual amount of leave salary, study allowance, cost of fees, travelling and other expenses, if any, incurred by the University, together with interest thereon at rates for the time being in force on Government loans, from the date of demand, before his resignation is accepted or permission to retire is granted or his quitting service otherwise.

Provided that except in the case of employees who fail to complete the course of study nothing in this rule shall apply to an employee who, after return to duty from study leave, is permitted to retire from service on medical grounds.

- (2) (a) The study leave availed of by such employee shall be converted into regular leave standing at his credit on the date on which the study leave commenced, any regular leave taken in continuation of study leave being suitably adjusted for the purpose and the balance of the period of study leave, if any, which cannot be so converted treated as extraordinary leave.
- (b) In addition to the amount to be refunded by the employee under sub-clause (2) above he shall be required to refund any excess of leave salary actually drawn over the leave salary admissible on conversion of the study leave.
- (3) Notwithstanding anything contained in this rule, the Board of Management may, if it is necessary or expedient to do so, either in the interest of the University or having regard to the peculiar circumstances of the case or class of cases, by order waive or reduce the amount required to be refunded by the employee concerned or class of employees.

SABBATICAL LEAVE (FOR TEACHERS)

11. (i) Permanent whole-time teachers of the University who have completed three years of service may be granted sabbatical leave to undertake study or research or other academic pursuits solely for the object of increasing their proficiency and usefulness to the University. This leave shall not be granted to a teacher who has less than one year service in the University to retire.
- (ii) The duration of leave shall not exceed six or twelve months according as the teacher has actually worked in the University for not less than three or six years respectively since his return from the earlier spell of sabbatical leave. Provided further that sabbatical leave shall not be granted until after the expiry of three years from the date of the teacher's return from the previous study leave or any other kind of training programme.
- (iii) A teacher shall, during the period of sabbatical leave be paid full pay and allowances (subject to the prescribed conditions being fulfilled) at the rates applicable to him immediately prior to his proceeding on sabbatical leave. The University shall not however, fill up his post or make other alternative arrangements involving additional expenditure.
- (iv) A teacher on sabbatical leave shall not take up during the period of that leave, any regular appointment under another organisation in India or abroad. He may, however, be allowed to accept a fellowship or Research Scholarship or adhoc teaching and research assignment with honorarium or any other form of assistance, other than a regular employment in an institution of advanced studies provided that in such cases the Board of Management may, if it so desires, sanction sabbatical leave on reduced pay and allowances.

- (v) During the period of sabbatical leave the teacher shall be allowed to draw the increment on due date. The period of leave shall also count as service for purpose of pension/contributory provident fund provided the teacher rejoins the University on the expiry of his leave.

Note—1. The programme to be followed during sabbatical leave shall be submitted to the University for approval alongwith the application for point of leave.

2. On return from leave the teacher shall report to the University the nature of studies, research or other work undertaken during the period of leave.

MATERNITY LEAVE

12. (i) Maternity Leave on full pay may be granted to female employee with less than two surviving children for a period of 90 days from the date of its commencement.
- (ii) Maternity leave may also be granted to a female employee (irrespective of number of surviving children) in case of miscarriage, including abortion, subject to the condition that the leave applied for does not exceed six weeks and the application for leave is supported by a medical certificate.
- (iii) Maternity leave may be combined with earned leave, half pay leave or extraordinary leave but any leave applied for in continuation of maternity leave may be granted if the request is supported by a medical certificate.
- (iv) Notwithstanding the provision contained in clause 12 (iii) any leave (including commuted Leave for a period not exceeding sixty days and leave not due) upto a maximum of one year applied for in continuation of maternity leave) may be granted without production of medical certificate.

SPECIAL DISABILITY LEAVE

- (a) SPECIAL DISABILITY LEAVE FOR INJURY INTENTIONALLY INFLICTED

13. (i) Special disability Leave may be granted to an employee who is disabled by injury intentionally inflicted or caused in, or in consequence of the due performance of his official duties or in consequence of his official position.
- (ii) Such Leave shall not be granted unless the disability manifested in itself within three months of the occurrence to which it is attributed and the person disabled acted with due promptitude in bringing it to notice.

Provided that the authority competent to grant leave may, if it is satisfied, as to the cause of the disability, permit leave to be granted in cases where the disability manifested itself more than three months after the occurrence of its cause.

- (iii) The period of leave granted shall be such as is certified by an Authorised Medical Attendant and shall in no case exceed 24 months.
- (iv) Special disability leave may be combined with leave of any other kind.
- (v) Special disability leave may be granted more than once if the disability is aggravated or re-manifests in similar circumstances at a later date but not more than 24 months of such leave shall be granted in consequence of any one disability.
- (vi) Special disability leave shall be counted as duty in calculating service for pension and shall not, except the leave granted under the provision to clause (b) of sub-clause (vii) of this ordinance be debited against the leave account.
- (vii) Leave salary during such leave shall—
- (a) for the first 120 days of any period of such leave including a period of such leave granted under sub-clause (v) above be equal to leave salary while on earned leave ; and

- (b) for the remaining period of any such leave, be equal to leave salary during half pay leave.

Provided that a member of the staff, may at his option be allowed leave salary as in sub-clause (a) above for period not exceeding another 120 days, and in that event the period of such leave shall be debited to his half pay leave account.

(b) SPECIAL DISABILITY LEAVE FOR ACCIDENTAL INJURY

- (viii) The provisions in part (A) of this ordinance shall apply also to an employee who is disabled by injury accidentally incurred in, or in consequence of, the due performance of his official duties or in consequence of his official position, or by illness incurred in the performance of any particular duty which has the effect of increasing his liability to illness or injury beyond the ordinary risk attaching to the post which he holds.

- (ix) The grant of special disability leave in such cases shall be subject to the further conditions—

- (a) that the disability, if due to disease, must be certified by an Authorised Medical Attendant to be directly due to the performance of the particular duty ;

- (b) that, if the employee has contracted such disability during service, it must be, in the opinion of the authority competent to sanction leave, exceptional in character ; and

- (c) that the period of absence recommended by an authorised medical attendant may be covered in part by leave under the ordinance and in part by any other kind of leave, and that the amount of special disability leave granted on leave salary equal to that admissible on earned leave shall not exceed 120 days.

QUARANTINE LEAVE

14. (i) Quarantine leave is leave of absence from duty necessitated in consequence of the presence an infectious disease in the family or household of an employee.

- (ii) Quarantine leave may be granted on medical certificate for a period not exceeding 21 days. In exceptional cases this limit may be raised to thirty days. Any leave necessary for quarantine purposes in excess of this period shall be treated as ordinary leave. Quarantine leave may be combined with earned leave, half pay leave or extraordinary leave.

- (iii) An employee on quarantine leave is not treated as absent from duty and his pay is not affected.

(B) EMPLOYEES APPOINTED IN PROBATION

15. An employee appointed as a probationer against a substantive vacancy and with definite terms of probation shall during the period of probation be granted leave which would be admissible to him if he held his post substantively otherwise than on probation. If for any reason it is proposed to terminate the services of a probationer, any leave granted to him should not extend beyond the date on which the probationary period expires or any earlier date on which his services are otherwise terminated by the orders of the Board of Management or competent authority. On the other hand, an employee appointed 'on probation' to a post, not substantively vacant, to assess his suitability to the post, shall until he is substantively confirmed, be treated as a temporary employee for purposes of grant of leave. If a person in the permanent service of the University is appointed 'on probation' to a higher post he shall not, during probation, be deprived of the benefit of leave rules applicable to his permanent post.

(C) EMPLOYEES RE-EMPLOYED AFTER RETIREMENT

16. In the case of an employee re-employed after retirement the provisions of these ordinances shall apply as if he had entered service for the first time on the date of his re-employment. Re-employed pensioners who are treated as new entrants in the matter of leave may also be granted terminal leave under sub-clause 12 of the clause 20 below.

(D) TEMPORARY EMPLOYEES

17. Temporary employees shall be governed by the provisions of part (A) of these Ordinances subject to the following condition and exceptions ;

(1) Earned leave—

- (a) A temporary employee shall be entitled to earned leave as a permanent employee.

(2) Half Pay Leave—

No half pay leave may be granted to a temporary employee unless the authority competent to sanction leave has reason to believe that the employee will return to duty on the expiry of such leave.

(3) Commuted Leave—

Temporary employees shall be entitled to commute any portion of the half pay leave as a permanent employee.

(4) Extraordinary Leave—

In the case of a temporary employee the duration of extraordinary leave on any occasion shall not exceed the following limits—

- (a) Three months at a time ;

- (b) Six months in cases where the employee has completed three years continuous service and the leave application is supported by a medical certificate ;

- (c) Eighteen months where the employee is undergoing treatment in a recognised hospital for tuberculosis, cancer or leprosy ;

- (i) 24 months in cases where the leave is required for prosecuting studies, certified to be in the University interest, provided that the employee has completed three years, continuous service on the date of commencement of extraordinary leave. In cases where this condition is not satisfied, extraordinary leave to this extent may be sanctioned in continuation of any other kind of leave due and applied for (including three months extraordinary leave under (a) above, if the employee completes three years continuous service on the date of expiry of such leave).

- (ii) When a temporary employee fails to resume duty on the expiry of the maximum period of extraordinary leave granted to him or where a employee who is granted a lesser amount of leave remains absent from duty for any period which together with the extraordinary leave granted exceeds the limit upto which he could have been granted such leave under (i) above, he shall unless the Board of Management in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines, be deemed to have resigned his appointment and shall accordingly cease to be in the University employ.

- (c) Two spells of extraordinary leave if intervened by any other kind of leave shall be treated as one continuous spell of extraordinary leave for the purposes of sub-clause (a) to (d) above.

(5) Leave not due, study leave and sabbatical leave—

Temporary employees shall not be entitled for the grant of leave not due, study leave and sabbatical leave.

Note :—Leave not due may be granted to temporary employees who are suffering from T.B., Leprosy, Cancer or Mental illness provided (i) request for such leave is supported by a medical certificate (ii) the official has put in a minimum of one year of service (iii) the post from which the official proceeds on leave is likely to last till his return to duty and (iv) the leave should be limited to a period of 360 days during entire service. The other conditions are applicable to permanent employees would also apply.

(E) EMPLOYEES APPOINTED ON CONTRACT

18. Employees appointed on contract will be granted leave in accordance with the terms of the contract.

(F) HONORARY AND AD HOC EMPLOYEES

19. (i) Honorary employees of the University shall be entitled to leave on the same terms as are applicable to whole-time temporary employees of the University.

(ii) Employees, whose appointment is treated as ad hoc for purely technical reasons may be extended the benefits admissible to temporary employees under these ordinances. In all other cases of ad hoc appointments which are for brief periods the ad hoc employees may be allowed earned leave at the rate of 2½ days per month of completed service

(G) GENERAL

(i) General conditions :

20. (i) Leave—how earned :

Leave is earned by duty only. The period spent in foreign service counts as duty if contribution towards leave salary is paid for such period.

(2) Right to leave :

(a) Leave cannot be claimed as a matter of right. Leave of any kind may be refused or revoked by the competent authority empowered to grant it without assigning any reason, if that authority considers such action to be in the interest of the University.

(b) No leave shall be granted to an employee whom a competent authority has decided to dismiss, remove or compulsorily retire from service nor shall any leave be granted to an employee when he is under suspension.

(3) Maximum period of absence from duty on leave :

(a) No employee shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding five years.

(b) Where an employee does not resume duty after remaining on leave for a continuous period of five years or where an employee after the expiry of his leave remains absent from duty, otherwise than on foreign service or on account of suspension, for any period which together with the period of leave granted to him exceeds five years, he shall unless the Board of Management in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines, be removed from service after following the prescribed procedure.

(4) Application for leave :

Leave should always be applied for in advance and the sanction of the competent authority obtained before it is availed of except in cases of emergency and for satisfactory reasons.

Note.—An employee should not leave station till the order sanctioning leave has been issued.

(5) Commencement and termination of leave :

(a) Leave ordinarily begins from the date on which leave as such is actually availed of and ends on the day the employee resumes his duty.

(b) Sundays and other recognised holidays (including Restricted holidays) may be prefixed and/or suffixed to leave with the permission of the authority competent to sanction the leave.

(6) Rejoining of duty before the expiry of the leave :

(a) An employee on leave may not return to duty before the expiry of the period of leave granted to him unless he is permitted to do so by the authority which sanctioned him the leave.

(b) Notwithstanding anything contained in (a) above, an employee on leave preparatory to retirement shall be precluded from withdrawing his request for permission to retire and from returning to duty, save with the consent of the Board of Management.

(7) Leave on medical grounds to be supported by medical certificate :

An employee who applies for leave on medical grounds shall support his application with a medical certificate from an Authorised Medical Officer of the University or where no such Medical Officer has been appointed, from a Registered Medical Practitioner. The authority competent to sanction leave may, however, require the applicant to appear before a Medical Board.

Leave or extension of leave on medical certificate shall not be granted beyond the date on which an employee is pronounced by a Medical Officer or Board to be permanently incapacitated for further service.

8) Rejoining duty on return from leave on medical grounds :

No employee who has been granted leave (other than casual leave) on medical certificate shall be allowed to return to duty without producing a medical certificate of fitness.

9) Employment during leave :

An employee on leave shall not, without the written permission of the University, engage directly or indirectly in any trade or business whatsoever or in any private tuition or other work to which any emolument or honorarium is attached; but this prohibition shall not apply to work undertaken in connection with the examination of a University, Public Service Commission, Board of Education or similar Bodies/Institutions or to any literary work or publication or radio or extension lectures or with the permission of the Vice-Chancellor, to any other academic work.

The leave salary of an employee who is permitted to take up any employment during leave shall be subject to such restrictions as the Board of Management may impose.

10) Absence without leave or overstays of leave :

An employee who absents himself without leave or remains absent without leave after the expiry of the leave granted to him, shall be entitled to no leave allowance or salary for the period of such absence. Such period shall be debited against his leave account as leave without pay unless his leave is extended by the authority empowered to grant the leave. Wilful absence from duty may be treated as misconduct.

(11) Leave preparatory to retirement :

An employee may be permitted by the authority competent to grant leave to take leave preparatory to retirement to the extent of earned leave due not exceeding 240 days together with half pay leave due subject to the condition the such leave extends upto and includes the date of retirement.

Note.—The leave granted as leave preparatory to retirement shall not include extraordinary leave.

(12) Leave/cash payment in lieu of leave beyond the date of retirement or quitting of service :

(i) No leave shall be granted to an employee beyond (i) the date of retirement or (ii) the date of his final cessation of his duties or (iii) the date on which he retires by giving notice to the Vice-Chancellor or he is retired by University by giving him notice or pay and allowances in lieu of such notice in accordance with the terms and conditions of his service (iv) the date of his resignation from service

(ii) (a) Where an employee retires on attaining the normal age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service the authority competent to grant leave shall suo motu, issue an order granting cash equivalent to leave salary for earned leave, if any, at the credit of an employee on the date of his retirement subject to a maximum of 240 days.

(b) The cash equivalent under clause (a) shall be calculated as follows and shall be payable in one lump sum as a one-time settlement. No House Rent allowance of City Compensatory Allowance shall be payable :—

Pay admissible on the date of retirement plus dearness allowance admissible on that date.

Cash equivalent = $\frac{\text{Pay admissible on the date of retirement plus dearness allowance admissible on that date} \times 30}{\text{Number of days of unutilised earned leave at credit on the date of retirement subject to a maximum of 240 days}}$

30
Number of days of unutilised earned leave at credit on the date of retirement subject to a maximum of 240 days.

(i) The authority competent to grant leave may withhold whole or part of cash equivalent of earned leave in the case of an employee who retires from service on attaining the age of retirement while under suspension or while disciplinary or criminal proceedings are pending against him, if in the view of such authority there is a possibility of some money becoming recovering from him on conclusion of the proceedings, he will become eligible to the amount so withheld after adjustment of University dues, if any.

(iv) (a) Where the service of an employee has been extended, in the interest of public service beyond the date of his retirement he may be granted—

(i) during the period of extension, any earned leave due in respect of the period of such extension plus the earned leave which was at his credit on the date of his retirement subject to a maximum of 120 days/240 days, as the case may be, as prescribed in clause 5.

(ii) after expiry of the period of extension, cash equivalent in the manner provided in clause 20(12)(ii) in respect of earned leave at credit on the date of retirement, plus earned leave earned during the period of extension, reduced by the earned leave availed of during such period, subject to a maximum of 240 days.

(b) The cash equivalent payable under sub-clause (ii) of (a) above shall be calculated in the manner indicated in clause 20(12)(ii)(b).

(v) An employee who retires or is retired from service in the manner mentioned in clause 20(12)(i)(iii) may be granted, suo moto by the authority competent to grant leave, cash equivalent of the credit subject to a maximum of 240 days and also in respect of all the half pay leave at his credit provided this period does not exceed the period between the date on which he so retires or is retired from service and the date on which he would have retired in the normal course after attaining the age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service. The cash equivalent shall be equal to the leave salary as admissible for earned leave and/or equal to the leave salary as admissible for half pay leave plus dearness allowance admissible on that leave salary for the first 240 days at the rates in force on the date the employee so retires or is retired from ser-

vice. The pension and pension equivalent or other retirement benefits and ad hoc relief granted relief on pension shall be deducted from the leave salary paid for the period of half pay leave, if any, for which the cash equivalent is payable. The amount so calculated shall be paid in one lump sum as a one-time settlement. No House Rent Allowance or City compensatory Allowance shall be payable :

Provided that if leave salary for the half pay leave component falls short of pension and other pensionary benefits, cash equivalent of half pay leave shall not be granted.

(vi) (a) (i) Where the services of an employee are terminated by notice or by payment of pay and allowances in lieu of notice, or otherwise in accordance with the terms and conditions of his appointment, he may be granted, suo motu, by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date on which he ceases to be in service subject to a maximum of 240 days.

(ii) If an employee resigns or quits service, he may be granted, suo motu, by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date of cessation of service, to the extent of half of such leave at his credit subject to a maximum of 120 days.

(iii) An employee who is re-employed after retirement may, on termination of his re-employment, be granted, suo motu, by the authority competent to grant leave cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date of termination of re-employment subject to a maximum of 240 days (including the period for which encashment was allowed at the time of retirement).

(b) The cash equivalent payable under sub-clause vi(a) above shall be calculated in the manner indicated in clause 20(12)(ii)(b) and for the purpose of computation or cash equivalent under sub-clause vi(a) (iii) above the pay on the date of the termination of re-employment shall be the pay fixed in the scale of post of re-employment before adjustment of pension and pension equivalent of other retirement benefits, and the dearness allowance appropriate to that pay.

(13) Leave at the credit of employees who dies in harness—

(i) In case an employee dies in harness, the cash equivalent of the leave salary that the deceased employee would have got had he gone on earned leave, but for the death, due and admissible on the date immediately following the date of death subject to a maximum of leave salary for 240 days shall be paid to his family. Further such cash equivalent shall not be subject to reduction on account of pension equivalent of death-cum-retirement gratuity.

Note : 1—In addition to the cash equivalent of leave salary admissible under this rule, the family of the deceased employee shall also be entitled to payment of dearness allowance only as per orders issued in this behalf separately.

(ii) Cash equivalent of leave salary in case of invalidation from service—An employee who is declared by a medical authority to be completely and permanently incapacitated for further service may be granted, suo motu, by the authority competent to grant leave, cash equivalent of leave salary in respect of leave due and admissible, on the date of his invalidation from service, provided that the period of leave for which he is granted cash equivalent does not extend beyond the date on which he would have retired in the normal course after attaining the age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service. The cash equivalent thus payable shall be equal to the leave salary as calculated under clause 20(12)

(v) An employee not in permanent employee or quasi-permanent employee shall not however be granted cash equivalent of leave salary in respect of half pay leave standing at his credit on the date of his invalidation from service.

Note 2.—In the case of employees governed by the contributory provident fund rules no deduction need be made out of cash equivalent of leave salary on account of University contribution to C.P. Fund.

(14) Payment of cash equivalent of leave salary in the case of death etc. of an employee.—In the event of the death of an employee while in service or after retirement or after cessation of duties but before actual receipt of its cash equivalent of leave salary under sub-clause (12) and (13) above such amount shall be payable—

- (i) to the widow and if there are more widows than one, to the eldest surviving widow, if the deceased was a male employee, or to the husband, if the deceased was a female employee.

Note : The eldest surviving widow shall be determined with reference to the date of marriage and not with reference to their ages.

- (ii) failing a widow or husband, as the case may be to the eldest surviving son; or an adopted son.
- (iii) failing (i) and (ii) above, to the eldest surviving unmarried daughter;
- (iv) failing (i) to (iii) above to the eldest surviving widowed daughter;
- (v) failing (i) to (iv) above, to the father;
- (vi) failing (i) to (v) above, to the mother;
- (vii) failing (i) to (vi) above, to the eldest surviving brother below the age of eighteen years;
- (viii) failing (i) to (vii) above, to the eldest surviving unmarried sister; and
- (ix) failing the above, the eldest surviving widowed sister.

(15) Conversion of one kind of leave to another :

- (a) At the request of the employee concerned, the University may convert retrospectively any kind of leave including extraordinary leave into a leave of different kind which was admissible to him at the time the leave was originally taken; but he cannot claim such conversion as a matter of right.
- (b) If one kind of leave is converted into another, the amount of leave salary and the allowance admissible shall be recalculated and arrears of leave salary and allowances paid or the amount overdrawn recovered as the case may be.

(16) Increment during leave.—If increment of pay falls during any leave other than casual leave, special casual leave, duty leave, study leave or sabbatical leave, the effect of increase of pay will be given from the date the employee resumes duty without prejudice to the normal date of his increment, except in those cases where the leave does not count for increment.

(17) Leave year.—For the purpose of these Ordinances, unless otherwise specified the terms 'year' shall mean calendar year running from the commencement of the calendar session to the end of the calendar session.

(ii) Authorities Empowered to Sanction Leave

21. The Vice-Chancellor is empowered to sanction leave and if he so desires delegate such powers to another officer of the University.

(iii) Leave Salary

22 (1) An employee granted casual leave or special casual leave is not treated as absent from duty and his pay is not intermitted. During duty leave, study leave and sabbatical leave, a employee will draw pay under the provisions of clause 4, 10 and 11 respectively.

(2) An employee on earned leave is entitled to leave salary equivalent to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

(3) An employee on commuted leave is entitled to leave salary equal to the amount admissible under sub-clause 22(2).

(4) An employee on half pay leave or leave not due is entitled to leave salary equal to half the amount specified in sub-clause 22(2).

(5) An employee on extraordinary leave shall not be entitled to any leave salary.

(6) An employee on special Disability leave is entitled to leave salary as admissible under Clause 13.

(7) An employee on Maternity leave and Quarantine leave is entitled to draw pay as at the time of proceeding on leave.

(8) Payment of dearness, house rent and city compensatory allowances during leave shall be governed by the provisions of the rules regarding the payment of those allowances.

(9) An employee who is granted leave beyond the date of compulsory retirement/retirement or quitting of service as the case may be, as provided under Clause 20(12) shall be entitled during such leave salary as admissible under clause 20(12)(b).

(10) If the case of an employee who is granted leave earned by him during period of reemployment, the leave salary shall be based on the pay drawn by him exclusive of the pension and pension equivalent of other retirement benefits.

(iv) Making of rules under these Ordinances

23. The Vice-Chancellor may make rules under these ordinances prescribing the procedure to be followed in—

- (i) making application for leave and for permission to return to duty before the expiry of the leave;
- (ii) granting leave and submission of medical certificates while proceeding or returning from leave;
- (iii) the payment of leave salary;
- (iv) the maintenance of records of service; and
- (v) the maintenance of leave accounts.

24. Exceptions.—These ordinances shall not be applicable to (a) person in respect of whom special provisions have been made by or under the provisions of the Statutes of the University (b) persons on deputation for a limited duration (c) persons appointed on consolidated salary or daily wages (d) work charged staff and (e) persons paid from contingencies.

AMENDMENTS :

25. Unless there is anything repugnant in the Indira Gandhi National Open University Act, 1985, any amendment to the CCS (Leave) Rules, 1972, shall be deemed to be the amendments of the relevant provisions of these ordinances or any order or administrative instructions already issued to be issued by the Central Government shall be deemed to be the orders or administrative instructions under these ordinances, with effect from the date of such amendments/orders are brought into force by the Central Government. The above provisions will not apply to study leave for teachers and sabbatical leave for teachers.

Relaxation

26. When the Board of Management is satisfied that the operation of any of these ordinances cause undue hardship in any particular case, the Board of Management for reasons to be recorded, dispense with or relax the requirements of that clause, to such extent and subject to such exceptions and conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a most and equitable manner.

APPENDIX-I BOND TO BE EXECUTED BY THE TEACHERS WHEN GRANTED STUDY LEAVE

This agreement made on this day of 198 between the Indira Gandhi National Open University being a body corporate constituted under the Indira Gandhi National Open University Act, 1985 (No. 50 of 1985) (hereinafter called the University of the one part) and

(i) resident of (hereinafter called the Obliger of the second part):
and

(ii) resident of ; and

(iii) resident of (hereinafter called—(ii) and (iii)— jointly the sureties of the third part).

Whereas the Obliger is employed in the Indira Gandhi National Open University in the

And whereas the Obliger has applied for Study Leave for the following purpose:

And whereas the University has agreed to grant Study Leave on the condition that after the completion of studies, the Obliger will re-join the University and serve the University for a minimum period of years. The Obliger has agreed to this condition and the sureties have also assured the University that the Obliger will perform these obligations faithfully.

1. That the Obliger undertakes that after completion of studies as aforesaid shall re-join the University and shall serve under the University for a minimum period of years.

2. That in case the Obliger fails to complete studies within the period of Study Leave or fails to re-join the service of the University on the expiry of Study Leave or resigns from the service of the University at any time before the expiry of the agreed period of service after return to duty at the University being dismissed or removed from the service by the University within the period aforesaid the Obliger and the sureties shall forthwith pay to the University or as may be directed by the University a sum of Rs. a liquidated damages and refund the advance received by the Obliger from University 1; and shall pay all the expenses incurred by the University on the Obliger consequent on the grant of Study Leave, provided always that if the Obliger completes 18 months service after return from study leave, then the sureties and the Obliger shall be liable to pay only half the amount of the liquidated damages.

3. That the Obliger and the sureties shall pay interest at the rate of 6% per annum on the amount payable as per Clause 2 above.

4. That the liability of the Obliger and the sureties to pay the amount due to the University shall be joint and several and the University shall be competent to recover the amount due from all or either of them.

5. That hereinabove given is a continuing surety and shall not be impaired or discharged by reason of any time being granted or by any forbearance, act or omission of the University or any person authorised by it or any other indulgence or concession shown by the University to the Obliger or to anyone surety and the University shall be competent to recover the amount due from all or either of them.

6. That the University may at its discretion extend the Study Leave of the obliger from time to time without any reference to the sureties and the sureties shall remain liable in all respects for the amounts payable under these presents during the original period as well as during the extended period.

7. That if any amount is paid by the University outside India then the Obliger and the sureties shall be liable to pay the equivalent amount in Indian Currency according to the prevalent official rate of exchange at the time of payment.

In witness whereof the parties have set their hands hereto in presence of witness:

Witness No. 1

.....
Sig.

.....
(Name :

Sig.

.....
Obliger

Witness No. 2

Sig.

.....
(Name :

Witness No. 1

Sig.

.....
(Name :

)
Sig.

.....
Surety No. 1

Witness No. 2

Sig.

.....
(Name :

Witness No. 1

Sig.

.....
(Name :

)
Sig.

.....
Surety No. 2

Witness No. 2

Sig.

.....
(Name :

Witness No. 1

Sig.

.....
Officer of the University

.....
(Name :

Witness No. 2

Sig.

.....
(Name :

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1990

सा.का.नि. 311 :—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण में ज्येष्ठ निजी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सर्वेक्षण (ज्येष्ठ निजी सहायक) भर्ती नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उद्भावित अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता, वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सेवा में जोड़े हुए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ निजी सहायक	1* (1989) *कार्यभार के आभार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राज-पत्रित अनुसचिवीय	2000-60-2300 75-3200 रु०	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8			9			10
लागू नहीं होता।			लागू नहीं होता।			आशुलिपिक श्रेणी 2 की श्रेणी से प्रोन्नत अधिकारियों के लिये 2 वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जायेगा।

11

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।

12

प्रोन्नति:—1640-2900 रु. के वेतनमान में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 1 से जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसे अधिकारियों से जिन्होंने आशुलिपिक श्रेणी 1 और आशुलिपिक श्रेणी-2 (1400-2300/2600) की श्रेणी में कुल मिलाकर सात वर्ष नियमित सेवा की है और दोनों के न हो सकने पर 1400-2300/2600 रु. के वेतनमान में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-2 जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण:—

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सर्वश्रेष्ठ पद धारण किये हुए, या

(ii) जिन्होंने 1640-2900 रु. या समतुल्य वेतनमान में दो वर्ष नियमित सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने 1400—2300/2600 रु. या समतुल्य वेतनमान में 7 वर्ष नियमित सेवा की है; या

(ख) जिनकी आशुलिपिक (अंग्रेजी या हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति है (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति किये गये व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी प्रकार या किसी अन्य संगठन/विभाग में इन नियमों के अधीन इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काबज बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।

13

प्रोन्नति के लिये समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे।

- | | |
|--|----------|
| 1. उप महानिदेशक | —अध्यक्ष |
| 2. निदेशक (प्रशा. एवं वित्त) | —सदस्य |
| 3. निदेशक, उप सचिव (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) | —सदस्य |
| 4. निदेशक, भारतीय सर्वेक्षण (चक्रानुक्रम से) | —सदस्य |

14

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. एस. एम./01/025/88]

भार. डी. गुप्ता, डेस्क अधिकारी

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi, the 25th April, 1990

G.S.R. 311.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Senior Personnel Assistant in the Survey of India under the Department of Science & Technology, namely :—

1. Short title and commencement.—These rules may be called the Survey of India (Senior Personnel Assistant) Recruitment Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the

scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit and other, qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law

applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Personnel Assistant	1 (1989) (Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'B' Gazetted Ministerial	2000-60-2300-EB-75-3200	Non-Selection	Not applicable
Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	
7	8	9	10	11	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years for officers promoted from the grade of Stenographer Grade II.	By promotion failing which by transfer on deputation.	

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
12	13	14

Promotion :

From Stenographers Grade I in the scale of Rs. 1640-2900 with two years regular service in the grade, failing which from officers with combined regular service of seven years in the grade of Stenographer Grade I and Stenographer Grade II (1400-2300/2600) and failing both from Stenographer Grade II in the scale of Rs. 1400-2300/2600 with seven years regular service in the grade.

Transfer on deputation:—

Officers of the Central Government

(a) (i) holding analogous posts on regular basis

or

(ii) with two years regular service in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent;

or

(iii) with seven years regular service in the scale of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent; and

(b) possessing a speed of 100 words per minute in Stenography English or Hindi).

(The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another cadre post held immediately preceding appointment under these rules in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).

Group 'B' DPC for Promotion consisting of:—

1. Deputy Surveyor General—Chairman
2. Director (Admn. & Finance)—Member
3. Director/Deputy Secretary (Department of Science & Technology).—Member.
4. Director, Survey of India (By rotation).—Member.

Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

[No. SM/(01/025/88]
R.D GUPTA, Desk Officer

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन खंड)

नई दिल्ली, 8 मई, 1990

(व्यापार पोत)

सा.का.नि. 312.—केन्द्रीय सरकार, व्यापार पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 457 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं व्यापार पोत (चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र) नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यापार पोत (चलत उन्मोचन प्रमाण-पत्र) संशोधन नियम, 1990 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. व्यापार पोत (चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र) नियम, 1960 में,—
(क) नियम 3 का उपनियम (2) में निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जाएगा—

“और प्ररूप के लागत की ऐसी राशि जो महानिदेशक द्वारा निश्चित की जाए :

परन्तु यदि नियम 4 के अधीन प्ररूप नहीं दिया जाता है तो आवेदक को राशि वापिस कर दी जाएगी।”

(ख) नियम 12 के उपनियम (2) का लोप किया जा या तथा नियम 12 का उपनियम (1) नियम 12 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा; और

(ग) प्ररूप 1 में, 'शीर्ष नाविका को रूचना' के अधीन त्रम संख्यांक 3 में, शब्द और अंक "4 रु. का संदाय करने पर" का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. एच- 11021/3/90-एम टी]

राम सनेही, अवर सचिव,

टिप्पण : मूल नियम तत्कालीन परिवहन और संचार मंत्रालय के परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचना सा.का.नि. सं. 1557 तारीख 16 दिसम्बर, 1960 द्वारा प्रकाशित किये गए थे जिनका पश्चात्तवर्ती संशोधन सा. का. नि. सं. 528 तारीख 30 मार्च, 1978 द्वारा किया गया।

**MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(Shipping Wing)**

New Delhi, the 8th May, 1990
(Merchant Shipping)

G.S.R. 312.—In exercise of the powers conferred by section 457 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules, 1960, namely :—

(1) Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Amendment Rules, 1990.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2) In the Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules, 1960,

(a) in sub-rule (2) of rule 3, the words "and such amount being the cost of the form as may be fixed by the Director General :

Provided that the amount shall be refunded to the applicant if a form is not issued to him under rule 4" shall be omitted :

(b) sub-rule (2) of rule 12 shall be omitted and sub-rule (1) of rule 12 shall be renumbered as rule 12; and

(c) in form I, under the heading, Notice to Seamen in serial number 3, the words and figure "on payment of Rs. 4" shall be omitted.

[F. No. H-11021/3/90-MT]
RAM SANEHI, Under Secy.

Note.—The Principle rules were published vide GSR No. 1557 dated the 16th December, 1960 under the notification of then Ministry of Transport and Communication, Department of Transport and were subsequently amended by G.S.R. 528 dated the 30th March, 1978.